आरआईएस
वार्षिक रिपोर्ट
2015–16

अंतर्राष्टीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान
एवं सूचना प्रणाली

विषय वस्तु

अध्यक्ष का संदेश		*iii*
महानिदेशक की रिर्पोट		*v*
I	नीतिगत अनुसंधान	1
II	नीति शोध पत्र	21
III	नीतिगत वार्ता की संवृद्धिः सम्मेलन, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ	23
IV	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	97
V	प्रकाशन कार्यक्रम	104
VI	आकंड़े एवं सूचना केंद्र	113
VII	मानव संसाधन	116
VIII	वित्तीय विवरण	123

आरआईएस संचालन परिषद

अध्यक्ष

श्री श्याम सरन
पूर्व विदेश सचिव
विदेश मंत्रालय

उप–अध्यक्ष

डॉ. वी.एस. शेषाद्री

पदेन सदस्य

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय

सुश्री रीता ए. तेवतिया
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री शक्तिकांत दास
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

प्रोफेसर आशुतोष शर्मा
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री अमर सिन्हा
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय

अपदेन सदस्य

फरवरी 2016 तक

प्रोफेसर बी बी भट्टाचार्य
पूर्व उपकुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रो. दीपक नैयर
मानद प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

कमोडोर सी उदय भास्कर, वीएसएम
निदेशक, सोसाइटी फार पालिसी स्टडीज

28 मार्च 2016 से

डॉ. बलदेव राज
महानिदेशक
नेशनल इन्सिटिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरू

श्रीमति श्यामला गोपीनाथ
अध्यक्षा, एचडीएफसी बैंक

श्री जयंत दासगुप्ता
प्रबंध भागीदार, लक्ष्मीकुमारन एवं श्रीधरन एटोरनेएस तथा डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत

श्री शेषाद्री चारी
वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक एवं लेखक
नई दिल्ली

***सदस्य सचिव* (पदेन)**

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

श्री एस. टी. देवारे
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

सदस्य

श्री ए. एन. राम
पूर्व सचिव
विदेश मंत्रालय

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक
मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

प्रोफेसर रथिन रश्य
निदेशक
राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपुर्व सीईओ, नीति आयोग

श्री संतोष झा
संयुक्त सचिव, (पीपीएंडआर, जीसीआई)
विदेश मंत्रालय

विशेष आमंत्रित

डा. नागेश कुमार
प्रमुख, यूएन–ईएससीएपी दक्षिण और
दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय, नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अध्यक्ष का संदेश

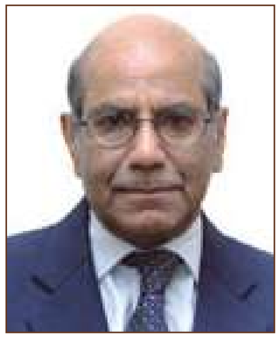

श्री श्याम सरन
अध्यक्ष, आरआईएस

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से, विकासशील देशों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। इसका एक घरेलू आयाम है जिसमें देश अपनी विशिष्टताओं को सामने रख कर लक्ष्यों की रूपरेखा बनाते रहे हैं। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है जिसमें सहयोग के लिए अवसरों की खोज, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने का कार्य एवं प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) जैसे संस्थानों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसीकि माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने इच्छा जताई है, विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एवं भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर आरआईएस सतत विकास लक्ष्यों के कारगर कार्यान्वयन में योगदान देने में सक्रियतापूर्वक जुटा हुआ है।

इस संस्थान ने अक्टूबर, 2015 में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी तैयार किए हैं। शिखर सम्मेलन ने अधिदेशित किया है कि आरआईएस में स्थापित भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) को विकासशील देशों में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा सफल विकास उपायों के दस्तावेजीकरण के लिए शिक्षाविदों, पत्रकारों, मीडिया की हस्तियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच संपर्कों को मजबूत बनाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर आरआईएस कार्य योजना का एक ओर उल्लेखनीय आयाम है दक्षिणीय सहयोग प्रक्रिया को मजबूत बनाने में इसकी भूमिका। विकासशील देशों के बीच सहयोग पर विकसित हो रहे विभिन्न तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए आरआईएस ने मार्च 2016 में दक्षिणीय सहयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (नेष्ट) का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही आरआईएस ने विदेश मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे आइटेक कार्यक्रम के तहत 'लर्निंग साउथ–साउथ कॉपरेशन' नामक एक नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की भी लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के तहत सभी प्रतिभागियों को दक्षिणीय सहयोग की व्यापक अवधारणों से परिचित कराया जाएगा।

संस्था बहुपक्षीय मंचों पर भी सक्रिय रही है और दिसंबर 2015 में नैरोबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय बैठक के दौरान अपनी प्रमुख विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट का लोकार्पण किया। क्षेत्रीय स्तर पर इस संस्था ने एक अन्य प्रमुख प्रकाशन *दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग रिपोर्ट* के द्वारा अपना योगदान दिया। क्षेत्रीय मोर्चे पर अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों में *प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू इकोनोमी इन द इंडियन ओशॅन* शीर्षक रिपोर्ट शामिल है। आरआईएस में स्थित आसियान–भारत केंद्र ने *आसियान–इंडिया डेवेलपमेंट एंड कोपरेशन रिपोर्ट* प्रकाशित की। इन योगदानों का नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा बहुमूल्य संदर्भ सामग्री के रूप में स्वागत किया गया है।

नीतिगत वार्ता को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में प्रमुख संगठनों के साथ संयुक्त रूप से कई सम्मेलनों, कार्यशालाओं, परामर्श बैठकों एवं संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। आरआईएस संकाय सदस्यों ने भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में अपनी भागीदारी के जरिये उल्लेखनीय योगदान दिया है। आरआईएस में स्थित आसियान–इंडिया सेंटर अनुसंधान अध्ययनों के प्रकाशन एवं कई समारोहों के आयोजन के द्वारा लगातार नीतिगत शोध जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इन कार्यक्रमों के बारे में इस वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से वर्णत है।

मैं इस अवसर पर उपाध्याक्ष डा. वी.एस. शेषाद्रि एवं संचालन परिषद के अन्य सदस्यों का संस्थान के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में उनके बहुमूल्य समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में, आरआईएस भारत सरकार और वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों को विश्लेषणात्मक नीतिगत अनुसंधान सहायता प्रदान करने के अपने अधिदेश को पूरा करता रहेगा।

श्याम शरण

महानिदेशक की रिपोर्ट

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

आरआईएस का अनुसंधान कार्यक्रम लगातार चार प्रमुख क्षेत्रों, क्रमशः वैश्विक आर्थिक मुद्दे एवं विकासशील देशों के बीच सहयोग, व्यापार एवं निवेश पर क्षेत्रीय पहल, क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और संपर्क तथा नई प्रौद्योगिकियां एवं विकास पर केंद्रित है। इन विषय वस्तुओं के तहत, संस्थान द्वारा जो शोध अध्ययन किए जा रहे हैं, उन्हें इस वार्षिक रिपोर्ट के नीतिगत अनुसंधान पर पहले अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के सक्रिय नेतृत्व के तहत, आरआईएस ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर विशेष कार्य योजना आरंभ की। आरआईएस, विदेश मंत्रालय; नीति आयोग; नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय एवं भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है और एसडीजी के कार्यान्वयन के लिए भारत एवं विकासशील देशों (दक्षिण) से दृष्टिकोण उपलब्ध कराने में प्रभावशाली योगदान दिया है। आरआईएस जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता रहा है, उनमें सामुद्रिक अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनोमी) तथा उत्तरदायी अनुसंधान एवं नवोन्मेषी प्रचलन (आरआरआई) भी शामिल हैं।

संस्थान ने अपने प्रमुख प्रकाशनों, *साउथ एशिया डेवेलपमेंट एंड कोपरेशन रिपोर्ट* तथा *वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवेलपमेंट रिपोर्ट* का भी प्रकाशन किया है। इन प्रवर्तक प्रकाशनों का लक्ष्य विकासशील देशों के लाभ के लिए क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराना है।

अक्टूबर 2015 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत–अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर दो विशेष रिपोर्ट *इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिप टूवार्ड्स सस्टेनेबल डेवेलपमेंट* एवं *इंडिया–अफ्रीका पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर : एकॉमप्लिशमेंट्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स* प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, आरआईएस ने *प्रॉस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकोनोमी इन द इंडियन ओशॅन* रिपोर्ट एवं कई अन्य शोध भी प्रकाशित किए। आरआईएस स्थित आसियान इंडिया सेंटर ने भी कई अन्य रिपोर्टों के साथ *आसियान–इंडिया डेवेलपमेंट एंड कोपरेशन रिपोर्ट 2015* प्रकाशित की।

जैसे कि हमारी कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर आधारित है, संस्थान ने नीतिगत समरूपता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं, परामर्श बैठकों, संगोष्ठियों एवं चर्चा बैठकों का आयोजन किया। इनमें विकासशील देशों के बीच सहयोग, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा पर परामर्श, विकास के लिए वित पोषण पर परामर्श एवं 2015 के बाद का एजेंडा, सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय परामर्श, डब्ल्यूटीओ एवं एसडीजी पर परामर्श, नैरोबी मंत्रीस्तरीय बैठक के समक्ष मुद्दे, अंतःप्रशांत क्षेत्र साझीदारी (टीपीपी) पर पैनल चर्चा, भारत–अफ्रीका साझीदारी पर परामर्श, हिन्द महासागर में सामुद्रिक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर आईओआरए ब्लू इकोनोमी डॉयलॉग, भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग पर संगोष्ठी आदि कार्यक्रम शामिल है।

अपनी स्थापना से ही आरआईएस विकासशील देशों के आपसी सहयोग की प्रक्रिया को बढ़ाने में सक्रितापूर्वक एवं कारगर तरीके से जुड़ा रहा है। इस सतत प्रयास के एक हिस्से के रूप में मार्च 2016 में नई दिल्ली में विकासशील देशों के सहयोग पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आरआईएस में भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) भी इस कार्य में सक्रिय रहा है और विकास सहयोग को बढ़ावा देने की विशिष्ट विषय वस्तुओं पर उसने नीतिगत सार पत्र भी प्रकाशित किए हैं। एफआईडीसी ने विकासशील देशों के सहयोग की व्यापक संरचना में भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा करने के लिए चेन्नई एवं जयपुर में संगोष्ठी का भी आयोजन किया।

संस्थान का आसियान और पूर्व एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (इरिया), बहु पक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक), इब्सा (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका), इंडियन ओसन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) आदि जैसे अन्य नेटवर्कों के साथ घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। इस संदर्भ में, इसे रेखांकित किए जाने की आवश्यकता है कि नेटवर्क ऑफ साउदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट) जिसकी संकल्पना एवं स्थापना आरआईएस द्वारा की गई है, का भी नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दक्षिणीय सहयोग सम्मेलन के दौरान लोकार्पण किया गया था।

अपनी क्षमता निर्माण कार्य योजना के एक हिस्से के रूप में, आरआईएस ने विकासशील देशों के प्रतिभागियों के लाभ के लिए भारतीय तकनीकी आर्थिक सहयोग (आईटेक) कार्यक्रम के अंतर्गत 'लर्निंग साउथ–साउथ कॉपरेशन' नामक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण का आयोजन किया। संस्थान ने 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्धे एवं विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर अपने वार्षिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। संस्थान 2017 से साईंस डिप्लोमैसी पर एक नए आईटेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी आरंभ करने जा रहा है। आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया सेंटर, आसियान–भारत आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के कार्य में भी सक्रियतापूर्वक जुटा है। इसने अन्य कई महत्वपूर्ण समारोहों के अतिरिक्त, आसियान–भारत संबंध : एक नया आयाम पर दिल्ली डॉयलॉग VIII, आसियान–भारत सांस्कृतिक संपर्कों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सामुद्रिक सुरक्षा एवं सहयोग पर ईएएस सम्मेलन, आसियान–भारतीय विशिष्ट व्यक्ति व्याख्यान, थिंकटैंकों के आसियान–भारतीय नेटवर्क पर चौथा गोलमेज, आदि आसियान–भारतीय एकीकरण एवं विकास पर गोलमेज, आसियान–भारतीय संपर्कों पर गोलमेज आदि का भी आयोजन किया। सेंटर ने कई रिपोर्टों के अतिरिक्त, *आसियान–भारत सांस्कृतिक संपर्क : ऐतिहासिक एवं समसामयिक आयाम, आसियान–भारत आर्थिक संबंधः अवसर एवं चुनौतियां,* और *भारत एवं एपीएसी : एक मूल्यांकन* शीर्षक रिपोर्टों का भी प्रकाशन किया।

आरआईएस अपने कार्यकलापों को लगातार अपनी वेबसाइट, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया मंचों के जरिये प्रचारित करता है।

यहां, मैं आरआईएस के चेयरमैन श्री श्याम शरण एवं आरआईएस संचालन परिषद के अन्य सदस्यों को संस्थान के अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए उनके समर्थन एवं दिशा निर्देश के लिए हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय तथा अन्य विभागों जैसे कि आर्थिक विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य सभी सहयोग करने वाले संस्थानों को हमारी कार्य योजना के साथ उनके सक्रिय सहयोग संबंध के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर आरआईएस संकाय में अपने वरिष्ठ सहयोगियों तथा अनुसंधान एवं प्रशासन टीमों के अन्य सदस्यों को भी आरआईएस के प्रयोजनों एवं लक्ष्यों को अर्जित करने में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

सचिन चतुर्वेदी

I

नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस का अनुसंधान कार्यक्रम वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्यता चार व्यापक क्षेत्रों में रहा है (क) वैश्विक आर्थिक मुद्दे और दक्षिणीय सहयोग; (ब) व्यापार और निवेश पर क्षेत्रीय पहलें; (ग) क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुगमीकरण और संयोजकता; (घ) नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे। इन व्यापक विषय वस्तुओं के अंतर्गत विशिष्ट अध्ययन निम्नानुसार हैं:

क. वैश्विक आर्थिक मुद्दे और दक्षिणीय सहयोग

वर्ष 2015 पूर्व वैश्विक विकास एजेंडा

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/डॉ. के. रवि श्रीनिवास/प्रो. टी. सी. जेम्स/डॉ. सब्यसाची साहा/श्री अमित कुमार/श्री प्रत्युष

आरआईएस विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, भारत सरकार के विभागों और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर भारत में विधि निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच विचार–विमर्श के एक कार्यक्रम की मुहिम चला रहा है, ताकि इस एजेंडे में निहित भारत के प्रासंगिक लक्ष्यों पर अमल के लिए एक खाका (रोडमैप) तैयार करने की दिशा में जल्द से जल्द अधिकतम जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यही नहीं, आरआईएस ज्ञान संबंधी साझेदारी को मजबूत करने के लिए एसडीजी से जुड़े विशिष्ट मुद्दों पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों और भारत के संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में आरआईएस ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2015 पूर्व के विकास एजेंडे का औपचारिक रूप से अनुमोदन किए जाने से पहले भारत में एसडीजी पर विचार–विमर्श की एक श्रृंखला का

आयोजन किया। एसडीजी का अनुमोदन किए जाने से पहले इथियोपिया के अदीस अबाबा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित 'विकास के लिए वित्त पोषण (एफएफडी3)' पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पूर्व विकास के लिए वित्त पोषण पर विचार–विमर्श का आयोजन किया। एफएफडी3 के मौके पर प्रथम विचार–विमर्श 8 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में और द्वितीय विचार–विमर्श 14 जुलाई 2015 को अदीस अबाबा में आयोजित किए गए। इन बैठकों के बाद एफएफडी3 के निष्कर्ष एवं भारत के नजरिए पर मीडिया के साथ बातचीत का भी नई दिल्ली में आयोजन किया गया।

इन बैठकों में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने इन बैठकों का उद्‌घाटन किया। विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन विचार–विमर्श में भाग लिया। सितंबर 2015 में नई दिल्ली में नीति आयोग के साथ साझेदारी में एसडीजी पर एक बड़ा उच्चस्तरीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आरआईएस ने सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में भी उच्चस्तरीय पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ किया गया, जिसने दक्षिणीय दृष्टिकोण और वैश्विक संस्थागत संरचना (अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण) से जुड़े मुद्दों का पता लगाने के लिए औपचारिक रूप से एसडीजी को अपनाया।

आरआईएस वर्ष 2016 में एसडीजी पर अपने कार्यकलाप कार्यक्रम को जारी रखेगा तथा एसडीजी के सामाजिक एवं आर्थिक आयामों से जुड़ी परिचर्चा में तेजी लाएगा और इसके साथ ही वैश्विक, राष्ट्रीय एवं उप–राष्ट्रीय मुद्दों को समायोजित करने वाले एसडीजी के कार्यान्वयन के उपायों पर सहभागिता को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कल्याण कार्यक्रमों के संयोजन में एसडीजी का स्थान सुनिश्चित करने और एसडीजी में निहित विकासात्मक लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई में उन्मुख दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विचार–विमर्श आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सरकारों सहित राज्यों के स्तर पर प्रमुख माने जाने वाले निकाय शामिल होंगे। विस्तृत परिपेक्ष के दोनों सिरों पर राज्यों के साथ सहभागिता और इस तरह एसडीजी को पाने के एक साधन के रूप में सहकारी संघवाद पर राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत समझ को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरआईएस में भारतीय विकास सहयोग के लिए मंच (एफआईडीसी) के तहत यह पहल की जा रही है। आरआईएस इसके अलावा एसडीजी के तहत संबंधित लक्ष्यों और प्रमुख क्षेत्रवार वित्त एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर फोकस करने वाले दृष्टिकोण प्रपत्रों (पेपर) पर आधारित मौलिक प्रकाशन भी प्रस्तुत करेगा।

देशों का वर्गीकरण और जी–20

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. मनमोहन अग्रवाल

जी–20 पर तुर्की की अध्यक्षता में समावेश को उनके कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। तुर्की की अध्यक्षता वाले इस प्रस्ताव पर और आगे बढ़ने से पहले इस पेपर में उल्लिखित कई वैचारिक मुद्दों पर विस्तार से गौर करने की जरूरत है। तुर्की की अध्यक्षता में दिए गए सुझाव के मुताबिक भारत को अल्प आय वाले विकासशील देशों (एलआईडीसी) के समूह से बाहर कर देने की स्थिति में विकासशील देशों के हितों से जुड़े कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की अगुवाई समाप्त हो

जाएगी। इस मुद्दे पर एक नीतिगत संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के बाद भी आरआईएस इस दिशा में निरंतर कार्यरत है।

नैरोबी में आयोजित डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए विभिन्न मुद्दे

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. के. रवि श्रीनिवास/प्रो. टी. सी. जेम्स

(1) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महानिदेशक रॉबर्टो एजेवेडो ने केन्या के नैरोबी में 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के आयोजन से पहले ही दोहा विकास एजेंडे के शेष मुद्दों का समाधान करने पर विशेष जोर दिया। हालांकि, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य प्रतीत होता है। इसके बावजूद आरआईएस ने विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न मुद्दों विशेषकर नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से जुड़े प्रासंगिक मुद्दों पर अपना कार्य तेजी से आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में संस्था ने बहुपक्षीय विकास की रोशनी में मेगा–क्षेत्रीय समझौतो के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए अपनी विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट का नैरोबी में लोकार्पण किया कृषि संबंधी समझौते (एओए) के दायरे में रहते हुए विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा चिंताओं का एक 'स्थायी समाधान' निकालना भी एक विशेष मुद्दा है। आरआईएस ने इस मुद्दे पर वर्तमान चुनौतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया और आगे की संभावित राह सुझाई।

(2) बौद्धिक संपदा से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में निम्नलिखित संभावित मसलों पर चर्चा होने की आवश्यकता है :

- बौद्धिक संपदा और नवाचार
- बौद्धिक संपदा और जलवायु परिवर्तन
- अनुच्छेद 27.3 (ख) की समीक्षा और ट्रिप्स समझौते एवं जैव विविधता तथा पारंपरिक ज्ञान एवं लोक साहित्य के संरक्षण पर सम्मेलन के बीच नाता।
- अल्प विकसित देशों (एलडीसी) द्वारा ट्रिप्स समझौते का कार्यान्वयन और एलडीसी के लिए परिवर्तन काल का विस्तार। ट्रिप्स समझौते के तहत गैर–उल्लंघन एवं शिकायतों की स्थिति पर स्थगन का विस्तार।
- तंबाकू उत्पादों के लिए सरल पैकेजिंग आवश्यकताएं।
- क्या वार्ताओं को शराब और मदिरा संबंधी भौगोलिक संकेतकों (जीआईएस) तक ही सीमित कर दिया जाना चाहिए अथवा क्या इन वार्ताओं का दायरा बढ़ाकर इसमें शराब और मदिरा के अलावा अन्य वस्तुओं से संबंधित जीआईएस को भी शामिल करना चाहिए। इस पर आम सहमति है।
- व्यापार और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, ट्रिप्स के अनुच्छेद 66.2 पर अमल से उभरने वाले आईपी संबंधी संभावित मुद्दे।

(3) एलडीसी की शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) बाजार पहुंच के मसले के संबंध में आरआईएस इस मुद्दे के विभिन्न आयामों पर गौर कर रहा है:

- हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2005) से लेकर बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) तक इस मुद्दे पर हुई बहस का विश्लेषण करना।
- एलडीसी की बाजार पहुंच पर भारत की शुल्क मुक्त व्यापार वरीयता (डीएफटीपी) योजना के प्रभाव का परीक्षण।
- भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 97 प्रतिशत तक कवरेज को बढ़ाने संबंधी फैसले के निहितार्थ का पता लगाना।
- डीएफक्यूएफ योजना के संबंध में कुछ विकासशील देशों विशेषकर चीन,

ब्राजील और रूस जैसे देशों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना।

- सभी विकासशील देशों विशेषकर प्रति वर्ष 200 अरब डॉलर से अधिक राशि का वैश्विक निर्यात करने वाले देशों की डीएफक्यूएफ नीतियों के निहितार्थ पर अनुभवों के आधार पर गौर करना।

यदि विकसित और विकासशील देशों में इस आशय का समझौता हो जाता है कि वे एलडीसी को उनकी उत्पाद लाइनों के 97 प्रतिशत की सीमा तक डीएफक्यूएफ बाजार पहुंच की पेशकश करेंगे तो वैश्विक व्यापार का ढांचा बदल जाएगा।

जी–20 प्रस्ताव/जी–20 के तहत व्यापार और निवेश के मुद्दे

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. राम उपेंद्र दास

व्यापार और निवेश अपने–आप में ना केवल महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि यह रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन जैसे विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने का आवश्यक साधन है। व्यापार एवं निवेश का प्रवाह वैश्वीकरण के इस युग में अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है तथा इससे समस्त देशों एवं क्षेत्रों की आपसी अंतर–निर्भरता बढ़ गई है। इन प्रवाहों के साथ–साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय नीति वाली व्यवस्थाओं तथा इस तरह के प्रवाहों के नियंत्रित स्वरूप में होने की बात सामने आई है, जिन पर उच्चस्तरीय नीतिगत ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि व्यापार और निवेश के विकास एवं तरक्की से जुड़े अहम निहितार्थ होते हैं, इसलिए ऐसे में उच्च स्तर पर वैश्विक ध्यान सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है, ताकि राष्ट्रीय स्तर के सफल परिणामों के जरिए समग्र वैश्विक आर्थिक उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अध्ययन में कार्रवाई के लिए कुछ विशेष सुझावों का उल्लेख किया जाएगा और फिर इन्हें जी–20 के नेताओं के समक्ष रखा जाएगा।

ऐसा होने के लिए कुछ कार्रवाई किए जाने वाले मुद्दों का खाका तैयार करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। इन मुद्दों पर जी–20 के नेताओं द्वारा विचार किया जाना चाहिए। आरआईएस सक्रिय रूप से जी–20 प्रक्रिया में भाग लेता आ रहा है। आरआईएस ने जी–20 की फरवरी 2015 में इस्तांबुल में, नवंबर 2015 में अंताल्या में और दिसंबर 2015 में बीजिंग में हुई बैठकों में भी भाग लिया।

वैश्विक मूल्य चेन में भारत–आसियान क्षेत्रीय सहयोग

प्रो. एस. के. मोहंती

भारत की नई विनिर्माण नीति को उच्च तकनीक वाले कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि मशीनरी, विद्युत एवं ऑप्टिकल उत्पादों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आसियान देशों की विनिर्माण नीति के साथ व्यापक रूप से एकीकृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत कलपुर्जों एवं सहायक सामान (एक्सेसरीज) से की जा सकती है। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि ये भारत और आसियान के बीच के मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल हैं। ये क्षेत्र भारत–आसियान एफटीए के ढांचे में खास अहमियत रखते हैं। इस ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका असर छोटे एवं मझले उद्योगों पर पड़ेगा। इस अध्ययन में उन उद्योगों के भीतर सीमा पार नेटवर्कों का निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, जिनमें भारत को विनिर्माण क्षमता और अनुपूरकताएं हासिल हैं और जो आसियान की मांग या आपूर्ति क्षमता से मेल खाती हैं। इसी तरह अध्ययन में उन उद्योगों के भीतर सीमा पार नेटवर्कों का निर्माण करने की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा, जिनमें आसियान को विनिर्माण क्षमता और अनुपूरकताएं हासिल हैं और जो भारत की मांग या आपूर्ति क्षमता से मेल खाती हैं। इसके अलावा, इस अध्ययन में

क्षेत्र के भीतर उत्पादन नेटवर्कों के निर्माण में निहित चुनौतियों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। इस अध्ययन में यह भी पता लगाया जाएगा कि आसियान एवं भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों को बढ़ावा देने में कनेक्टिविटी और व्यापार सुविधा से जुड़ी क्या–क्या कमियां हैं और इसके साथ ही संभावित उपाय भी बताए जाएंगे।

दक्षिणीय सहयोगः भारत–अफ्रीका विकास सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. एस. के. मोहंती/प्रो. टी.सी. जेम्स/श्री अमित कुमार

डीपीए के सहयोग से आरआईएस–एफआईडीसी ने अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग की कुछ सफल परिणामों पर अध्ययन किया। भारत–अफ्रीका मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन जिसका वर्ष 2015 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया जिसके लिए आरआईएस–एफआईडीसी ने विशेष दस्तावेज उपलब्ध कराए। यह अध्ययन जमीनी स्तर वाली उन क्षमता निर्माण परियोजनाओं पर केंद्रित था जो इस क्षेत्र में भारत द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गईं हैं और जो विकासशील देशों में भारत के विकास सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रभावी रूप से दर्शाते हैं।

दक्षिणीय भागीदारी पर वैश्विक डेटाबेस की प्रवृत्तियों

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. मिलिंदो चक्रबर्ती/श्री सुशील कुमार/श्री प्रत्युष/सुश्री श्रुति शर्मा

दक्षिण से विकास सहयोग संबंधी जानकारी के संग्रह, संकलन, प्रोसेसिंग, विश्लेषण और प्रसार के लिए एक साझा मंच निश्चित रूप से संभव है, लेकिन यह प्रतिवादों के साथ ही मुमकिन है। दक्षिणीय सहयोग न तो एक व्यापक अवधारणा है और न ही यह अपने कार्यकलापों में सख्त है। विकासशील देश जो विकास से जुड़ी पहल करते हैं जो एसएससी के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और हर देश की जरूरतों एवं सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों के आधार पर भिन्न होती है। सभी दक्षिणी राष्ट्र एसएससी के समान स्वरूप के अंतर्गत एकजुट नहीं हैं और हर दक्षिणी देश विकास सहयोग संबंधी जानकारी के संग्रह एवं विश्लेषण के लिए अपनी खुद की व्यवस्था कर सकता है। अतः ऐसी कोई मानक एसएससी सांख्यिकीय प्रबंधन प्रणाली नहीं हो सकती है जो सभी दक्षिणी देशों की प्रथाओं को अवश्य ही शामिल करे। साक्ष्य पर आधारित विश्लेषण नीति एवं रणनीति के विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन सुलभ कराता है और इसका अपेक्षाकृत अधिक ध्यान के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वर्तमान में, अच्छा डेटा सेट व्यापार और एफडीआई जैसे कुछ क्षेत्रों में तो उपलब्ध हैं, लेकिन सेवाओं एवं विकास सहयोग के क्षेत्र में अथवा कमजोर आर्थिक संस्थानों वाले देशों में ये सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं। हाल ही में विकासशील देशों की साझेदारियों में अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत ब्यौरा इकट्ठा किया जाता है और व्यवस्थित विश्लेषण हो सके। डेटा बेस से इस कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

विकासशील देशों में निर्यात परिष्करण : उभरती प्रवृत्तियां और चुनौतियां

प्रो. प्रबीर डे/सुश्री श्रेया पैन

इस अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य होंगे। पहला, यह निर्यात परिष्करण को मापेगा और दूसरा, यह निर्यात परिष्करण के प्रमुख निर्धारकों को समझने का प्रयास करेगा।

इस अध्ययन के निष्कर्ष हमें यह बताएंगे कि विकासशील देश किस तरह से निर्यात परिष्करण के मामले में विकसित दुनिया के मुकाबले प्रदर्शन करेंगे। यह विकासशील देशों को अपने निर्यात बास्केट के उन्नयन का अवसर प्रदान करने के लिए एक नीतिगत दिशा भी प्रदान करेगा।

ख. व्यापार और निवेश पर क्षेत्रीय पहलें

वैश्वीकरण की राह पर अग्रसर मध्य एशिया के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से सबक

प्रो. राम उपेंद्र दास

एशिया–प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के दायरे में मध्य एशियाई क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। न केवल यह क्षेत्र ऐतिहासिक सिल्क रूट के संचालन मार्ग में अहम रहा है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे पूर्वी, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण, उत्तरी और पश्चिमी एशिया को एकीकृत करने के लिहाज से एक आर्थिक मिलन स्थल के रूप में भी तब्दील कर दिया है। संक्षेप में, मध्य एशियाई क्षेत्र विशेषकर ऐसे समय में वैश्विक एकीकरण के एक नए संभावित केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है जब आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र एशिया की ओर स्थानांतरित हो गया है। वैसे तो मध्य एशियाई देश अप्रयुक्त व्यापक आर्थिक संभावनाओं के साथ प्राकृतिक, खनिज और मानव संसाधनों के मामले में अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन पूर्ववर्ती आर्थिक प्रतिमान से कहीं अलग हटकर उनका संक्रमण पूरा होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। यही नहीं, क्षेत्रीय एकीकरण के अर्थशास्त्र के मामले में भी उन्हें बेहद कम अनुभव है। इसी पृष्ठभूमि में संबंधित पेपर ने मध्य एशिया में हुए आर्थिक विकास की रूपरेखा का विश्लेषण किया है और इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में, भारत में हुए आर्थिक विकास एवं प्रगति से कुछ सबक लेने की कोशिश की गई है। यह पेपर वैश्वीकरण की राह पर अग्रसर मध्य एशियाई क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से भविष्य में भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करेगा।

एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में समुद्रीय अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) का उद्भव : अवसर और चुनौतियां

प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. प्रियदर्शी दास/सुश्री आस्था गुप्ता

हाल के वर्षों में समुद्र आधारित संसाधनों की निरंतर बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप समुद्रीय अर्थव्यवस्था की ओर पूरी दुनिया का ध्यान कई गुना बढ़ गया है। समुद्रीय अर्थव्यवस्था से जहां एक ओर उत्पादन एवं मानव उपभोग के लिए समुद्र आधारित संसाधनों की बढ़ती मांग की पुष्टि होती है, वहीं दूसरी ओर इसके एवज में पर्यावरण क्षरण के रूप में भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसके तहत समावेशी विकास की रणनीति के साथ समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आईओआरए के तहत समुद्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू गरीबी में कमी और सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा के उन्मूलन में इसके अहम योगदान के रूप में प्रतिबिंबित होता है। महासागर ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध खजाने हैं जिनकी अपनी खुद की जैविक प्रक्रियाओं के जरिए पुर्नावर्तन (रिसाइक्लिंग) हो सकती है और इसके साथ ही उन्हें फिर से संचित भी किया जा सकता है। वास्तव

में, महासागर समुद्री संसाधनों की अत्यधिक खपत से उत्पन्न जोखिमों को समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उपयुक्त संरक्षण और संयोजन उपायों को बाकायदा लागू किया जाए। समुद्रीय अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाने से गरीब और कमजोर लोगों की आर्थिक बेहतरी के अवसरों को गंवाने की संभावनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी काफी कम की जा सकती हैं।

वैसे तो समुद्रीय अर्थव्यवस्था को सतत विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक अलग पहल के रूप में इसे लोकप्रिय बनाने से वैश्विक समुदाय को समुद्री एवं तटीय संसाधनों की विशाल क्षमता के बारे में जागरूक करना और संसाधन गहन 'ब्राउन' विकास मॉडल (ब्राउन या भूरे रंग से आशय दरअसल खनिजों से है) की खामियों को उजागर करना संभव हो सकता है, जिसके तहत अंतर्निहित रूप से मुख्यतः संसाधनों की निकासी पर ध्यान लगाया जाता है, जबकि समुद्र आधारित प्राकृतिक संसाधनों के संचयन एवं लचीलेपन पर ठीक उतना ध्यान कतई नहीं दिया जाता है। समुद्रीय अर्थव्यवस्था की खासियतों के अनुरूप ही राष्ट्रीय विकास नीतियों को ढाल देने से अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी के बीच के इंटरफेस और द्वंद्व स्पष्ट रूप से सामने आ सकते हैं और इसके साथ ही समावेशी विकास एवं सतत विकास के दोनों उद्देश्यों को एक–दूसरे से जोड़ने के लिए उपयुक्त व्यवस्थां की जा सकती है।

समुद्रीय अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में फैल रही है। ब्लू इकोनॉमी का मानचित्रण और अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों पर इसके असर का आकलन इस क्षेत्र के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है : (1) सजीव संसाधन – मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, समुद्री खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, समुद्री सिवार, शैवाल, जलीय पौधे, मत्स्य हैचरी, इत्यादि; (2) परिवहन– गहरे समुद्र में माल ढुलाई, अंतर्देशीय जल परिवहन, समुद्र में यात्री परिवहन, तटीय और विशाल झीलों में यात्री परिवहन, समुद्री भंडार एवं भंडारण, जल में परिवहन के लिए अन्य सहायक गतिविधियां, इत्यादि; (3) जल आधारित पर्यटन और मनोरंजन – समुद्र में अवकाश का आनंद, सुंदर और दर्शनीय स्थलों में परिवहन, मनोरंजन के सामान किराये पर लेना, खेल और मनोरंजन संबंधी अध्ययन, नाव डीलर, पूर्ण सेवा वाले रेस्तरां, होटल, मोटल और लॉजिंग स्थल, बंदरगाह, मनोरंजन वाहन पार्क एवं शिविर, सुंदर जल में पर्यटन, इत्यादि; (4) समुद्री औद्योगिक गतिविधियां– जहाज एवं नाव निर्माण सहित समुद्री निर्माण, खोज और नौवहन उपकरण, नौका विहार (बोटिंग) नेट, समुद्री खेल के सामान का उत्पादन, इत्यादि; (अ) समुद्री अक्षय ऊर्जा सहित ऊर्जा – हवा, तरंग, ज्वार, थर्मल रूपांतरण, बायोमास, इत्याादि; (5) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण – अपतटीय तेल एवं गैस की खोज, पाइपलाइन और संबंधित संरचनाओं का निर्माण, इत्यादि; (6) शिक्षा – समुद्री विज्ञान एवं प्रशिक्षण, विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरिंग, भू–सूचना विज्ञान, मेट्रोलोजी संबंधी परामर्श, जल–सर्वेक्षण, इत्यादि; (7) समुद्र तल पर खनिजों का अन्वेषण – कच्चा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की निकासी, बहुधात्विक पिंड, कोबाल्ट पपड़ी, सल्फाइड, इत्रियम, डिस्प्रोसियम एवं टर्बियम, औद्योगिक रेत का खनन, भूभौतिकीय अन्वेषण और सेवाओं का मानचित्रण, इत्यादि; (8) बंदरगाह संबंधी गतिविधियां– खुदाई, रो रो, रो पैक्स, लो लो, जहाज चित्रकला, बंदरगाह और पत्तयन का संचालन, समुद्री कार्गो का संचालन, जहाज और नाव की मरम्मत, इत्यादि; (9) समुद्री सेवाएं– हाई टेक समुद्री सेवाएं, समुद्री वित्तीय सेवाएं, समुद्री बीमा एवं समुद्री कानूनी सेवाएं, समुद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास, मनोरंजन और विहार संबंधी सेवाएं, शिपिंग के लिए नौवहन सेवाएं,

इत्यादि; और (10) भारी निर्माण सहित समुद्री निर्माण व इंजीनियरिंग– समुद्र–तट, पुल और समुद्री सुरंग, इत्यादि।

आईओआरए क्षेत्र में मत्स्य पालन के आर्थिक पहलू

प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. प्रियदर्शी दास

आईओआरए पिछले दशक के दौरान अफ्रीकी–एशियाई क्षेत्र में एक जीवंत क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर कर सामने आया है। वैसे तो इस क्षेत्र का इंट्रा–क्षेत्रीय व्यापार (आईआरटी) वर्ष 2013 में 29.2 फीसदी दर्ज किया गया है, लेकिन इस क्षेत्र में पांच कस्टम यूनियनों की मौजूदगी के कारण इसे 'खुले क्षेत्रवाद' को आगे बढ़ाना होगा। इससे आईओआरए में एफटीए होने की संभावना सीमित हो गई है। एक वैकल्पिक नीतिगत रणनीति के रूप में क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रित किया जा सकता है और अतीत में इस क्षेत्र से जुड़ी कल्पना के तहत क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र की पहचान की गई है। सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में मछली पकड़ने के कार्य का योगदान कई मायनों में विशेष रूप से भोजन, पोषण, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मत्स्य पालन क्षेत्र पर आरआईएस के वर्तमान कार्यकलाप कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में मत्स्य पालन सेक्टर के आर्थिक आयामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभी जारी एक अध्ययन के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों जैसे कि आजीविका सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, उत्पादन संरचना, व्यापार आयामों के साथ–साथ आईओआरए में एक क्षेत्रीय संस्थागत व्यवस्था की संभाव्यता पर गौर किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय फोरम की अहमियत को और आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भी ऐसे कई अन्य आर्थिक मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत शोध की जरूरत है। मछली की कीमतों में तेज उतार–चढ़ाव, क्षेत्रवार सब्सिडी के मुद्दे (हालांकि, इस पर डब्ल्यूटीओ में चर्चा हुई है), एनटीबी, मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रीय मानक पर चर्चा, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि इन मुद्दों में शामिल हैं। मत्स्य पालन पर आरआईएस के भावी कार्यकलाप कार्यक्रम के अंतर्गत इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि इस दिशा में आगे विश्लेषण किया जा सके।

भारत–अफ्रीका आर्थिक सहयोग पर टीएफटीए का प्रभाव

प्रो. एस. के. मोहंती

अफ्रीका ने क्षेत्रीय समूहों पर परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में अफ्रीका की एकीकरण प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। यह प्रक्रिया पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र में शुरू की गई है, जिसमें अफ्रीका की 26 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसे त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (टीएफटीए) नाम दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा), दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी) शामिल हैं। इस तरह की व्यवस्था के आर्थिक प्रभाव पर आरआईएस करीबी नजर रख रहा है। अफ्रीका के साथ भारत का व्यापक आर्थिक सहयोग पिछले दो दशकों के दौरान काफी तेजी से बढ़ा। वैसे तो अफ्रीका के साथ कुल व्यापार में भारत एक शुद्ध आयातक है, लेकिन अनेक देशों को भारत से निरंतर अच्छा– खासा निर्यात हो रहा है। अफ्रीका इसके साथ ही भारत के लिए बाह्य एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत रहा है।

भारत के एफटीए/सीईसीए : प्रभाव और भविष्य की दिशा

प्रो. राम उपेंद्र दास

भारत के एफटीए के सकारात्मक प्रभावों के अब भी कोसों दूर रहने के वर्तमान ब्यौरे को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन के तहत विभिन्न संबंधित पहलुओं का यथार्थपरक आकलन किया जाएगा। इसके मद्देनजर मंत्रणा के लिए विशेष बैठकों की योजना बनाई जा रही है।

बेल्ट और रोड पहल

प्रो. एस. के. मोहंती

आरआईएस 'बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई)' तथा भारत एवं अन्य विकासशील देशों के लिए इसके निहितार्थों पर करीबी नजर रख रहा है। बीआरआई के तहत इसकी समस्त सहायक सुविधाओं के साथ मार्ग तैयार करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की पहचान करने के साथ–साथ इन्हें क्रियान्वित भी किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि व्यापार और निवेश के प्रवाहों पर परियोजना का आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा। इन प्रस्तावित पहलों पर विभिन्न देशों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई हैः एक प्रतिक्रिया में परियोजना के संभावित भू–राजनीतिक निहितार्थों को लेकर आशंका जताई गई है और एक अन्य प्रतिक्रिया में एक संभावित अवसर गंवा देने का उल्लेख किया गया है।

चीन ने नए समुद्री रेशम मार्ग (सिल्क रूट) के निकट प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक के विस्तृत दायरे को छूने वाली एक ट्रांस–यूरेशियाई परियोजना का प्रस्ताव रखा है, जो प्रशांत एवं हिंद महासागर को कवर करेगी और जो उसकी अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी पहलों में से एक है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग पूरे यूरो–एशियाई क्षेत्र को आपस में जोड़ेगी। उत्तरी सड़क भूमि पर अवस्थित सड़क होगी और यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। दक्षिणी सड़क एक समुद्री मार्ग है, जो भारत को भी स्पर्श करेगा।

यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संयुक्त संभाव्यता अध्ययन

प्रो. राम उपेंद्र दास

एक तरफ भारत और दूसरी तरफ आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान एवं रूस के आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच संभावित पूरकता को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) का गठन किया गया है, ताकि वह इस आर्थिक संघ के साथ भारत की आर्थिक सहयोग सहभागिता के लिए समुचित दृष्टिकोण और प्रक्रिया की सिफारिश कर सके। भारत की हालिया आर्थिक गतिशीलता के साथ–साथ इस समूह के सदस्यों के आर्थिक प्रदर्शन के मद्देनजर इसके साथ व्यापक रूप से संलग्नता आवश्यक प्रतीत होती है, जिसमें वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के साथ–साथ आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र भी शामिल हों। यह अध्ययन इस तथ्य के मद्देनजर भी आवश्यक प्रतीत होता है कि अतीत में इस क्षेत्र के अत्यंत मजबूत आर्थिक संबंध रह चुके हैं और ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए भी इसे मजबूत बनाया जा सकता है। इस अध्ययन की खातिर जेएसजी को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आरआईएस से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने संपर्क साधा है।

आरआईएस ने जुलाई 2015 में मास्को में आयोजित संयुक्त संभाव्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की पहली बैठक में भाग लिया था।

शेष एशिया के साथ पूर्वी और दक्षिण–पूर्व एशिया को एकीकृत करने के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में दक्षिण एशिया

प्रो. राम उपेंद्र दास

भारत की अगुवाई में दक्षिण एशिया की हालिया आर्थिक गतिशीलता के साथ–साथ विभिन्न विश्वसनीय अनुमानों में इसके वर्ष 2016 में सर्वाधिक तेजी से विकासोन्मुख क्षेत्र रहने की संभावनाएं व्यक्त किए जाने और भारतीय नीति–निर्माण के तहत 'मेक इन इंडिया' पहल पर विशेष जोर दिए जाने के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ पूर्वी एशिया एवं आसियान और दूसरी तरफ दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और यहां तक कि अफ्रीका के पूर्वी तट को आपस में एकीकृत करने में दक्षिण एशिया और भारत एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत दक्षिण एशिया और भारत परिकल्पित रूप से एशिया के विभिन्न भागों के लिए एक आर्थिक केंद्र बनने के लिहाज से बिल्कुल अनुकूल नजर आते हैं। बहरहाल, यह एक ऐसा विषय है जो अपनी संपूर्णता में विश्लेषित नहीं किया गया है। यही नहीं, इस उद्देश्य के मद्देनजर सटीक क्षेत्रों और आयामों की पहचान करने हेतु भी इस विषय को खंगाला नहीं गया है और इस तरह इन पर अब तक पर्याप्त नीतिगत ध्यान नहीं दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तावित अध्ययन के बुनियादी उद्देश्य ये हैंः (1) एशिया के विभिन्न भागों को एकीकृत करने के लिए भारत को एक आर्थिक केंद्र बनाने हेतु विश्लेषणात्मक और अनुभवजन्य आधार प्रदान करना (2) समस्त उप–क्षेत्रों में ऐसे आयामों और सेक्टरों की पहचान करना जिनमें भारत इस तरह की अहम भूमिका निभा सकता है और (3) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु नीतिगत उपाय और तौर–तरीके सुझाना। ईआरआईए, जकार्ता के लिए यह अध्ययन किया जा रहा है।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार

प्रो. राम उपेंद्र दास

भारत ने हाल ही में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए एक रणनीति शुरू की है। इसके तहत उन क्षेत्रों में भारत के व्यापार एवं निवेश सहयोग के जरिए आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सीएलएमवी की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुकूल हैं। यही नहीं, विशेष रूप से म्यांमार के जरिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर फोकस करने वाले क्षेत्रीय सहयोग का विस्तारीकरण मेकांग क्षेत्र में भी किया जा सकता है, जिसमें कंबोडिया, लाओ पीडीआर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इस संबंध में एक अध्ययन भारत–म्यांमार सीमा व्यापार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है जिसमें वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, निवेश, बैंकिंग एवं वित्त और कनेक्टिविटी को कवर किया जा रहा है। यह अध्ययन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है।

भारत–कोमेसा सीईपीए पर संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट

प्रो. एस. के. मोहंती

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) ने दोनों ही पक्षों के विचाराधीन भारत–कोमेसा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को औपचारिक रूप देने की संभाव्यता पर गौर करने के लिए वर्ष 2012 में एक संयुक्त अध्ययन का शुभारंभ किया। आरआईएस ने संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें वस्तु व्यापार के उदारीकरण, सेवा व्यापार के उदारीकरण एवं निवेश उदारीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया है। रिपोर्ट में व्यापार के विस्तार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में निहित संभावनाओं और भारत के साथ–साथ कोमेसा के सदस्य देशों में भी सहयोग के अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। भारत–कोमेसा सीईपीए से दोनों ही पक्षों की व्यापार क्षमता में संभावित वृद्धि का संकेत देने के अलावा अध्ययन में टैरिफ की मौजूदा संरचना, गैर टैरिफ बाधाओं, मूल उद्‌गम स्थल के नियमों, व्यापार सुविधा एवं एफडीआई नीतियों और इन क्षेत्रों में भावी सुधारों के रोडमैप पर भी प्रकाश डाला गया है। जहां एक ओर टैरिफ में कमी से भारत और कोमेसा के बीच व्यापार का व्यापक विस्तारीकरण होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर मूल उद्‌गम स्थल के नियमों में सुधारों के महत्व, व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, एसपीएस और टीबीटी उपायों पर विशेष बल दिया गया है। वस्तुओं के व्यापार के अलावा, अध्ययन से भारत और कोमेसा के बीच सेवाओं के व्यापार में मजबूत पूरकता होने का पता चला है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों ही पक्षों की प्रतिस्पर्धी क्षमता की तुलना करने पर यह पाया गया है कि भारत और कोमेसा दोनों को ही प्रस्तावित सीईपीए के संदर्भ में सेवाओं पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यापार नीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन की व्यापक सिफारिशों की परिकल्पना तरजीही बाजार पहुंच के लिए जारी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जिसका सामना हाल के वर्षों में भारत और कोमेसा के सदस्य देशों दोनों को ही करना पड़ा है।

इब्सा: अनुसंधान कार्यक्रम और विजिटिंग फेलोशिप

प्रो. सचिन चतुर्वेदी/प्रो. एस. के. मोहंती/डॉ. बीना पांडे

आरआईएस भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इब्सा वार्ता मंच – ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के तहत भारत के दो अन्य भागीदार देशों में से प्रत्येक देश के दो शोध छात्रों (रिसर्च स्कॉलर) को इब्सा विजिटिंग फेलोशिप की पेशकश कर रहा है। इस कार्यक्रम में एक प्रभावी बहुपक्षीय संस्थागत ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि सुसंगत एवं अभिन्न ढंग से समुचित तालमेल बैठाते हुए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के उन शोध छात्रों एवं शिक्षाविदों के लिए खुला है जिन्हें साझेदार देशों में इब्सा वार्ता प्रक्रिया के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पाने के लिए व्यापक शोध कार्य करने में गहन रुचि है।

ग. क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार सुविधा और कनेक्टिविटी

आर्थिक कॉरिडोर के प्रभावों का आकलन करना

प्रो. प्रबीर डे/ सुश्री ओपिंदर कौर

अध्ययन का लक्ष्य एक ऐसा आर्थिक भूगोल मॉडल विकसित करना है जिसका परीक्षण उप–राष्ट्रीय डेटा के साथ किया जाएगा और यह विकास के लिहाज से भारतीय राज्यों के लिए विशेष संदर्भ के साथ भारत में आर्थिक (परिवहन) कॉरिडोर के प्रभाव का आकलन करेगा। भारत को पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ जोड़ने वाले इन चार महत्वपूर्ण गलियारों (कॉरिडोर) का चयन किया गया है, (1) बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार (बीसीआईएम)–आर्थिक कॉरिडोर (2) ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर (स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा), (3) त्रिपक्षीय राजमार्ग और (4) कलादान मल्टीमोडल पारगमन परिवहन परियोजना।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार बढ़ाने के लिए नीतिगत और कार्यान्वयन उपाय

प्रो. राम उपेंद्र दास

पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुल सीमाओं का लगभग 98 प्रतिशत भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रूप में है, यह विशाल हिस्सा उत्तर में चीन, दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर–पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ सीमाओं को साझा करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र को हासिल विशेष स्थांन संबंधी बढ़त और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन न केवल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान), बल्कि अन्य पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भी सहयोग के लिए एक आधार के रूप में इसके विकास को पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। यही नहीं, विशेष रूप से म्यांमार के जरिए भारत की 'लुक ईस्ट' या 'एक्ट ईस्ट' नीति के एक हिस्से के रूप में आसियान के कई सदस्य देशों जैसे कि कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के साथ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को संभव बनाया जा सकता है। भारत के साथ सीमा व्यापार, जो म्यांमार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, पर विशेष ध्यान देकर भारत को न केवल म्यांमार, बल्कि भारत की व्यापक रणनीति के एक हिस्से के रूप में कंबोडिया–लाओ पीडीआर–म्यांमार–वियतनाम (सीएलएमवी) सहयोग के साथ भी इसे एकीकृत करके इस दिशा में शुरुआत की जा सकती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) ने क्षमता का दोहन करने और नीतिगत व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए आरआईएस से इस विषय पर एक अध्ययन करने का अनुरोध किया था। यह अध्ययन अंतिम चरण में है।

आसियान–भारत व्यापार में गैर–टैरिफ उपाय (एनटीएम)

प्रो. प्रबीर डे/डॉ. दुरईराज कुमारसामी

इस अध्ययन में चुनिंदा उत्पादों के मामले में आसियान में भारत के आड़े आ रही एनटीएम और भारत में आसियान के आड़े आ रही एनटीएम का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में 16 वर्गीकृत एनटीएम में शामिल एसपीएस और टीबीटी पर विचार किया गया है। अभी जारी यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही डेटा पर आधारित है।

भारत और आसियान के बीच उभरते उत्पादन नेटवर्क

प्रो. प्रबीर डे/डॉ. दुरईराज कुमारसामी

इस अध्ययन में भारत और आसियान देशों के बीच विशेषकर विनिर्माण क्षेत्रों अर्थात मशीनरी, विद्युत एवं ऑप्टिकल उत्पादों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उभरते उत्पादन नेटवर्क परिदृश्य पर करीबी नजरें दौड़ाई गई हैं। इस अध्ययन में उत्पादन नेटवर्कों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने का भी प्रयास किया गया है। विशेषकर इस अध्ययन में आसियान और भारत के बीच उत्पादन नेटवर्कों को बढ़ावा देने की खातिर कनेक्टिविटी एवं व्यापार सुविधा में निहित खामियों की पहचान की गई है और इसके साथ ही इसमें संभावित उपाय भी बताए गए हैं।

भारत–मंगोलिया आर्थिक संबंध

प्रो. प्रबीर डे/ सुश्री श्रेया पैन

यह अध्ययन मंगोलिया में भारतीय दूतावास के अनुरोध पर किया जा रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देते हुए भारत और मंगोलिया के बीच के आर्थिक संबंधों को अच्छी तरह से पेश करना है।

पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग की संभावनाएं तलाशना

डा. वी.एस. शेषाद्री

भारत और एपेक : एक मूल्यांकन' पर एक रिपोर्ट फरवरी 2015 में सरकार को प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट औपचारिक रूप से आरआईएस–फिक्की के एक संयुक्त कार्यक्रम में सचिव (पूर्व) द्वारा जारी की गई थी। भारत एवं कोरिया गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर भी एक अध्ययन शुरू किया गया था और इस बारे में रिपोर्ट 8 सितंबर 2015 को आरआईएस–एआईसी के एक कार्यक्रम में जारी की गई थी। जापान के साथ भारत के सीईपीए पर एक अध्ययन फिलहाल जारी है। इस अध्ययन में सिंगापुर और मलेशिया के साथ हुए सीईपीए पर अमल की भी समीक्षा की जा सकती है।

आरआईएस दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015

आरआईएस टीम

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015 (एसएडीसीआर 2015) ने लीक से हटकर एक नए नजरिये को अपनाते हुए दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण के बारे में लोगों की अब तक बनी सोच को एक सिरे से पलट दिया है। यह रिपोर्ट दरअसल विचारों और दृष्टिकोणों का एक आर्थिक शिखर सम्मेलन है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकताओं को 'विपरीत क्रम' में पेश किया गया है जो क्षेत्रीय समृद्धि से शुरू होकर शांति पर समाप्त होती है। इसमें व्यापक निष्पक्षता एवं नई अंतर्दृष्टि के साथ कहीं ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह शैक्षिक एवं नीति उन्मुख अध्ययनों के साथ–साथ इन अध्ययनों के लिए इस्तेमाल किए गए विशिष्ट अनुसंधान तरीकों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र ही 'सबसे कम एकीकृत क्षेत्र' नहीं है। रिपोर्ट में यह बात भी रेखांकित की गई है कि अन्य क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की सफलताओं का

महिमा मंडन करना और केवल दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण में ही खामी ढूंढ़ने के नजरिए को बदलने की जरूरत है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण के लिए की गई पहलों को अच्छी सफलता मिली है और इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय समूहों की विफल पहलों से सबक सीखने का भी जिक्र इसमें किया गया है।

एसएडीसीआर 2015 की केंद्रीय थीम अर्थात 'शांति के लिए आर्थिक एकीकरण – समृद्धि सृजित करना' भी दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के परिणामों, इस क्षेत्र में शांति हासिल करने की अनिवार्यता और दक्षिण एशिया को एक समृद्ध क्षेत्र बनाने की संभावनाओं पर गौर करने का एक नवीन तरीका है। वैसे तो शांति और समृद्धि की में समस्याओं दोनों ही दिशाओं में संभव है, लेकिन इस रिपोर्ट में समृद्धि को ही मुख्य उद्देश्य बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जिसे दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है और जिससे आगे चलकर 'शांति का माहौल' बन सकता है। इन प्रयासों के मद्देनजर यह रिपोर्ट अपने दृष्टिकोण में अनूठी है और इसकी सामग्री भी समृद्ध है, जो सार्क क्षेत्र के भीतर और इससे परे रहने वाले विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यह रिपोर्ट 25 जून 2015 को भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा जारी की गई थी।

सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए भारत की रणनीति

प्रो. राम उपेंद्र दास

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एवं वियतनाम (सीएलएमवी) क्षेत्र के बीच प्राचीन काल से ही सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत और सीएलएमवी देशों के बीच लंबे समय से लोगों, वस्तुओं, पूंजी एवं विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। हालांकि, इन संबंधों को आज अप्रयुक्त क्षमता के नजरिए से देखा जाता है। जहां एक ओर सीएलएमवी क्षेत्र और आसियान क्षेत्र के बाकी हिस्सों के बीच विकास के मामले में खाई रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट नीति में भी भारत–सीएलएमवी आर्थिक एकीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

समग्र रूप से आसियान क्षेत्र की खासियत यह है कि आसियान के भीतर एवं बाहर दोनों ही जगहों पर मजबूत उत्पादन नेटवर्क और क्षेत्रीय वैल्यू चेन (आरवीसी) मौजूद हैं। वहीं, दूसरी ओर भारत अपने पड़ोस में स्थित लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय वैल्यू चेन से बाहर है। क्षेत्रीय वैल्यू चेन ने आसियान के बाकी हिस्सों की तुलना में सीएलएमवी क्षेत्र को भी कुछ हद तक नजरअंदाज किया है।

चूंकि आरवीसी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के महत्वपूर्ण वाहनों के रूप में उभर कर सामने आई हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त नीतिगत समर्थन की जरूरत है ताकि रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और बेहतर जीवन स्तर जैसी विकासात्मक अनिवार्यताओं को हासिल किया जा सके।

इस संदर्भ में यह अध्ययन संबंधित विषय में प्रमुख योगदान के लिहाज से सीएलएमवी क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक एकीकरण के लिए विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य आधार प्रदान करता है। इसके साथ ही यह कुछ विशेष नीतिगत कदमों के बारे में सुझाव देता है जो इस रिश्ते के तहत उपलब्ध विशाल वाणिज्यिक और विकास क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। यह अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

रिपोर्ट 14 अगस्त 2015 को भारत सरकार में वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी।

डी. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

कृषि में जीवित संशोधित प्राणियों (एलएमओ) के सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देश और तौर–तरीके विकसित करना

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / प्रो. मनमोहन अग्रवाल / डॉ. रवि के. श्रीनिवास / डा. अमित कुमार

यह परियोजना जैव सुरक्षा पर यूएनईपी–जीईएफ क्षमता सृजन द्वितीय चरण प्रोजेक्ट के तहत लागू की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मॉडल प्रश्नावली तैयार करना और जीवित संशोधित प्राणियों (एलएमओ) अर्थात आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) के किफायती विश्लेषण के लिए दिशा–निर्देश एवं प्रश्नावली विकसित करना और सामाजिक–आर्थिक आकलन के लिए दिशा–निर्देशों, उपकरणों एवं प्रणालियों को विकसित करना है। भागीदार संस्थानों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; गुजरात विकास अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचूर; कृषि अनुसंधान प्रबंधन की राष्ट्रीय अकादमी, हैदराबाद; और सामाजिक–आर्थिक बदलाव के लिए संस्थान, बेंगलुरू शामिल हैं। दो वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना के वर्ष 2016 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।

प्रोग्रेसः वैश्विक जवाबदेह अनुसंधान और सामाजिक एवं वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / डॉ. रवि के. श्रीनिवास /डा. अमित कुमार

'प्रोग्रेस' वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2016 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ के एफपी–7 द्वारा प्रायोजित परियोजना है। दुनिया भर से इस परियोजना में 10 प्रोजेक्ट भागीदार हैं जिनमें भारत की ओर से आरआईएस भी शामिल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही वाले अनुसंधान और नवाचार (आरआरआई) पर एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें शिक्षाविद, एसएमई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नीति सलाहकार, अनुसंधान के लिए धन प्रदाता, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और उद्योग शामिल होंगे। यह वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक सामाजिक निकायों के साथ आरआरआई के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को जोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि सामाजिक वांछनीयता से जुड़े नवाचार पर फोकस किया जा सके, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में विज्ञान का वित्त पोषण करने वाली रणनीतियों तथा नवाचार नीतियों की तुलना करने वाले एक प्रमुख तथ्यान्वेषी मिशन को पूरा किया जा सके, विश्व स्तर पर आरआरआई के लिए एक यूरोपीय मानक मॉडल की वकालत की जा सके, सामाजिक वांछनीयता के बारे में सूचित करने के लिए एक वाहक के रूप में संवैधानिक मूल्यों का उपयोग किया जा सके और वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय नवाचार प्रणालियों में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति विकसित की जा सके। आरआईएस के लिए यह आरआरआई की उभरती अवधारणा

के तहत पहली परियोजना है। आरआईएस इस अवधारणा के साथ संलग्न होकर इसे भारत के लिए इसे प्रासंगिक बनाएगा।

समस्त एफटीए में आईपीआर और प्रस्तावित भारतीय नीति का मसौदा

प्रो. सचिन चतुर्वेदी /प्रो. टी. सी. जेम्स / डॉ. रवि के. श्रीनिवास

नए मेगा एफटीए के उद्‌भव को देखते हुए आईपीआर से संबंधित मुद्दे संभावित सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आरआईएस आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में अपना काम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएगा कि भारत ने एक नई मसौदा नीति प्रस्तुत की है, जिसमें भारत की आईपीआर नीति के बुनियादी ढांचे को बदलने का प्रस्ताव है। यहां तक कि क्षेत्रवार स्तर पर नए आईपीआर प्रावधानों के निहितार्थ विशेष रूप से स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहद ज्यादा हैं। इससे पहले आरआईएस और दक्षिण केंद्र ने साथ में मिलकर काम किया था और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया था। दक्षिण केंद्र के साथ हमारे अतीत के रिश्ते के मद्देनजर ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें दक्षिण केंद्र और आरआईएस दोनों संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। इनमें आईपी मुद्दे, दवाओं तक पहुंच, इत्यादि शामिल हैं। आरआईएस इसके अलावा व्यापार एवं सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीटीएसडी) और डब्ल्यूपीआईओ के सहयोग से भी आईपी मुद्दों पर काम करेगा। आरआईएस की टीम ने इस पर दक्षिण सेंटर, आईसीटीएसडी और डब्ल्यूपीआईओ के साथ विचार–विमर्श किया है।

आरएंडडी गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं : प्रदर्शन आधारित नवाचार पुरस्कार

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / डॉ. रवि के. श्रीनिवास / डा. अमित कुमार

'रिवार्ड' वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक की अवधि के लिए यूरोपीय संघ के एफपी–7 द्वारा प्रायोजित परियोजना है। यूकलान (ब्रिटेन) और आरआईएस इसमें परियोजना भागीदार हैं। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रणाली के पूरक के तौर पर नए क्षितिज खोलने की कोशिश करेगी। इस परियोजना के तहत महत्वाकांक्षी उत्पादन दवा संबंधी नवाचार के लिए नैतिक और कानूनी रूप से मजबूत प्रदर्शन आधारित पुरस्कार व्यवस्था है, जो मौजूदा पेटेंट व्यवस्था के पूरक के तौर पर है। यह वैश्विक गरीबों के लिए इसके व्यापक नुकसान को कम करने में मददगार है। चिकित्सा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति और जेंडर संबंधी अध्ययनों के विशेषज्ञों के साथ नीति शास्त्रियों, वकीलों, अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों के एक बहुविषयक सहयोग के तहत चयनित व्यवस्था का परीक्षण एक विकसित देश और एक विकासशील देश में किया जाएगा।

विकासशील देशों में व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास

प्रो. राम उपेंद्र दास

व्यापार और विकास के साथ–साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी के बीच के नाते एवं करणीय संबंधों का विश्लेषण अक्सर सैद्धांतिक और प्रायोगिक अन्वेषणों के एक द्विआधारी ढांचे के तहत किया जाता है। अध्ययन में एक वैचारिक ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास किया गया है, जिसकी पुष्टि व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास के बीच के

निष्क्रिय–संबंधों पर अनुभवजन्य साक्ष्य से होती है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के विकासशील देशों में नीतिगत निहितार्थों को समझना है ताकि इन देशों में विकास मोर्चे के स्थानांतरण के लिए व्यापार, प्रौद्योगिकी और विकास में समुचित तालमेल से लाभ उठाया जा सके।

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए बीज – भारत एवं अफ्रीका के बीज उद्योग में सहयोग

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / डा. अमित कुमार

यह आईडीएस के नेतृत्व वाली परियोजना है जिसमें भारत से आरआईएस, केन्या से केब, इथियोपिया से ईआईएआर और आईडीएस (ब्रिटेन) शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य गुंजाइश और मानचित्रण संबंधी अनुसंधान करना है, जिसके तहत इस प्रस्ताव पर गौर किया जा रहा है कि क्या भारतीय बीज उद्योग अफ्रीकी निकायों के सहयोग से छोटे जोत धारकों को सस्ती बीज प्रौद्योगिकी और विपणन संबंधी क्षमता मुहैया कराएगा जिससे कम कीमत पर कृषि उत्पादन में बेहतरी के जरिए गरीबी कम होगी, बशर्ते कि वित्तपोषण, क्षमता और नीति संबंधी खाई/बाधाओं को दूर कर दिया जाए। इसमें इस बात पर गौर किया जाएगा कि क्या उपलब्ध बीज प्रौद्योगिकियों से अफ्रीका में गरीब किसानों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और क्या खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी बीज प्रणालियों की उत्पादकता एवं लचीलापन बढ़ाने हेतु भारत की व्यापक बीज प्रणाली से सबक लेना संभव है, जिसमें आरएंडडी से लेकर विपणन तक शामिल हैं। इस दिशा में पड़ताल के निष्कर्षों पर हितधारक वार्ता का इस्तेमाल साझेदारियों को मजबूत बनाने और भारतीय कंपनियों के संभावित विकास प्रभाव को उत्प्रेरित करने के लिए आगे की कार्रवाई की पहचान करने में किया जाएगा।

विज्ञान कूटनीति

प्रो. सचिन चतुर्वेदी / डॉ. रवि के. श्रीनिवास / डा. अमित कुमार

विज्ञान कूटनीति अन्य विकासशील देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण बन गई है। विज्ञान कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और अन्य देशों के साथ सहभागिता की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एसएंडटी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एवं क्षमता निर्माण में अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में विज्ञान कूटनीति का इस्तेमाल किया है। रॉयल सोसायटी और विज्ञान की प्रगति के लिए अमेरिकी संघ (एएएएस) उन विज्ञान निकायों में शामिल हैं जो विज्ञान कूटनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने रिर्पोटों को प्रकाशित किया है तथा इस पर बैठकों का आयोजन किया है। विभिन्न देशों के अलावा कई राष्ट्रों के क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत की सहभागिता की व्यापक रूपरेखा और एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की उसकी आकांक्षाओं को देखते हुए विज्ञान कूटनीति भारत के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने और विकासशील देशों एवं एलडीसी के साथ सहभागिता को गहरा करने के एक साधन के रूप में विज्ञान का उपयोग करने के रणनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकती है।

एक गतिविधि और विशेष जोर वाली पहल के रूप में विज्ञान कूटनीति को नियोजन, विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसके साथ ही नीति प्रासंगिक जानकारी और एसएंडटी एवं विदेश नीति के क्षेत्र में विकास के साथ निरंतर सहभागिता की भी आवश्यकता है। एएएस ने विज्ञान कूटनीति में

तीन प्रक्रियाओं अर्थात कूटनीति में विज्ञान, विज्ञान के लिए कूटनीति और कूटनीति के लिए विज्ञान की पहचान की है। तीनों ही प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कूटनीति में विज्ञान के तहत वैज्ञानिक समुदाय से विदेश नीति निर्माताओं को जानकारी प्रदान करवाना शामिल है और इनमें एमओयूस, रणनीतिक एसएंडटी सहयोग के तहत संधियां एवं संयुक्त उपक्रम, विदेशी विकास सहायता के हिस्से के रूप में एसएंडटी कार्यक्रम शामिल हैं। विज्ञान के लिए कूटनीति में वैज्ञानिक आदान–प्रदान और वैज्ञानिक सहयोग शामिल हैं, जबकि कूटनीति के लिए विज्ञान में एसएंडटी के जरिए कूटनीति की सुविधा शामिल है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की गुंजाइश प्रदान करती है। आरआईएस में विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम इन प्रक्रियाओं को जानकारी उपलब्ध कराएगा और आर्थिक एवं विदेश नीति आधारित पहलों और इसके ठीक विपरीत स्थिति में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर एसएंडटी गतिविधियों के अपेक्षाकृत ज्यादा एकीकरण की सुविधा होगी।

प्रस्तावित कार्यक्रम विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कार्यक्रम के तहत चार प्रमुख गतिविधियां पर ध्यान दिया जाएगा : (1) बाह्य प्रवाह (2) अंतर्राष्ट्रीय आधार का सृजन (3) नेटवर्कों को विकसित करना और (4) रणनीतिक सोच। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत डीएसटी और विदेश मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श करके अन्य प्रासंगिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जाएगा। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एसएंडटी सहयोग में संलग्न विज्ञान अकादमियां भी इनमें शामिल हैं। इसके तहत आरआईएस के प्रासंगिक कार्यकलाप कार्यक्रमों और परियोजनाओं से भी लाभ उठाया जाएगा। आरआईएस ने विज्ञान कूटनीति में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के समक्ष रखा है और इसे वर्ष 2017 में शुरू किए जाने की संभावना है तथा यह आरआईएस के आईटीईसी कार्यक्रमों की तर्ज पर होगा।

जवाबदेह अनुसंधान और नवाचार– प्रैक्टिस

प्रो. सचिन चतुर्वेदी /डॉ. रवि के. श्रीनिवास / डा. अमित कुमार

आरआरआई–प्रैक्टिस (जवाबदेह अनुसंधान और नवाचार–प्रैक्टिस) तीन वर्षों (2016–2018) के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है और इसे वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में शुरू किया जाएगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया के 14 संस्थान इस परियोजना में भागीदार संस्थान हैं और आरआईएस भारत की ओर से भागीदार संस्थान है। आरआईएस 'प्रोग्रेस' परियोजना में एक भागीदार संस्थान था, जो जवाबदेह अनुसंधान और नवाचार पर तीन साल (2014–2016) की परियोजना थी और जो ईसी द्वारा वित्त पोषित थी। यह परियोजना पूरी हो चुकी है और आरआईएस ने परियोजना की बैठकों में भाग लेने के अलावा प्रदेय (डिलिवरेबल्स) को कई जानकारियां दी हैं।

आरआरआई–प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों में फैले 24 अनुसंधान संगठनों एवं अनुसंधान का वित्तपोषण करने वाले संगठनों में आरआरआई के कार्यान्वयन पर गौर करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य आरआरआई के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना, पहचान करना और बढ़ावा देना है, ताकि इसे बढ़ाकर यूरोपीय और वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके। यह परियोजना ओस्लो और एकरशस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज द्वारा समन्वित है। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2016 में ओस्लो में आयोजित एक बैठक और कार्यशाला में शुरू किया गया था।

भारतीय दवा उद्योग पर अध्ययन और ट्रिप्स व्यवस्था में दवा तक पहुंच

प्रो. टी. सी. जेम्स / सुश्री दीप्ति भाटिया

भारत ने पूरी तरह से ट्रिप्स दायित्वों को लागू किया है, जो 1 जनवरी 2005 से प्रभावी हैं। दवा उद्योग पर इसका अधिकतम प्रभाव वर्ष 1972 से लेकर वर्ष 2004 तक की अवधि में पड़ा। चूंकि भारत ने दवाओं के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट प्रदान नहीं किया था, इसलिए भारत पेटेंट वर्जन की तुलना में काफी कम कीमतों पर नवीनतम दवाओं के जेनेरिक वर्जन का उत्पादन एवं आपूर्ति करने में सक्षम था। भारतीय दवा उद्योग ने भी विनिर्माण क्षमता विकसित की और इस अवधि के दौरान उच्च वृद्धि दर हासिल की। 1 जनवरी 2005 से दवाओं के मामले में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था की शुरुआत होने पर भारतीय जेनेरिक दवा कंपनियों ने अपनी यह बढ़त गंवा दी। ट्रिप्स व्यवस्था के 10 साल की अवधि के दौरान भारतीय दवा उद्योग और दवाओं तक पहुंच पर पड़े असर का कोई भी शोध अध्ययन नहीं कराया गया है।

इस अध्ययन में विशेष रूप से यह बताया गया है कि नई बौद्धिक संपदा व्यवस्था (आईपीआर) ने किस तरह से दवा उद्योग को प्रभावित किया है और इसके साथ ही भारत एवं अन्य विकासशील देशों में किफायती दवाओं तक पहुंच भी किस तरह प्रभावित हुई है। अध्ययन के दायरे में भारतीय दवा उद्योग के इतिहास एवं विकास को इस तरह से कवर किया गया हैः (1) आजादी से पहले की अवधि से लेकर वर्ष 1972 तक; (2) वर्ष 1972 से लेकर वर्ष 2005 तक (जिस दौरान कोई उत्पाद पेटेंट नहीं था); और (3) वर्ष 2005 से लेकर वर्तमान समय तक। वर्ष 2005 के बाद इस क्षेत्र में नजर आने वाली प्रवृत्तियां, उद्योग की वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिदृश्य में भारत एवं अन्य विकासशील देशों में दवाओं तक पहुंच से जुड़े मुद्दे और दवाओं में नवाचार, जो पेटेंट के रूप में परिलक्षित होता है।

इसमें दवा उद्योग को प्रभावित करने वाले नियम–कायदों, उद्योग के विकास के आंकड़ों, दवा मूल्य के आंकड़ों, आयात–निर्यात के आंकड़ों, वर्तमान स्थिति के 'स्वोट' विश्लेषण, प्रमुख विकास संकेतकों और आगे की राह को शामिल किया गया है।

इस अध्ययन का एक उद्देश्य उन नीतिगत वक्तव्यों पर गौर करना भी है जिनका असर किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर पड़ा है। इनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, चिकित्सा उपकरण नीति, स्वास्थ्य नीति, आयुष नीति, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति, मेक इन इंडिया अभियान के साथ–साथ आयुष क्षेत्र के लिए सरकार का दृष्टिकोण शामिल हैं। भारत द्वारा अफ्रीका के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विकास सहयोग की गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अध्ययन के एक हिस्से के रूप में अपनी थोक दवा आवश्यकताओं के लिए एक ही स्रोत पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के खतरों पर एक नीतिगत संक्षिप्त नोट पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और इसे सरकार को भी सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के मसौदे पर एक अन्य नीतिगत संक्षिप्त नोट को भी पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। चिकित्सा उपकरण नीति पर एक और नीतिगत संक्षिप्त नोट को जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।

डब्ल्यूएचओ के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षणों पर अध्ययन

प्रो. टी.सी. जेम्स/सुश्री निवेदिता सक्सेना/श्री जाकिर थॉमस

स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) हस्तक्षेप के बाद भारत में क्लिनिकल ट्रायल के नियमों में हाल के वर्षों में व्यापक बदलाव देखे गए हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाव पेश करने के बाद नियमों में अनेक बदलाव किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में इन परिवर्तनों को लागू किया गया है। इन परिवर्तनों का प्रभाव अभी तक ज्ञात नहीं है।

यह अध्ययन में चिकित्सीय परीक्षण के नियमों में किए गए बदलावों और इस क्षेत्र पर उनके प्रभाव को समझाने की कोशिश करेगा। अध्ययन में जिन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा वह है : भारत में क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित कानून, स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का फैसला, संदर्भ, सामग्री और निर्देश, उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले भारत में क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित नियम–कायदे और फैसले के बाद किए गए बदलाव।

निम्नलिखित घटक इस अध्ययन के भाग हैं: क्लिनिकल ट्रायल के वर्तमान दिशा–निर्देशों का अवलोकन, विगत वर्षों के दौरान सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएसओ) में पंजीकृत कराए गए क्लिनिकल परीक्षण और उनकी संख्या, उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले एवं उसके बाद भारत में स्वीकृत क्लिनिकल परीक्षणों की संख्या पर गौर करना, नए नियम–कायदे किस तरह से काम कर रहे हैं, अस्पतालों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए एक क्षेत्र अध्ययन कराना, क्लिनिकल अनुसंधान संगठन, विशेषज्ञ और सीडीएसओ, भारतीय कानून किस हद तक अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), यूरोपीय दवा एजेंसी (ईएमए) एवं ब्रिटेन के विनियमों और आसियान देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, चिकित्सीय परीक्षण के बेहतर संचालन के सिद्धांत और भारत के दृष्टिकोण में शामिल तत्व, उपेक्षित बीमारियों के लिए एक विशेष दृष्टिकोण हेतु नियम–कायदे और कार्रवाई के लिए क्षेत्रों की पहचान।

इस अध्ययन का पहला भाग पूरा हो चुका है और समकक्ष समीक्षा रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन को पेश कर दी गई है।

II

नीतिगत शोध पत्र

भारत की विदेश नीति

- भारत की विदेश नीति की विस्तृत रूपरेखा और विशिष्ट उपायों पर एक विस्तृत नोट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पेश किया गया था।

भारत–अफ्रीका

- 'अफ्रीका के चुनिंदा देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रदान किया गया था।
- 'चुनिंदा अफ्रीकी देशों में भारत की व्यापार संभावनाएंः उत्पाद स्तरीय विश्लेषण' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को पेश किया गया था।
- 'अफ्रीका में भारत की अप्रयुक्त व्यापार क्षमता के रुझान' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुतत किया गया था।
- 'स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारत–अफ्रीका की आर्थिक एवं विकास भागीदारी, अनुभव एवं आगे की राह' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया था।

भारत–मध्य एशिया

- भारत–मध्य एशिया के आर्थिक सहयोग पर एक विस्तृत शोधपत्र, जो इसी विषय पर आरआईएस द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी के निष्कर्षों पर आंशिक रूप से आधारित था, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पेश किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा के लिए तैयारियों के एक हिस्सेर के रूप में यह नोट प्रस्तुत किया गया था।

मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली

- 'भारत पर एक संक्षिप्त परिचय (प्रोफाइल) – मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (एसआईसीए) व्यापार और निवेश संबंध' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया था।

एशिया–प्रशांत व्यापार समझौता

- 'एशिया–प्रशांत व्यापार समझौते के तहत व्यापार वार्ताओं का चौथा दौर फिर से शुरू करने' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को पेश किया गया था।

आईओआरए

- हिंद महासागर तटीय (रिम) क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के विकास का टिकाऊ प्रबंधन करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति बनाने पर एक आईओआरए कार्यशाला आयोजित करने हेतु तंजानिया द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर शोधपत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को प्रदान की गई।

भारत–ईरान

- 'ईरान में भारत की व्यापार संभावनाओं' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग को प्रदान किया गया था।

भारत–श्रीलंका

- 'श्रीलंका को भारत से निर्यात की संभावनाओं' पर एक शोधपत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग को प्रदान किया गया था।

देश–वर्गीकरण

- देशों के वर्गीकरण पर एक शोधपत्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया था।

एफटीए

- आरआईएस ने भागीदार देशों और विभिन्न क्षेत्रीय समूहों विशेषकर यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) और पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार (कोमेसा) के साथ एफटीए हेतु भारत की निरंतर जारी वार्ताओं पर विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि में शोधपत्र प्रदान किए गए।

सतत विकास के लक्ष्य

- 'उभरते भारत के लिए भागीदारी: परिवर्तन के उत्प्रेरकों के रूप में एसडीजी' पर एक संक्षिप्त सार तैयार किया गया था और फिर उसे लोकसभा सचिवालय को भेज दिया गया था। इस शोधपत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशी विकास एवं निष्पक्षता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के सामाजिक–आर्थिक और गवर्नेंस संबंधी विश्लेषण पर दृष्टिकोण शामिल हैं।

III

नीतिगत वार्ता की संवृद्धि – सम्मेलन, संगोष्ठि और कार्यशालाएँ

दक्षिणीय सहयोग सम्मेलन

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिणीय सहयोग पर नई दिल्ली में 10–11 मार्च, 2016 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

सम्मेलन की शुरुआत में प्रसिद्ध विद्वानों और विशेषज्ञों ने बताया कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय विकासपरक माहौल में दक्षिणीय सहयोग की अहमियत किस तरह बढ़ रही है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री एस टी देवारे, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय की ओर से की गई जो आरआईएस की रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं एवं सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे में इंटरनेशनल स्टडीज के चेयर राम साठे, ने निवेश और विकास संबंधी सहयोग में इस क्षेत्र के आंतरिक व्यापार में हो रही बढ़ोतरी पर ध्यान दिलाया। श्री देवारे ने कहा कि दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा

सुश्री सुजाता मेहता, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य भाषण देती हुई। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. ली शियाओयुन, श्री युरी अफानासिएव, श्री जाओकिम रैटर, श्री एस.टी. देवारे, श्री वु होंगबो, प्रो. अनुराधा शिनॉय एवं श्री अरुण कुमार साहु।

देना आरआईएस के शोध कार्यक्रम का केंद्र बिंदु रहा है और यह सम्मेलन उस दिशा में एक अहम कदम है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने अपने मुख्य भाषण में दक्षिण के तेजी से हो रहे उदय के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आर्थिक चहल–पहल और उद्यमिता का केंद्र साउथ ही बन गया है। उन्होंने ध्यान दिलाया, इंट्रा साउथ कारोबार, निवेश और विकास संबंधी सहयोग में काफी गंभीर बढ़ोतरी आई है। विश्व के विकास से जुड़े मौजूदा माहौल का अंदाजा इस क्षेत्र से लगाया जा सकता है। वैश्विक विकास में सहयोग के लहाज ससाउथ ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है।

डॉ. एस. जयशंकर
विदेश सचिव,
भारत सरकार

आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में दक्षिणीय सहयोग से जुड़े सीमा संबंधी मुद्दों को सही संदर्भ में रखते हुए कहा, दक्षिणीय सहयोग पर सम्मेलन उत्तर–दक्षिण सहयोग के बदलते माहौल की पृष्ठभूमि और दक्षिणीय सहयोग के नए केंद्र के विकसित होने के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका खास संदर्भ यह है कि दक्षिण अर्थव्यवस्था के नए केंद्र के तौर पर विकसित हो रहा है। दक्षिण की अर्थव्यवस्थाएं जिस उथल–पुथल से गुजर रही हैं, उसे देखते हुए यह खास तौर पर और महत्वपूर्ण हो जाता है। यूएन के रजिडेंट कोर्डिनेटर और यूएनडीपी के भारत में रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव श्री यूरी एफैनैसिएव ने इस सम्मेलन को ऐसे उपयुक्त समय में करवाने के लिए आइआईएस की तारीफ की जब दुनिया दक्षिणीय सहयोग में हो रहे विकास का गवाह बन रहा है और जब सतत विकास लक्ष्यों का वैश्विक मुद्दा पेश किया जा रहा है। चाइना इंटरनेशल डेलपमेंट रिसर्च नेटवर्क इस अवसर पर (सीआईडीआरएन) के चेयर श्री ली जिवाउयुआन ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा, 1980 के दशक की शुरुआत के साथ दुनिया दक्षिण के संगठित विकास की गवाह बनी है। युनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर के अंडर सेक्रेटरी जेनरल श्री वु हांगबू ने अपने विशेष भाषण में खास तौर पर जोर दिया कि यह सम्मेलन एक समयानुकूल प्रयास है क्योंकि 2030 के एजेंडे में सभी देशों के बीच साझेदारी पर जोर दिया गया है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशल स्टडीज की डीन और एफआईडीसी की चेयरपरसन प्रो. अनुराधा शीनॉय ने दुहराया कि दक्षिणीय सहयोग उत्तर–दक्षिण सहयोग से अलग है क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें लोगों को गरीबी से और सभी तरह की असुरक्षा से बाहर निकालने पर जोर है।

श्री जयंत प्रसाद
महानिदेशक, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली

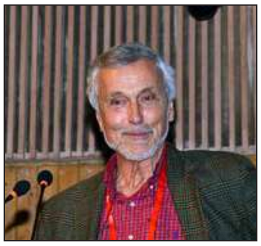

श्री ब्रैनिस्लाव गोसोविक
एसएससी पर विख्यात विशेषज्ञ, जेनेवा

यूएनसीटीएडी, जिनीवा के डिप्टी सेक्रेटरी जेनरल श्री जोकिम रीटर ने अपने विशेष संबोधन में तेजी से बढ़ते दक्षिण की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि दक्षिण–दक्षिण में कारोबार 1990 के दशक के छह फीसदी के मुकाबले बढ़ कर 25 फीसदी हो गया है और यह दक्षिण–दक्षिण निवेश में वृद्धि को भी दर्शाता है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और दक्षिण–दक्षिण सम्मेलन के संयोजक श्री अरुण कुमार साहू ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

इस मौके पर आरआईएस ने दक्षिणीय सहयोग के विभिन्न आयामों को समाहित करने वाले दो महत्वपूर्ण प्रकाशन भी जारी किए। आरआईएस कोर टीम की ओर से तैयार इन प्रकाशनों का शीर्षक है– ''साउथ–साउथ कॉपरेशन – मैपिंग न्यू फ्रंटियर्स और रिसर्जिंग साउथ– स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स''।

श्री जोआकिम रीतर
उपमहानिदेशक, अंकटाड, जेनेवा

सम्मेलन का उदेश्य दक्षिणीय सहयोग को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संदर्भ में समाहित करना था। इसलिए पहला पूर्णाधिवेशन सत्र वैश्विक न्याय के विचार से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार करने के लिए था। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट,

नई दिल्ली के प्रेसिडेंट प्रो. मुचकुंद दुबे ने सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के वक्ताओं में यूएनसीटीएडी, जिनीवा के डिप्टी सेक्रेटरी जेनरल श्री जोकिम रीटर; येल यूनिवर्सिटी, न्यू हेवन के ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम के निदेशक प्रो. थॉमस पॉगे; और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अर्थशास्त्र के मानद प्राध्यापक प्रो. दीपक नैयर शामिल थे।

दूसरा पूर्णाधिवेशन सत्र ग्लोबल एड आर्किटेक्चर, दक्षिणीय सहयोग और ट्राएंगलर डेवलपरमेंट कॉपरेशन पर था। इसमें उत्तर की ओर से की जाने वाली मदद के पारंपरिक सांस्थानिक ढांचे और दक्षिणीय सहयोग की रणीतियों के तहत अपनाए जा रहे विभिन्न तरीकों पर गौर किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता एंबेस्डर अशोक मुखर्जी ने की जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। यूएन– ईएससीएपी, नई दिल्ली के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया ऑफिस के प्रमुख डॉ. नागेश कुमार; इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोम के पूर्व एफएओ असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉ. जोमो क्वामे सुंदरम; और साउथ सेंटर, जेनेवा के डॉ. मैनुअल मोंटेस वक्ता थे।

डॉ. नागेश कुमार
प्रमुख, दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय, यूएन–एस्कैप, नई दिल्ली

तीसरे पूर्णाधिवेशन सत्र में दक्षिण के विकास के परामर्श और दक्षिण के थिंक टैंकों की भूमिका पर चर्चा हुई। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग, ढाका के डिस्टिंग्युस्ड फेलो डॉ. देवप्रिय भट्टाचार्य ने इस सत्र की अध्यक्षता की। साउथ सेंटर, जेनेवा के डॉ. विसेंटे यू; सीआईडीआरएन, बीजिंग के चेयर प्रो. ली जियाउयुन; इंस्टीच्यटो डे पेसक्यूसा इकनॉमिका एप्लीकाडा (आईपीईए); रीयो से डॉ. एंड्रे डे मेलो ई सूजा; साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एसएआइआइए), जोहानेसबर्ग के निदेशक प्रो. एलीजाबेथ सिड्रोपाउलोस; थिंक टैंक इनीशिएटिव, आईडीआरसी, नई दिल्ली के सीनियर प्रोग्राम ऑफीसर डॉ. समर वर्मा; ओईसीडी, पेरिस के डीएसी चेयर श्री एरिक सोलिएम; और प्रो. सचिन चतुर्वेदी वक्ताओं में शामिल थे।

श्री विसेंटे यु
साउथ सेंटर, जेनेवा

दक्षिणीय सहयोग सभी के लिए एक ही समाधान को सही मानने के सिद्धांत पर काम नहीं करता। इसलिए चौथे पूर्णाधिवेशन सत्र में अफ्रीका, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और दक्षिण–पूर्व एशिया के दक्षिणीय सहयोग के क्षेत्रीय अनुभवों को साझा किया गया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। जीडीआई बोन के डॉ. थॉमस फ्यूज इसके सह अध्यक्ष थे। एशिया फाउंडेशन, क्वालालंपुर से डॉ. एंथिया मुलाकला; संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणीय सहयोग कार्यालय; न्यूयॉर्क के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री फांसिस्को सिपलीसियो; इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल डायलॉग, केप टाउन की सुश्री सनूशा नायडू; पीआईएफसीएसएस, सैनसैल्वाडोर से श्री एडगर एलजैंडो ह्यूजो; और विदेश मंत्रालय, कंपाला के श्री जेम्स बिचाची वाफूला इस चर्चा में शामिल थे।

पांचवे पूर्णाधिवेशन सत्र में दक्षिणीय सहयोग में सीएसओ और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर चर्चा हुई। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव, (आर्थिक संबंध) श्री अमर सिन्हा ने सत्र की अध्यक्षता की। पीआरआईए के अध्यक्ष डॉ. राजेश टंडन इस के सह अध्यक्ष थे। टाटा सस्टेनेबलिटी ग्रुप, नई दिल्ली के श्री शंकर वेंकटेश्वरन; भारती एयरटेल, नई दिल्ली की सुश्री विनीता सेठी; ब्रिक्स पॉलिसी सेंटर, रीयो के डॉ. पाउलो लुई; मोरोक्स लेविग्ने एस्टीवसय सार्क डेवलपमेंट फंड, थिपू के सीईओ डॉ. सुनील मोटवानी; यूएनवी के एशिया और पैसिफिक कार्यालय, बैंकॉक के रिजनल मैनेजर डॉ. मेनन बार्नियर; और वोलंट्री एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी), नई दिल्ली के श्री हर्ष जेटली इसमें वक्ता थे।

श्री अमर सिन्हा
सचिव, (ईआर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

इन पूर्णाधिवेशन सत्रों के अलावा इस सम्मेलन के दौरान चार समानंतर सत्र भी आयोजित किए गए। श्री अरुण साहू ने जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबलिटी और फाइनांसिग फॉर डेवलपमेंट पर समानांतर सत्र 1ए की अध्यक्षता की। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. स्वर्ण सिंह इसके सह–अध्यक्ष थे। साउथ सेंटर, जेनेवा

प्रो. वेनपिंग हीं
एकेडमी ऑफ सोशल साईंसेज, बीजिंग

प्रो. एस. के. मोहंती
आरआईएस

श्री आलोक ए. डिमरी
संयुक्त सचिव (एमईआर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

के डॉ. विंसेट यू; ऑक्सफैम इंडिया, नई दिल्ली की सुश्री निशा अग्रवाल; जेएनयू के प्रो. स्वर्ण सिंह; इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, कोलंबो में पर्यावरण अर्थशास्त्र के प्रमुख डॉ. अतुल सेनारत्ने; और गेटवे हाउस, मुंबई की सीनियर फेलो डॉ. रजनी बख्शी पैनलिस्ट के तौर पर इस चर्चा में शामिल रहे।

जेएनयू के प्रो. गुलशन सचदेवा और चाइनिज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, बीजिंग के प्रो. वेनपिंग हे ने समानांतर सत्र 1बी की अध्यक्षता की जो एसलएससी और क्षेत्रीय विकास : अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063 पर था। आईडीएसए की सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. रुचिता बेरी; दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी अध्ययन विभाग के प्रमुख प्रो. सुरेश कुमार; एएफआरओडीएडी, हरारे के कार्यकारी निदेशक डॉ. फेनवेल केनाला बोकोसी; साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, जोहानेसबर्ग के श्री निशान बेशाराती; और मुंबई विश्विद्यालय की सुश्री रेणु मोदी इसमें वक्ताओं के तौर पर शामिल थे।

डब्लूएचओ, नई दिल्ली के भारत प्रितिनिधि डॉ. हेंक बेकडम और आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. टी सी जेम्स ने समानांतर सत्र १ सी की अध्यक्षता की जो स्वास्थ्य पर था। टोरंटो विश्वविद्यालय के एडजंक्ट प्रोफेसर डॉ. हल्ला थोर्सटेंसडॉटिर; मोरा इंस्टीट्यूट, मैक्सिको सिटी के डॉ. जार्ज ए परेज पिंडा; यूएनएएम, मैक्सिको सिटी की सुश्री ओरनेला गैरेली रियोस; नेपाल नेत्र ज्योति संघ, काठमांडू के अध्यक्ष प्रो. तीर्थ प्रसाद मिश्रा और ओआरएफ, नई दिल्ली व जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, सोनीपत की फेलो डॉ. उर्वशी अनेजा इस चर्चा में शामिल रहे।

डॉ. नागेश कुमार और कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रो. राधारमण चक्रवर्ती ने समानांतर सत्र 2ए की अध्यक्षता की। यह दक्षिणीय सहयोग के थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क पर केंद्रित था। आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती; जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता के प्रो. सैकत सिन्हा रॉय; जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, सोनीपत के डीन डॉ. श्रीराम चौलिया; कंबोडिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई), नोम पेन्ह के श्री लैरी स्ट्रेंज; और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और ईएनएपी, ब्रासीलिया के डॉ. माइकल मॉरिस डिलिस्वा वक्ताओं के तौर पर शामिल थे।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (एमईआर) श्री आलोक ए डिमरी और जेएनयू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अर्चना नेगी ने समानांतर सत्र 2बी की अध्यक्षता की। यह ईसीओएसओसी/डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फोरम (डीसीएफ) की भमिका पर था। यूएनडीईएसए, न्यूयॉर्क के ऑफिस ऑफ ईसीओएसओसी सपोर्ट एंड कोर्डिनेशन के निदेशक श्री नाविद हनीफ; साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (एसएआईआईए), जोहानेसबर्ग से प्रो. एलिजाबेथ सिड्रोपोलिस; जीडीआई, बॉन के डॉ. थॉमस फ्यूस; और चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीजिंग से प्रो. वांग यीहुआन ने इसमें अपने विचार रखे।

एफएओ के भारत प्रतिनिधि श्री श्याम खड़के और श्वाने यूनिवर्सिटी, प्रटोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकॉमिक रिसर्च ऑन इनोवेशन से प्रो. रसिगन महराज ने समानांतर सत्र 2सी की अध्यक्षता की। यह सत्र एसएंडटी, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर था। ईएमबीआरएपीए, ब्रासीलिया से डॉ जोस बेलीनी; आईआरएमए, आनंद से डॉ. एच एस शैलेंद्र; एबीएनई– एनईपीएडी और यूनिवर्सिटी ऑफ वागाडोंगू से प्रो. डीरन मकिंडे; जेएनयू से प्रो. प्रणब देसाई; और आंध्र विश्वविद्यालय, वाईजैग से डॉ. अलूरी वेंकट नागवर्ण इसमें वक्ता के तौर पर शामिल थे।

इवैल्यूएशन मैथडॉलॉजी और एकाउंटिंग पर आयोजित समानांतर सत्र ३ए की अध्यक्षता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड प़ॉलिसी (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली के निदेशक डॉ. रतिन रॉय और आरआईएस के प्रो. एस के मोहंती ने

डॉ. रथिन रॉय
निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली

प्रो. थॉमस पोग
डायरेक्टर, ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम, याले यूनिवर्सिटी, न्यू हैवेन

प्रो. सईद मुनीर खसरु
द इंस्टीच्युट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी एंड गर्वेनेंस, ढाका

सुश्री नरगिजा एलिमकुलोवा
इंटरनेशनल एतातुर्क अलाटू यूनिवर्सिटी, बिशकेक

की। एसईजीआईबी, मैड्रिड से प्रो. सिल्विया लोपेज; आरआईएस, नई दिल्ली और शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के विजिटिंग फेलो प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती; इंस्टीट्यूटो डे पेस्क्यूसा इनकोमिका एप्लीकाडा (आईपीईए), रीयो से डॉ. एंड्रे डी मेलो डिसूजा; साउथ–साउथ एंड ट्राइंगुलर कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक युनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैंकाक से डॉ. नान ली कलिंस; और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से डॉ. प्रणय सिन्हा इसमें वक्ता थे।

येल यूनिवर्सिटी, न्यू हैवन के ग्लोबल जिस्टस प्रोग्राम के निदेशक प्रो. थॉमस पॉगे और ग्रफिथ यूनिवर्सिटी, ब्रिसबेन के डॉ. लूइस कारबेरा ने समानांतर सत्र ३ बी की अध्यक्षता की। यह सत्र दक्षिणीय सहयोग और वन वर्ल्ड ग्लोबल सिटीजनशिप पर था। सेवा मंदिर, उदयपुर के अजय मेहता; स्पीकिंग ट्री, नई दिल्ली की संपादक सुश्री नारायणी गणेश; डब्लूएफएम/इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पॉलिसी के ग्लोबल ईसी के सदस्य और यूएनपीए कैंपेन, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. डब्लू जेम्स अपुतराज; द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी एंड गवर्नेंस, ढाका के प्रो. सैयद मुनीर खसरू; और यूनवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, बर्मिंघम के श्री चंद्रचूर सिंह वक्ता के तौर पर शामिल हुए।

दक्षिणीय सहयोग ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट डायनमिक्स पर आयोजित समानांतर सत्र ३ सी की अध्यक्षता आईसीआरआईईआर में प्रोफेसर डॉ. निशा तनेजा और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेंद्रम के प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल ने की। प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस; प्रो. शाहिद अहमद, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; यंगून यूनिवर्सिटी ऑफ इकनोमिक्स से प्रो. चो चो थिन; और टेरी, नई दिल्ली से सुश्री स्वाती गणेशन ने इस चर्चा में भाग लिया।

इस दौरान यंग स्कॉलर्स फोरम ऑन दक्षिणीय सहयोग पर आयोजित समानांतर सत्र ४ ए की अध्यक्षता आईडीएसए, नई दिल्ली की सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. रुचिता बेरी ने की। विदेश मंत्रालय, एडिस अबाबा से सुश्री रेडिएट डेलिल्गन; द पांडिया कोलेगरस इंस्टीट्यूट, रक्षा मंत्रालय, ब्रासीलिया से श्री कार्लोस ई टीमो ब्रीटो; नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एवलेंडा, ब्यूनोस एयर्स से सुश्री लेटीसिया एस्टेवेज; इंटरनेशनल अतातुर्क अलाटू यूनिवर्सिटी, बिशकेक से सुश्री नरगीजा एलिमकुलोवा; मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के डॉ. एस बी यादव; शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के पीएचडी छात्र श्री सैदू नसीरू सुलेमान; इंटरनेशनल अतातुर्क अलाटू यूनिवर्सिटी, बिशकेक के अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख डॉ. किलबेक अकमलदोएव; फोन टू वोट के श्री ए. कृष्ण प्रसाद; और मोरा इंस्टीट्यूट, मैक्सिको सिटी की सुश्री लॉरा करीना गुटिएरेज मतामोरोस ने इसमें वक्ता के तौर पर भाग लिया।

फ्रिडरिक एलेक्टेंजर यूनिवर्सिटी, एरलैंगेन डॉ. थॉमस मुहर और सिबायोसिस स्कूल ऑफ इकनोमिक्स, पुणे की निदेशक डॉ. ज्योति चांदीरमानी ने समानांतर सत्र ४ बी की अध्यक्षता की जो शिक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग पर था। एएमईएक्ससीआइडी, मैक्सिको सिटी में सीनियर एडवाइजर प्रो. गेरार्डो बराचो; ब्राजीलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रासीलिया की सुश्री करीना कोस्टा वावक्वेज; यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा डे प्यूबला, मैक्सिको सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जुआन पाब्लो प्राडो लालेंडे; यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी, नैरोबी के प्रो. फिलिप ओ नियांगुरो; और शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा के कुलपति डॉ. विजय गुप्ता इसमें वक्ता थे।

आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. मनमोहन अग्रवाल और प्रो. एसएस परमार ने समानांतर सत्र 4 सी की अध्यक्षता की जो साउथ साउथ कॉपरेशन में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी पर था। केपीएमजी के श्री नीलांचल मिश्रा; अर्नस्ट एंड यंग, नई दिल्ली के पार्टनर अभय अग्रवाल; सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, सियोल के डॉ. ताइक्यूम किम; डीएफआईडी इंडिया के ग्लोबल पार्टनरशिप की प्रमुख सुश्री तमर बेलो; यूएन ऑफिस

प्रो. मनमोहन अग्रवाल
विकास अध्ययन केंद्र, त्रिवेंद्रम

ऑन साउथ साउथ कॉपरेशन, न्यूयॉर्क के श्री डेनिस नकाला ने इस चर्चा में भाग लिया।

इन सभी समानांतर सत्रों के दौरान हुई चर्चा को रिपोर्ट के तौर पर एक विशेष सत्र मे पेश किया गया जिसका शीर्षक था वे फोरवार्ड। जेनेवा के दक्षिणीय सहयोग के प्रख्यात विशेषज्ञ श्री ब्रानिस्लाव गोसोविक और एसएआईआईए, जोहानेसबर्ग से प्रो. एलिजाबेथ सिड्रोपॉलस ने इस सत्र की अध्यक्षता की।

भारत के विदेश सचिव डॉ. एस जयशंकर ने समापन संबोधन दिया। समापन सत्र की अध्यक्षता आईडीएसए के महा निदेशक एंबेस्डर जयंत प्रसाद ने की। आरआईएस के वायस अध्यक्ष श्री वीएस शेषाद्री ने विशेष संबोधन किया। जेनेवा के दक्षिणीय सहयोग के विशेषज्ञ श्री ब्रानिस्लाव गोसोविक ने भी विशेष संबोधन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सम्मेलन के दौरान विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सप्तवर्ण का भी आयोजित किया गया। सुश्री अरुणा मोहंती के निर्देशन में आयोजित यह कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सात रंगों पर आधारित था। इस दौरान भारतीय विशेषज्ञों, शोधार्थियों, विषयों के विशेषज्ञों, सरकार के ऊच्च पदों पर मौजूद अधिकारियों, अकादमिक क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के अलावा विदेशों से सौ से ज्यादा प्रख्यात वक्ताओं ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

नेस्ट

सम्मेलन के दौरान साउथ के प्रमुख थिंक टैंकों को साथ लाने के लिए नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक टैंक्स (नेस्ट) की भी शुरुआत की गई। नेस्ट दक्षिणीय देशों के बीच ज्ञान और सूचना के सेतु के तौर पर काम करेगा ताकि विकास से जुड़े एक जैसे अनुभवों के साथ ही सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को भी साझा कर सकें।

दक्षिणीय सहयोग पर प्रदर्शनी

दो दिन के सम्मेलन के दौरान दक्षिणीय सहयोग पर श्री एस टी देवारे ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान वरिष्ठ कूटनीतिक, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और दुनिया भर के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में 38 सरकारी,

(दायें से) : संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विभाग के अवर महानिदेशक श्री वु होंगबो एसएससी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए। चित्र में सुश्री सुजाता मेहता, श्री एस.टी. देवारे एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं।

प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अपने ऐसे उत्पाद और मुख्य क्षमताओं को प्रदर्शित किया जो दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

भारत–अफ्रीका साझेदारीः भविष्य की दिशा

25 से 29 अक्तूबर, 2015 को होने वाले तीसरे भारत– अफ्रीका फोरम सम्मेलन के पहले इसकी तैयारी के तौर पर आरआईएस ने इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनायलसिस (आईडीएसए), ब्रूकिंग्स इंडिया और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिल कर 'भारत–दक्षिण अफ्रीका साझेदारी : भविष्य की दिशा' विषय पर नई दिल्ली में 20 अक्टूबर, 2015 को एक परिचर्चा आयोजित की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (एम एंड ईआर) सुश्री सुजाता मेहता ने इस दौरान विशेष भाषण दिया। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इथियोपिया के भारत में राजदूत और अफ्रीकन डिप्लोमेटिक कोर के डीन महामहिम डॉ. गेनेट जेविड ने मुख्य भाषण दिया। आईडीएसए के महा निदेशक एंबेस्डर जयंत प्रसाद ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। ब्रूकिंग्स इंडिया के सीनियर फेलो और डायरेक्टर रिसर्च डॉ. सुबीर गोकरण; विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डीपीए–2) श्री अरुण कुमार साहू; सीआईआई के इंटरनेशनल पॉलिसी एंड ट्रेड के हेड श्री पवन कुमार; सीनियर रिसर्च एसोसिएट; कोर्डिनेटर अफ्रीका, यूएन, एलएसी सेंटर; और आईडीएसए की डॉ. रुचिता बेरी ने धन्यवाद पेश किया।

सुश्री सुजाता मेहता ने ध्यान दिलाया कि अफ्रीकी साझेदारों की इच्छा के मुताबिक भारत विकास सहयोग की प्रक्रिया में शामिल हो गया है। यह साझेदारी गैर हस्तक्षेप, संप्रभुता के सम्मान, बराबरी और साझेदारी की भावना पर आधारित है ना ही दानकर्ता और दान लेने वाले के संबंध पर। अफ्रीका के 41 देशों की 137 परियोजनाओं के लिए भारत ने 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम मुहैया करवाई है।

उन्होंने भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग का एक नया ढांचा विकसित करना है। इसमें अफ्रीका के साथ क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय और दोतरफा स्तर पर सहयोग का एक बेहद अहम ढ़ाचा खड़ा किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विकास से जुड़ा सहयोग इस संबंध में स्वभाविक तौर पर बहुत मददगार साबित होता

भारत में फेडेरल डेमोक्रैटिक रिपब्लिक इथोपिया के राजदूत एवं अफ्रीकन डिप्लोमैटिक कॉर्प्स के डीन महामहिम डा. जेनेट जेवाइड कंसलटेशन में मुख्य भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डा. सुबीर गोकर्ण, सुश्री सुजाता मेहता एवं श्री जयंत प्रसाद भी दिखाई दे रहे हैं।

है। आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिहाज से भारत के अफ्रीका में चल रहे तकनीकी सहयोग और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम बहुत अहम हैं। पिछले तीन साल के दौरान लगभग 25000 स्कॉलरशिप प्रदान की गई हैं।

महामहिम डॉ. गेनेट जेविड ने कहा कि अफ्रीका की जीडीपी में 5.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ोतरी हो ही रही है। यहां प्रचूर संभावनाएं भी उपलब्ध हैं। इस वजह से यह तेजी से आगे बढ़ते क्षेत्र के रूप में उदित हो रहा है और भारत सहित विभिन्न देश इसके साथ आर्थिक सहयोग के लिए तत्पर हैं। भारत का अफ्रीका के साथ संबंध हाल के समय में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि सदियों पुराना है। यह साझा सम्मान और लाभ के सिद्धांत पर आधारित है और सच्ची साझेदारी और एकजुटता के आधार पर खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा, 'भारत हमारी समस्याओं के लिए कोई दवा नहीं बताता। मानव संसाधन विकसित करने में सहयोग के लिहाज से भारत ने सभी दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया है।'

एंबेस्डर जयंत प्रसाद ने कहा, दुनिया बदल गई है और भारत व अफ्रीका भी। साथ ही उन्होंने कहा, जहां 19वीं शताब्दी में यूरोप का बोलबाला था, 20वीं शताब्दी में अमेरिका की अहमियत रही मगर 21वीं शताब्दी एशिया और अफ्रीका की है। भारत के अफ्रीका के साथ भविष्य की साझदारी के बारे में उन्होंने कहा कि पहला क्षेत्र तो खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी सहयोग है, लेकिन इसके बाद ऊर्जा और आईसीटी में साझेदारी बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि संस्थान खड़े करना, मानव संसाधन का विकास करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास के इसी तरह के कार्यक्रम सहयोग के अगले क्षेत्र हो सकते हैं।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन में जिन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है, यह परिचर्चा उनकी पहचान कर उन पर आगे बढ़ने का रास्ता तैयार कर सकती है। चूंकि भारत और अफ्रीका के बीच साझेदारी के व्यापक क्षेत्र हैं, यह सम्मेलन भारत के विकास एजेंडा को एक दिशा दे सकेगा।

इस मौके पर सुश्री सुजाता मेहता ने तीन विशेष प्रकाशन भी लांच किए– आरआईएस का 'इंडिया अफ्रीका पार्टनर्शिप टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट'; आईडीएसए का 'इंडिया अफ्रीकाः कॉमन सेक्यूरिटी चौलेंजेज फॉर द नेक्स्ट डिकेड'; और ब्रूकिंग्स का 'इंडिया अफ्रीकाः फोर्जिंग ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप' शामिल है।

इस परिचर्चा के दौरान तीन सत्र आयोजित हुए– 'जियो स्टेरेटजिक लिंकेजेज एंड इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप', 'ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट' और 'सेक्टोरल पर्सपेक्टिव'।

विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना ने समापन भाषण दिया। समापन सत्र के दौरान एंबेस्डर जयंत प्रसाद, प्रो. सचिन चतुर्वेदी और डॉ. सुबीर गोकरण की ओर से भी संबोधन किए गए। श्री प्रणव कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

भारत–अफ्रीका साझेदारी पर राष्ट्रीय परामर्श

तीसरे भारत– अफ्रीका फोरम सम्मेलन से पहले आरआईएस ने इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनायलसिस (आईडीएसए), ब्रूकिंग्स इंडिया और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिल कर 'भारत–दक्षिण अफ्रीका साझेदारी : प्राथमिकताएं और संभावनाएं' विषय पर 16 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना को भारत–अफ्रीका फोरम समिट के लिए शानदार लोगो तैयार करवाने

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सिंह सरना 'भारत अफ्रीका साझीदारी पर राष्ट्रीय परामर्श : प्राथमिकताएं एवं संभावनाएं को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; श्री राजीव भाटिया; सुश्री रुचिता बेरी; एवं डा. डब्ल्यूपीएस सिद्धु भी दिखाई दे रहे हैं।

की बधाई दी। उन्होंन कहा कि यह बीते इतिहास के साथ ही भविष्य के विचारों को भी प्रदर्शित करता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना सचिव ने उद्घाटन भाषण दिया। एंबेस्डर राजीव भाटिया ने मुख्य भाषण दिया। ब्रूकिंग्स इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर फेलो डॉ. डब्लू.पी.एस सिंधू और सीआईआई के इंटरनेशनल पॉलिसी एंड ट्रेड के हेड श्री पवन कुमार ने भी इसे संबोधित किया। इस मौके पर सीनियर रिसर्च एसोसिएट और कोर्डिनेटर अफ्रीका, यूएन, एलएसी सेंटर, आईडीएसए डॉ. रुचिता बेरी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

इसके विभिन्न सत्रों के दौरान इन विषयों पर चर्चा हुईं – (i) भारत अफ्रीका साझेदारी और वैश्विक संदर्भ; (ii) व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दे; (iii) ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा; और (iv) जनता के आपसी संबंधः शिक्षा, सिविल सोसाइटी और सामाजिक क्षेत्र।

भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत और अफ्रीका के बीच पुरातन संबंधों को दुबारा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। भारत और अफ्रीका के बीच दोस्ती और विकास में सहयोग का बहुत पुराना इतिहास है। हमारे संबंध निश्चित तौर पर विकास की आधुनिक साझेदारी को ही प्रदर्शित करते हैं जो साझा जवाबदेही और एक–दूसरे को विकास संबंधी लक्ष्य हासिल करने में मदद के सिद्धांत पर आधारित है।

भारत–अफ्रीका के बीच सहयोग पर विमर्श में आरआईएस विभिन्न भाषणों, चर्चाओं और प्रकाशनों के जरिए लगातार सक्रिय रूप से सहयोग करता रहा है। 2015 की शुरुआत में आरआईएस ने कृषि की नई तकनीक पर भारत–अफ्रीका साझेदारी विषय पर नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया था। यह सम्मेलन इसी दिशा में एक कदम था।

भारत सरकार विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सरना ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह परामर्श पांच हफ्ते बाद होने वाले भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन का शुरुआती कार्यक्रम है। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि इस परामर्श के दौरान व्यापार, निवेश और विकास; ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा; तथा शिक्षा, सिविल सोसाइटी और सामाजिक क्षेत्र में जनता के आपसी संबंधों को ले कर कुछ अहम बिंदु सामने आ सकेंगे और उनका लाभ फोरम सम्मेलन के दौरान मिल सकेगा। मौजूदा वैश्विक संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत और अफ्रीका के संबंध और प्रगाढ़ हों। चूंकि दोनों क्षेत्र में व्यापक पूरकताये है, एक–दूसरे के पूरक

हैं, उसे देखते हुए भारत और अफ्रीका के बीच कृषि, खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा आदि विषयों पर सहयोग को संगठित रूप से विस्तार देने की काफी संभावनाएं हैं।

यह परामर्श भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ई एंड एसए) श्री तन्मय लाल की अध्यक्षता में हुए समापन सत्र के साथ समाप्त हुआ। डॉ. रुचिता बेरी ने परामर्श के दौराना हुई चर्चा पर रिपोर्ट पेश की। महामहिम एंबेस्डर डॉ. हसन ए. एल तलीब, रिपब्लिक ऑफ सूडान के श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव के नॉन रेजिडेंट राजदूत; आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और सीआईआई के अंतर्राष्ट्रीय नीति और व्यापार के प्रमुख श्री प्रणव कुमार ने भी इसे संबोधित किया। ब्रूकिंग्स इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर फेलो डॉ. डब्लूपीएस सिंधू ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

लाइबेरिया की राष्ट्रपति आरआईएस में

एफआईडीसी–आरआईएस ने 'भारत अफ्रीका साझेदारी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल' पर रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया के राष्ट्रपति महामहिम मदम एलेन जॉनसन सरलिफ का विशेष संबोधन नई दिल्ली में 31 अक्तूबर, 2015 को आयोजित किया। इस अवसर पर आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया।

लाईबेरिया की राष्ट्रपति महामहिम मैडम एलेन जॉनसन सरलीफ भाषण देती हुई।

राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करते हुए कहा प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कि वे राष्ट्रपति सरलिफ की यहां मौजूदगी से बेहद प्रसन्न हैं, जिन्होंने पहले एमडीजी और अब एसडीजी को ले कर बौद्धिक और नीतिगत नेतृत्व प्रदान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि आरआईएस और भारत में स्थित यूएन कार्यालय ने एक विशाल शोध कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें जन प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, अकादमिक जगत के लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) पर विमर्श किया जाएगा और इसे लागू करने की रणनीति भी तलाशी जाएगी।

राष्ट्रपति सरलिफ ने अपने विशेष भाषण में कहा कि उभरते अफ्रीका की पहचान आर्थिक विकास, सामाजिक पैमानों पर हो रहे तेज बदलाव और महत्वाकांक्षी व मुकाबले को तैयार युवा आबादी से होती है। भारत के साथ इसकी विकासपरक साझेदारी के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जोर दिया कि हमें इस साझेदारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अफ्रीका को व्यापार, निवेश, क्षमता विकास और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के बारे में दिए गए ठोस आश्वासन की तारीफ की। उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच शिक्षा

और कृषि क्रांति में साझेदारी की जरूरत पर खास तौर पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में एसडीजी के तीन सह–अध्यक्षों में से एक होने के नाते उन्होंने एसडीजी को अंगीकार किए जाने को ले कर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसडीजी को अमल में लाना अपेक्षाकृत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए व्यापक स्तर पर मानवीय और वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। एसडीजी के तहत दुनिया भर के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी पहलुओं का ध्यान रखते हुए विकास के 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य तय किए गए हैं। एसडीजी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थागत बदलाव ला कर विकास की बाधाओं को दूर करने का और सतत विकास के लिए एक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय माहौल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

यूएन रेजिडेंट कोर्डिनेटर और भारत में यूएनडीपी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री यूरी अफेनेसिव ने विशेष भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर यूएन के जरिए और खास तौर पर एसडीजी के जरिए भारत और अफ्रीका के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावना है। रिपलब्लिक ऑफ कोट डीवोयर में और इस समय रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया और रिपब्लिक ऑफ गुयाना में एक्रेडिटेड भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने भी लोगों को संबोधित किया। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सतत विकास के लक्ष्यों की राह पर राष्ट्रीय परामर्शः स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान (एसडीजी 3 और 4)

सितंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री सहित दुनिया भर के नेताओं ने 2030 के लिए सतत विकास का एजेंडा अपनाया था। इसमें गरीबी को समाप्त करने, असमानाता और अन्याय से मुकाबला करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए वर्ष 2030 तक के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी) तय किए गए हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (एमडीजी) की नीव पर अब एसडीजी और व्यापक सस्टेनेबलिटी एजेंडा के जरिए गरीबी के मूल कारणों की जड़ में जाने और विकास की वैश्विक जरूरत को पूरा करने में काफी सहयोग मिलेगा। यह सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। वैश्विक एजेंडा तय कर लिया गया है और अब यह संबंधित देश की जिम्मेवारी है कि वह अपने विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे आगे ले जाएं।

प्रो. बिबेक देबरॉय उद्घाटन भाषण देते हुए।

आरआईएस ने भारत सरकार के नीति आयोग और यूएन के भारत कार्यालय के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में 9–10 फरवरी, 2016 को खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा (एसडीजी 3 और 4) पर फोकस रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की राह तलाशने के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इसका उद्देश्य जागरुकता लाने के साथ ही केंद्र और राज्यों में इसके अमल के लिए रणनीति तलाशना भी था। नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य प्रो. बिबेक देबरॉय ने उद्घाटन भाषण दिया। आईआरएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और यूएन रेजिडेंट कॉर्डिनेटर व यूएनडीपी के भारत में रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव श्री यूरी अफानासिव ने स्वागत संबोधन किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सचिव (पश्चिम) सुश्री सुजाता मेहता ने एसडीजी फ्रेमवर्क और वैश्विक प्रक्रिया के बारे में बताया। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन (एसओएसपीआई) मंत्रालय के सचिव और भारत के चीफ स्टेटिस्टीसीयन प्रो. टी. सी. ए. अनंत ने विशेष संबोधन किया। नीति आयोग, भारत सरकार के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. पी. के. आनंद ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

परामर्श के पहले दिन मुख्य तौर पर एसडीजी 3 पर चर्चा हुई। जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्वस्थ्य जीवन को सुनिश्चित करना और सभी उम्र के सभी लोगों की कुशलता को बढ़ावा देना। पहला पूर्णाधिवेशन सत्र था हेल्दी इकोसिस्टम के जरिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसकी अध्यक्षता डब्लूएचओ के भारत प्रतिनिधि हेंग बेकेडम ने की। उन्होंने सभी एसडीजी के आपस में संबंध पर जोर दिया जैसे– स्वच्छता, जल प्रबंधन, स्वच्छ हवा और पानी, सुरक्षित भोजन, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन और सामुदायिक स्वास्थ्य देख–भाल, कमजोर तबकों के मुद्दे, महामारियों की चेतावनी और आपदा प्रबंधन, आधुनिक ऊर्जा और परिवहन की उपलब्धता, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को दूर करने की रणनीति, स्वास्थ्य (शांतिपूर्ण मस्तिष्क और स्वस्थ्य शरीर), शिक्षा की भूमिका, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, शराबखोरी पर नियंत्रण, धुम्रपान, नशीली दवाएं, मानसिक स्वास्थ्य और पब्लिक एडवोकेसी व मीडिया की भूमिका।

दूसरा पूर्णाधिवेशन सेशन टारगेट और इंडीकेटर्स पर था जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ पी. के आनंद ने की। इस दौरान जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई वे थे ग्लोबल मोनिटरिंग फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय इंडिकेटर्स के विकास के सिद्धांत, एसडीजी की निगरानी और विभिन्न अवधि के लिए लक्ष्यों की पहचान, मानकीकरण, हारमोनाइजेशन और विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में समन्वय और आंकड़े जमा करना व नए नजरिए।

नीति आयोग के सलाहकार (स्वास्थ्य/महिला व बाल कल्याण) श्री आलोक कुमार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी, डांचागत सुविधाओं और स्वास्थ्य खर्च पर आयोजित तीसरे पूर्णाधिवेशन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें सस्ती दवाओं, अस्पताल और पैथोलॉजिकल लैब तक लोगों की पहुंच, मरीजों को कर्ज की उपलब्धता, स्वास्थ्य बीमा और मानव संसाधन की कमी शामिल हैं।

पहले दिन तीन समांतर सत्र भी आयोजित किए गए जिनमें मृत्यु दरों में कमी और विभिन्न बीमारियों का नियंत्रण, एसडीजी 3 में औषधि विकास और जेनरिक दवाओं की भूमिका और एसडीजी 3 में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

दूसरे दिन की चर्चाएं एसडीजी 4 पर केंद्रित थीं जिनमें शामिल है– समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए जीवन पर्यंत सीखने के साधन को बढ़ावा देना। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने पहले पूर्णाधिवेशन सत्र की

अध्यक्षता की जिसमें गुणवत्ता, पहुंच, भागीदारी और विभिन्न क्षेत्रों के आपस में समन्वय पर जोर था। इस दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें लर्निंग आउटकम और अध्यापन की गुणवत्ताय बाल्यकाल विकास और प्री–प्राइमरी शिक्षाय सभी स्तर पर पहुंच और गुणवत्ताय समावेश और लैंगिक मुद्देय सतत विकास और स्वास्थ्य मूल्य शामिल थे।

जयपुर के शिक्षाशास्त्री श्री अभिमन्यू सिंह और नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर ने दूसरे पूर्णाधिवेशन सत्र की अध्यक्षता की जो कौशल विकास कार्यक्रमों और इनके अनुभवों को साझा करने पर आधारित था। इसमें मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता, सस्ता व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तथा बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास शामिल हैं।

गुणवत्ता और समावेशीकरण पर वैश्विक और राष्ट्रीय इंडिकेटर्स पर आयोजित तीसरे पूर्णाधिवेशन सत्र की अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के उप महा निदेशक डॉ. कृष्ण कुमार ने की। इस दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें वैश्विक मोनिटरिंग फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय इंडिकेटर्स के विकास के सिद्धांतय गुणवत्ता और समावेश की गणनाय मानकीकरण, हारमोनाइजेशन और आंकड़े जमा करने व नए नजरिए शामिल थे।

नीति आयोग के सदस्य श्री वी. के. सारास्वत ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। जिनमें यूएनईएससीएपी (एसेसडब्लूए) के प्रमुख प्रो. नागेश कुमार ने अपने विचार प्रकट किए। आरआईएस के अध्यक्ष एंबेस्डर श्याम सरन ने समापन भाषण दिया। नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. पी. के. आनंद ने विशेष भाषण दिया। आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. टी. सी. जेम्स ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

दो दिन की राष्ट्रीय चर्चा का उद्देश्य भारत के लिए आगे की राह तय करने के साथ ही इन एसडीजी को लागू करने के लिए भारत के मौजूदा नीतिगत ढांचे के तहत ही सकारात्मक एजेंडा तैयार करना था। इस चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों को साथ मिल कर काम करना होगा। ये लक्ष्य सामाजिक समानता के जरिए समावेशी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वास्थ्य भी इसका बहुत अहम तत्व है। इस चर्चा में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, अकादमिक क्षेत्र के प्रख्यात वक्ता और सिविल सोसाइटी संगठनों ने भाग लिया।

हिंद महासागर की समुद्रीय अर्थव्यवस्था की संभावना पर आईओआरए ब्लू इकॉनमी संवाद

आरआईएस ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), नई दिल्ली के साथ मिल कर 'हिंद महासागर में ब्लू इकॉनमी की संभावना' पर 17–18 अगस्त, 2015 में गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। ओआरएफ के उपाध्यक्ष श्री समीर सरन और भारत सरकार विदेश मंत्रालय के निदेशक (एमईआर) श्री आलोक डिमरी ने विशेष संबोधन किए। इंडियन ओशन रिम स्टडीज, आईओआरए के चेयर प्रो. वी. एन. अत्री ने मुख्य भाषण दिया। आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

ब्लू इकॉनमी के लिए एक व्यापक एकाउंटिंग ढांचा विकसित करने पर आयोजित पहले सत्र की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के निदेशक (एमईआर) श्री आलोक डिमरी ने की। फिशरीज और एक्वाकल्चर पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता यूएन के डिवीजन फॉर ओशन अफेयर्स एंड लॉ ऑफ दी सी के उप निदेशक (रिटायर्ड) डॉ. एच.

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी सम्मेलन में स्वागत भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) इंडियन ओसन रिम स्टडीज, आईओआरए के अध्यक्ष प्रो. वी.एन. अत्री; विदेश मंत्रालय के निदेशक (एमईआर), प्रो. आलोक डिमरी; ओआरएफ के उपाध्यक्ष श्री समीर सरन; एवं आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती।

पी. राजन ने की। तीसरे सत्र की अध्यक्षता ओआरएफ के जलवायु प्रयास के प्रमुख और सीनियर फेलो डॉ. विक्रम माथुर ने की। इस दौरान नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा पर चर्चा हुई। बंदरगाह, शिपिंग और निर्माण व अन्य क्षेत्रों पर आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता एनआरडीसी के अध्यक्ष और एमडी डॉ. एच पुरुषोत्तम ने की। पांचवे सत्र की अध्यक्षता इंडियन ओशन टूना कमीशन, शेशेल्स के महा सचिव श्री रंडोल्फ पायेट ने की। इस सत्र के दौरान सी–बेड एक्सप्लोरेशन और खनीज पर चर्चा की गई।

समुद्रीय अर्थव्यवस्था की धारणा विकास से जुड़े साहित्य में अपेक्षाकृत नई है। हरित अर्थव्यवस्था के दर्शन में यह किस तरह का बदलाव ला रही है इस पर बहुत से लोग विचार कर रहे हैं। हरित अर्थव्यवस्था कई देशों में विकास की रणनीति का अभिन्न हिस्सा रही है, फिर भी विकास की प्रक्रिया में ब्लू संसाधनों के योगदान को देख कर ब्लू इकॉनमी की उपयोगिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। समुद्रीय संसाधन जिनकी दुनिया को अभी ठीक तरीके से परिभाषित भी नहीं किया गया है, उनमें आम तौर पर समुद्र, नदी, झील और दूसरे जल स्रोत और जल संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो किसी देश के ताजा जल और समुद्री जल दोनों के इलाके के साथ ही मछली पकड़ने, खनिज, समुद्री पौधे, तेल, जल पर्यटन और खेल, मरीन बायोटेक्नालॉजी, हाइड्रोकार्बन, थोरियम आदि की डीप शी माइनिंग और इनसे जुड़ी जमीनी गतिविधियों को समुद्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना गया है। इस धारणा का प्रतिपादन करने वालों की नजर में ब्लू इकॉनमी के क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन के काफी अवसर हैं क्योंकि संसाधनों के सतत और सब को समाहित करने वाले उपयोग के साथ ही तेज आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग इन दोनों ही उद्देश्यों को समाहित करता है। माना जाता है कि ब्लू इकॉनमी से द्वीप और तटीय अर्थव्यवस्था अपने विकास संबंधी नीतियों में ज्यादा लाभ हासिल कर सकेंगे।

समुद्रीय अर्थव्यवस्था के विचार के साथ ही विश्व के प्रमुख समुद्रों में एक्वाकल्चर, सीफूड प्रोसेसिंग, समुद्र तकनीक विकास और शोध, समुद्र आधारित सेवाओं आदि के लिए निवेश को आकर्षित करने में तेजी आने की उम्मीद है। इस तर्क के अनुसार हिंद महासागर दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है तो इसमें ब्लू इकॉनमी को आगे

बढ़ाने के संसाधनों की प्रचूरता है। यह महासागर चार उप–क्षेत्रों – दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका को समाहित करता है। दुनिया के लगभग आधे कंटेनर शिप, एक तिहाई बड़े कार्गो यातायात और दो तिहाई से ज्यादा तेल परिवहन की ढुलाई इसी के जरिए होती है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के सदस्य देशों के लिए यह ब्लू इकॉनमी का अवधारणा ब्लू संसाधनों के ज्यादा सक्षम और वैज्ञानिक उपयोग का मौका उपलब्ध करवाती है ताकि वे इस क्षेत्र में विकास और रोजागर सृजन में इसका उपयोग कर सकें। मॉरिशस और शेशेल्स दो छोटे द्वीप वाले विकासशील देश हैं और इन्होंने पहले से ही अपनी–अपनी अर्थव्यवस्था में ब्लू इकॉनमी के सिद्धांतों को लागू करने के ले व्यापक समुद्री नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आईओआरए के दूसरे देश भी इस नीति को अपने विकास के लिए तेजी से शुरू करने पर विचार कर रही हैं ताकि ब्लू इकॉनमी के क्षेत्र से पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठा सकें और तेज विकास, सामाजिक कल्याण और पारिस्थितिक संतुलन को मुमकिन कर सकें।

इस विषय के महत्व को देखते हुए आरआईएस ने यह अहम सम्मेलन आयोजित किया। इंडियन ओशन रिम देशों के साथ साथ ही दुनिया के दूसरे कोनों के अकादमिक जगत के लोग, नीति निर्माता, कूटनीतिक और विद्वतजनों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता इंडियन ओशन रिम स्टडीज (आईओआरए) के चेयर प्रो. वी. एन. अत्री ने की। आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने इस सम्मेलन का सारांश पेश किया और ओआरएफ के क्लाइमेट इनीशिटिव के प्रमुख और सीनियर फेलो डॉ. विक्रम माथूर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

संयुक्त राष्ट्र आम सभा, न्यूयॉर्क के दौरान आरआईएस के कार्यक्रम

सतत विकास का 2030 एजेंडाः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान आरआईएस ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। पहला ऐसा साइड इवेंट 'सतत विकास का 2030 एजेंडाः दक्षिणी परिप्रेक्ष्य' पर 21 सितंबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन और सेंटर

(बायें से दायें) श्री युरी अफानासिएव, यूएन रेजीडेंट कॉर्डिनेटर एवं भारत में यूएनडीपी रेजीडेंट रिप्रजेंटेटिव ; श्री मछारिया कमाउ, यूएन में कीनिया के स्थायी प्रतिनिधि; यूएनडीपी की एडमिनिस्ट्रेटर सुश्री हेलेन क्लार्क; भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. अरविंद पनगरिया; श्री अशोक कुमार मुखर्जी, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि; आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और आरआईएस में असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्यसाची साहा।

ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन की भी साझेदारी रही। आरआईएस की असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची साहा ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एंबेस्डर अशोक कुमार मुकर्जी ने उद्‌घाटन भाषण दिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. अरविंद पानागढ़िया ने मुख्य संबोधन किया। यूएनडीपी की प्रशासक सुश्री हेलेन क्लार्क ने विशेष संबोधन किया। संयुक्त राष्ट्र में कीनिया के स्थायी प्रतिनिधि एंबेस्डर मछापिया कमाऊ; और संयुक्त राष्ट्र में आयरलैंड के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत डेविड डोनोघू और एसडीजी पर ओपन वर्किंग ग्रूप के को फेसिलिटेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस सम्मेलन में वरिष्ठ कूटनीतिकों, नीति निर्माताओं, संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न सदस्य देशों के स्थायी प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, प्रख्यात अकादमिक विद्वानों के अलावा दक्षिण के देशों के सिविल सोसाइटी और मीडिया के लोगों ने हिस्सा लिया।

पहली पैनल चर्चा थी– 2030 का एजेंडाः इसका विकासशील देशों के लिए क्या मतलब है? इस पैनल में साउथ सेंटर, जेनेवा के प्रो. कार्लोस कोरियाय सेंटर ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की निदेशक सुश्री सारा एफ क्लिफय यूएन रेजिडेंट कोर्डिनेटर और यूएनडीपी के भारत में स्थायी प्रतिनिधि श्री यूरी अफनासिव और यूएन फाउंडेशन की सीनियर पॉलिसी डायरेक्टर सुश्री मिन्ह–थाऊ पाम शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 लक्ष्य को तय करते समय माना है कि इससे पांच पी यानी पीपल (लोग), प्लानेट (ग्रह), प्रोसपेरिटी (समृद्धि), पीस (शांति) और पार्टनरशिप (साझेदारी) आपस में जुड़ सकेंगे। ये एसडीजी सार्वभौमिक, एकीकृत और आपस में संबद्ध हैं और किसी को भी पीछे न छोड़ने का ध्येय रखते हैं। हालांकि इन एसडीजी को अमल में लाना पूरी तरह संबंधित देशों पर निर्भर करेगा, लेकिन विकासशील देशों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने जरूरी हैं। इस संबंध में, पहले पैनल ने इस बात पर विचार किया कि इस एजेंडा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कैसे उत्तर–दक्षिण और दक्षिण–दक्षिण साझेदारी पर बहुत हद तक निर्भर करेगा।

दूसरी परिचर्चा का विषय थाः 2030 का एजेंडाः उभरते दक्षिण की चुनौतियां और अवसर। इस पैनल के अध्यक्ष नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर थे। इस सत्र के वक्ताओं में द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, न्यूयॉर्क के प्रो. संजय रेड्डी; संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के स्थायी उप प्रतिनिधि राजदूत कार्लोस सेर्गिओ सोबरल ड्यूरेट; ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. समीर सरन और ब्रूकिंग्स इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर फेलो डॉ. डब्लूपीएस सिद्धू शामिल थे।

अगले 15 साल के लिए दक्षिण की मुख्य चुनौतियां हैंः संसाधन, क्षमता और तकनीक। इसलिए अर्थव्यवस्था, तकनीक और पर्यावरण से जुड़े वैश्विक शासन व्यवस्था को सभी देशों में इस एजेंडा को व्यापक रूप से लागू करने और उसमें सहयोग करने पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमल में लाने के साधानों के रूप में (मींस ऑफ इंप्लीमेंटेशन) वित्त, तकनीक, क्षमता विकास, व्यापार और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समाधान करता है। दूसरे पैनल में इस बात पर चर्चा हुई कि बहुपक्षीय संस्थानों को इस एजेंडा को सभी बिंदुओं के लिहाज से प्रभावी बनाने

के लिए उभरती शक्तियों और विकासशील दुनिया की अभिलाषाओं को समाहित करना होगा।

संस्थानिक ढांचे और तकनीक का विकास और उस तक पहुंच पर विमर्श

आरआईएस की ओर से सेंटर ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ मिल कर आयोजित किया गए दूसरे साइड इवेंट का विषय था– 'सांस्थानिक ढांचे और तकनीक का विकास और उस तक पहुंच पर विमर्श'। इसे 22 सितंबर, 2015 को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मिडटाउन सेंटर में आयोजित किया गया। पहला सत्र इंटरनेशनल आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट पर था। इसके मोडरेटर ब्रूकिंग्स इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर फेलो डॉ. डब्लूपीएस सिद्धू थे। वक्ता के तौर पर इसमें जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डॉ. थॉमस फ्यूसय सेंटर फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डॉ. सारा हेरनय इंस्टीट्यूटो इगरापे की सीनियर फेलो जरेनाटे गिनिनी और आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी शामिल थे। एसडीजी के गोल 16 शांति और न्याय की बात करता है और गोल 17 विकास के लिए वैश्विक साझेदारी में नई जान डालने की बात करता है। ये गोल दक्षिणी देशों को यह मौका देते हैं कि वे वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका और महत्वाकांक्षा को स्पष्ट कर सकें। इस दौरान वक्ताओं ने एसडीजी को पूरा करने के लिए ग्लोबल पब्लिक गुड्स के प्रावधान को बढ़ाने और बहुपक्षीय संस्थानों में व्यापक वैश्विक सहभागिता पर जोर दिया। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि दक्षिण के संस्थान कैसे विकासशील विश्व की संसाधनों की जरूरतों में और 2015 के बाद के एजेंडा को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

दूसरा सत्र 'टीएफएम के संस्थानीकरणः आईपी और तकनीक तक पहुंच' विषय पर था। इस सत्र में भाग लेने वालों में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर श्री अमित नारंग; यूएन–डीईएसए के डॉ. डेविस ओकॉनोर; द साउथ सेंटर से प्रो. कार्लोस कोरिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री समीर सरन शामिल थे। मौजूदा संस्थानिक व्यवस्था विकासशील देशों को तत्काल जरूरत की तकनीक विकास, तैनाती और प्रसार व हस्तांतरण में अपर्याप्त हैं। इस लिहाज से कई बाधाएं हैं, जैसे कि आईपी राइट्स और तकनीकी को अपनाने की क्षमता की कमी। 2015 के उपरांत के विकास एजेंडा के तहत विश्व नेताओं ने एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा दस्तावेज में तकनीकी हस्तांतरण व्यवस्था (टीएफएम) स्थापित करने पर जोर दिया है। यूएन की व्यवस्था अब इस प्रस्ताव को जीवन देने पर काम कर रही है। इसलिए दूसरे पैनल ने टीएफएम के तहत विभिन्न देशों के लिए जिम्मेवारी को तय करने की संभावना पर विचार किया जिसके तहत वैश्विक स्तर पर तकनीक तक पहुंच और तकनीक हस्तांतरण, क्षमता विकास और इनोवेशन के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की व्यवस्था हो।

विकास के लिए वित्तीय उपलब्धता पर विमर्श

ईथीयोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में विकास हेतु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस (एफएफडी–3) से पहले आरआईएस ने संयुक्त राष्ट्र के भारत कार्यालय और भारत विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) की साझेदारी में विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर एक चर्चा आयोजित की जिसमें एफएफडी–3 के मुख्य मुद्दों पर विमर्श किया गया।

पहली चर्चा नई दिल्ली में 8 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई जिसमें आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने अध्यक्षीय भाषण दिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के यूएन आर्थिक और सामाजिक डिवीजन के निदेशक डॉ. आदर्श स्वाइकाय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के मानद प्रोफेसर दीपक नैयर और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर के अर्थशास्त्र के डिस्टिंग्यूश्ड प्रोफेसर डॉ. अकमल हुसैन इसमें वक्ता के तौर पर शामिल थे।

चर्चा में शामिल वक्ताओं ने एफएफडी3 को ले कर भारत के रवैये के बारे में बताया। एफएफडी ऐसे परिदृष्य में आयोजित हुआ जो अगले 15 साल के लिए विकास की वैश्विक संरचना तय करेगा। यह 2002 के मोंटेरी कंसेंसस और 2008 के दोहा घोषणापत्र को भी आगे बढ़ाता है जिसमें विकास के लिए संसाधन जुटाने और सतत विकास में वैश्विक साझेदारी के लिए इसका उपयोग करने की बात कही गई है। यह ऐसे विकास की बात करता है जिसके तीन पहलू हैंः समावेशी विकास को बढ़ावा, पर्यावरण की रक्षा और शांतिपूर्ण व समावेशी समाज।

वित्त और विकास पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आउटकम डक्यूमेंट का मसौदा पर आरआईएस के रिसर्च एसोसिएट डॉ. प्रियदर्शी दासय दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के महा सचिव श्री एन पॉल दिवाकरय सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबलिटी, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक श्री सुब्रत दासय वादा ना तोड़ अभियान के संयोजक श्री अमिताभ बेहरय वोलंट्री एक्शन नेटवर्क इंडिया (वानी) के श्री हर्ष जेटली ने। इस सत्र की अध्यक्षता की यूएन विमेन ऑफिस फॉर इंडिया की प्रतिनिधि सुश्री रिबेका रिचमैन ने।

पैनल में शामिल लोगों का मत था कि भारत का रवैया ऐसा होना चाहिए कि विकास प्रक्रिया के लिए वित्त की उपलब्धता को व्यापक प्ररिपेक्ष में देखा जाए जिसमें 2015 के उपरांत के विकास एजेंडा, जलवायु परिवर्तन और विकास सहयोग भी शामिल हो। विकास हेतु वित्त में वित्तीय मदद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, घरेलू संसाधन जुटाना और वैश्विक कर संबंधी मामले भी शामिल हैं।

जेएनयू के मानद प्रोफेसर, प्रो. दीपक नायर कंसलटेशन के दौरान संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाग के निदेशक, डा. आदेश स्वैका ; लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज के अर्थशास्त्र के विख्यात प्रोफेसर डा. अकमल हुसैन; एवं एफआईडीसी के बोर्ड मेंबर तथा नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर।

दूसरी चर्चा एडिस अबाबा में 14 जुलाई, 2015 को एफएफडी 3 के साइडलाइन पर आयोजित की गई। भारत सरकार के माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा ने अध्यक्षीय भाषण दिया। इथियोपिया और जिबूती में भारत के राजदूत श्री संजय वर्मा ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के विजिटिंग फेलो, प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती, साउथ सेंटर, जेनेवा के फाइनांस एंड डेवलपमेंट में सीनियर एडविजर डॉ. मैनुअल मोंटेस, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर, सिविक्स के महा सचिव श्री डैनी श्रीस्कंदराज ने अकादमिक जगत और सिविल सोसाइटी के विचार सामने रखे। आरआईएस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सब्यसाची साहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

इस चर्चा के दौरान निकले निष्कर्षों को पॉलिसी दस्तावेज के तौर पर माननीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को पेश किया गया जो एडिस अबाबा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे और आगे चल कर सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में जारी 2015 के उपरांत के विकास एजेंडा के लिए विभिन्न सरकारों के बीच चर्चा में शामिल हुए। आरआईएस ने यूएन के साथ साझेदारी की और बाद में भारत में एसडीजी कोल कर चले विमर्श में एकेडमिक और शोध जगत का मुख्य साझेदार बना।

विकास हेतु वित्त और 2015 उपरांत का एजेंडा

आरआईएस ने यूएन इन इंडिया और भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) के साथ मिल कर 'विकास हेतु वित्त और 2015 उपरांत का एजेंडाः एडिस के से आगे की राह' विषय पर 2 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आरआइएस के सतत विकास लक्ष्य पर कार्यक्रम का हिस्सा बना।

भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय जयंत सिन्हा ने मुख्य संबोधन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के अध्यक्ष एंबेस्डर श्याम सरन ने अध्यक्षीय भाषण दिया और विदेश मंत्रालय की सचिव (एम एंड ईआर) सुश्री सुजाता मेहता ने विशेष भाषण दिया। ऑक्सफैम इंडिया

भारत सरकार के वित राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा संगोष्ठी के दौरान प्रमुख भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; भारत सरकार के कंपनी मामले मंत्रालय के भारतीय कंपनी मामले संस्थान के महानिदेशक एवं सीईओ डा. भास्कर चटर्जी; विदेश मंत्रालय की सचिव (एमएंडईआर) सुश्री सुजाता मेहता; आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; यूएन रेजीडेंट कॉर्डिनेटर एवं भारत में यूएनडीपी रेजीडेंट रिप्रजेंटेटिव, श्री युरी अफानासिव; ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ सुश्री निशा अग्रवाल एवं नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया ग्रुप के संयोजक श्री अमिताभ बेहर।

की सुश्री निशा अग्रवाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के महा निदेशक और सीईओ डॉ. भास्कर चटर्जी वक्ताओं में शामिल थे। नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया/वादा ना तोड़ अभियान के कार्यकारी निदेशक श्री अमिताभ बेहर और एफआईडीसी उभरते विकास मुद्दे पर कार्यकारी समूह के संयोजक ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

यूएनडीपी, न्यूयॉर्क में एनईएसटी बैठक

आरआईएस ने यूएनडीपी के ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट ऑन साउथ–साउथ एंड ट्रायंगलर कॉपरेशन के साथ मिल कर न्यूयॉर्क स्थित यूएनडीपी कार्यालय में 22 सितंबर, 2015 को एक विमर्श का आयोजन किया जिसमें नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट) के भविष्य की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। यूएनडीपी के लीड एडवाइजर डॉ. जियाओजुन ग्रेस वांग ने शुरुआती संबोधन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विशेष टिप्पणी की। अन्य वक्ताओं में रिसर्च सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (आरसीआईडी), चीन कृषि विश्वविद्यालय, (सीएयू) के निदेशक डॉ. वांग यीहुआन; संयुक्त राष्ट्र में मैक्सिको के स्थायी मिशन के डेलीगेट श्री जीसस वेलाजेकूज कैस्टिलो; यूएनएड्स की सीनियर एडवाइजर सुश्री एंजेला ट्रेनटन–मबोंडे; जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डॉ. थॉमस फ्यूस; और द साउथ सेंटर के प्रो. मैनुअल मोंटेस शामिल थे।

वक्ताओं ने उत्तर–दक्षिण साझेदारी और दक्षिणीय सहयोग के बीच आपसी सहयोग पर जोर दिया। इस लिहाज से नेस्ट की ओर से सहयोग बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों पर भी चर्चा की गई।

(बायें से दायें) यूएनडीपी के साउथ–साउथ एंड ट्रैएंगूलर कोपरेशन में पॉलिसी एनालिस्ट, श्री डोनिंगनॉन सोरो; जर्मन डेवेलपमेंट इंस्टीच्युट के डा. थॉमस फुइस ; आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (सीएयू) के रिसर्च सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवेलपमेंट (आरसीआईडी) के निदेशक डा. वांग यीहुआन; यूएनडीपी के साउथ–साउथ एंड ट्रैएंगूलर कोपरेशन में प्रमुख सलाहकार डा. शियाओजुन ग्रेस वांग; आरआईएस के असिस्टैंट प्रोफेसर डा. सव्यसाची साहा; आरआईएस के रिसर्च असिस्टैंट श्री प्रत्युष; एवं यूएनडीपी के साउथ–साउथ एंड ट्रैएंगूलर कोपरेशन में पॉलिसी एनालिस्ट सुश्री शैम्स बनिहानि।

आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स (एआईएनटीटी) की चौथी गोलमेच चर्चा

आरआईएस के आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, मलेशिया, आसियान सचिवालय, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (आईएसआईएस), मलेशिया के साथ मिल कर आसियान–इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स (एआईएनटीटी) की चौथी गोलमेज वार्ता आयोजित की। क्वालालंपुर में 7–8 अगस्त, 2015 को आयोजित इस चर्चा का विषय था 'आसियान–भारतः संबंधों को मजबूती जो बांध सके'। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (आईएसआईएस), मलेशिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी श्री रस्तम मोहम्मद ईसा ने स्वागत भाषण दिया। मलेशिया के विदेश उप मंत्री सेरी रिजल मेरिकन नैना मेरिकन ने मुख्य संबोधन दिया। माननीय विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार जनरल (रिटायर्ड) डॉ. विजय कुमार सिंह ने उद्‌घाटन भाषण दिया। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा और आरआईएस के वायस अध्यक्ष डॉ. वी. एस. शेषाद्री ने विशेष भाषण दिए। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने समापन भाषण दिया।

'आसियान–भारत आर्थिक संबंधः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर एआईएनटीटी तीसरी गोलमेज चर्चा की रिपोर्ट और 'आसियान–भारतः 2015 उपरांत एजेंडा का आकार' की आईडीएसए की सातवीं दिल्ली डायलॉग की कार्यवाही की रिपोर्ट जारी की गई। गोलमेज चर्चा के पहले सत्र में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और एक देश से दूसरे देश में होने वाले अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे गैर–पारंपरिक सुरक्षा खतरों पर चर्ची की गई। डॉ. वी. एस. शेषाद्री ने इसकी अध्यक्षता की।

दूसरे सत्र के दौरान मौजूदा और उभरती हई सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई साथ ही इस क्षेत्र के देशों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उन पर भी विमर्श हुआ। सुश्री एलिना नूर ने इस सत्र की अध्यक्षता की। तीसरे सत्र के दौरान आसियान इकनॉमिक कम्यूनिटी (एईसी) और रिजनल कंप्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) जैसी क्षेत्रीय आर्थिक संरचना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और

(बायें से दायें) आरआईएस एवं एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) अनिल वाधवा; मलेशिया के उप विदेश मंत्री माननीय डाटो' सेरी रीजल मेरिकाना नैना मेरिकन; मलेशिया के इंस्टीच्युट ऑफ स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी टैन श्री रस्तम मोहम्मद इसा; भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह; एवं आरआईएस एवं एआईसी के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस.शेषाद्रि।

आगे का क्या रास्ता क्या हो सकता है, इस पर विमर्श किया गया। पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के चांसलर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के सीनियर फेलो डॉ. राजीव कुमार ने इसकी अध्यक्षता की।

एआईसी के संयोजक और आरआईएस के प्रो. प्रबीर डे ने चौथे सत्र की अध्यक्षता की जिसमें आसियान व भारत के बीच प्राचीन और मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा करते हुए संबंधों को और मजबूती देने के लिए सुझावों पर विचार किया गया।

पांचवें सत्र की अध्यक्षता तन स्री दातो अजित सिंह ने की जो आईजेएम कॉरपोरेशन, बेरहाड के एडवाइजर (इंडिया बिजनेस) हैं और आसियान सचिवालय के पूर्व महा निदेशक रहे हैं। यह सत्र 'आसियान के 2015 उपरांत एजेंडा और भविष्य की राह' पर था।

गोलमेज का समापन प्रो. प्रबीर डे और तन स्री रस्तम मोहम्मद ईसा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। इसमे भारत और आसियान के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके परिणाम का उपयोग 13वें आसियान–भारत सम्मेलन में किया जाएगा जो इस साल क्वालालंपुर में होगा।

दक्षिणीय सहयोग का भारतीय परिपेक्ष्य

प्रोग्रस पर परियोजना की अंतिम बैठक के साइडलाइन पर 13 जनवरी 2016 को एसीपी (अफ्रिकन, कैरीबियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ स्टेट्स) ने भारतीय दूतावास के साथ मिल कर दक्षिणीय सहयोग पर भारतीय परिपेक्ष पर संगोष्ठी का आयोजन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इसे संबोधित किया। विचार विमर्श उनकी किताब 'लॉजिक ऑफ शेयरिंगः इंडियन एप्रोच टू दक्षिणीय सहयोग' पर आधारित था। एसीपी के 50 से ज्यादा राजदूत, जिनका नेतृत्व एसीपी के महा सचिव महामहिम डॉ. पैट्रिक गोम्स कर रहे थे इसमें शामिल हुए। इनके साथ यूरोपीय आयोग के और अकादमिक जगत के प्रतिनिधि जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर के प्रो. डोरिस स्क्रोडर और ईसीडीपीएम के डॉ. जैम्स मैकी भी शामिल उपस्थित थे। भारत के ईयू में राजदूत श्री मानवजीत सिंह पूरी ने भी इसमें भाग लिया।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी महामहिम डा. पैट्रिक गोम्स को 'द लॉजिक ऑफ शेयरिंग : इंडियन अप्रोच टू साउथ–साउथ कोपरेशन' शीर्षक पुस्तक भेंट करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) श्री फिलीप लैट्रिचे, श्री मंजीव सिंह पुरी, प्रो. डोरिस एस्क्रोएडर; एवं डा. जेम्स मैकी।

इस बैठक ने दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के विशाल और बढ़ते योगदान को सामने लाने का शानदार मौका मुहैया करवाया। इसमें भाग लेने वालों ने 'लॉजिक ऑफ शेयरिंग' के प्रकाशन का स्वागत करते हुए पुस्तक को दक्षिणीय सहयोग के बारे में ठोस आंकड़ों की कमी को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।

तीसरा इंडियालिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवाचार और सतत विकास पर

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं में पिछले कुछ दशकों के दौरान आए अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें तकनीकी और संस्थानिक नवाचार ने काफी मदद की जिससे विभिन्न देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ सका। वैश्विकरण के तेजी से उभरते संदर्भ में अगर बचे रहना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले में खरा उतरना ही होगा। बड़े विकासशील देशों में भी विकास की ऊंची दर के उदाहरणों को देख कर साफ हो जाता है कि तेज आर्थिक विकास विकासशील दुनिया की भी पहुंच के अंदर है। हालांकि तीव्र विकास दर के साथ ही सभी स्तरों पर असमानता के बढ़ने और संसाधनों के बहुत अधिक दोहन के प्रमाण भी मिल रहे हैं। इसलिए अब उभरती चुनौती यह है कि आर्थिक, परिस्थिति और समाज के व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्य विकास भी हो और मुकाबले में खरा उतरना भी संभव हो। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य का केंद्र भी यही है। इस पृष्ठभूमि में आरआईएस और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस), त्रिवेंद्रम ने 16–18 मार्च, 2016 को केरल में तीसरा इंडियालिक्स सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य सम्मिलित और सतत विकास की नई चुनौतियों को पूरा करने के लिए व्यापक संदर्भ (तकनीकी, संस्थानिक और सांगठनिक) में नवाचार के महत्व को रेखांकित करना था।

इंडियालिक्स विकासशील देशों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और बदलते समाजों में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए लर्निंग, इनोवेशन एंड कंपिटेंस बिल्डिंग सिस्टम (लिक्स) की अवधारणा को एक ढांचे के तौर पर स्थापित करने के लिए बनाए गए विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ग्लोबलिक्स की भारतीय इकाई है।

श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य और पूर्व पर्यावरण और वन मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया। सीएसडी के अध्यक्ष श्री के. एम. चंद्रशेखर ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। सीएसडी के निदेशक प्रो. अमित शोवन राय ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने शुरुआती संबोधन किया। फेडरल यनिवर्सिटी ऑफ रियो डी जेनेरियो, ब्राजील के प्रो. जोस ई कैसियोलेटो ने ग्लोबलिक्स की ओर से बधाई दी। भारत में सयुक्त राष्ट्र के स्थानीय प्रतिनिधि इन इंडिया श्री यूरी एफ़ैनैसिएव ने विशेष संबोधन किया। केरल विधानसभा के सदस्य और सीएसडी के ऑनररी फेलो डॉ. टीएम थॉमस इसाक ने मुख्य संबोधन किया। सीएसडी के प्रो. के. जे. जोसफ ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

सम्मेलन के विभिन्न सत्रों के दौरान एमडीजी से ले कर एसडीजी तक जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैः कार्य, चुनौतियां और भविष्य की राहय एसडीजी, नवाचार और खगौलीकरण, नवाचार, असमानता और सस्टेनेबल विकास, लो कार्बन नवाचार, नवाचार और स्थायी विकास के लिए शासन, निर्माण संबंधी मुद्दे और स्थायी विकास, समावेशी और स्थायी विकास के लिए इनोवेशन, दक्षिणी परिप्रेक्ष्य, सतत कृषि के लिए नवाचार, प्लांटेशन कृषि, इनक्लूसिव और सतत विकास

के लिए आरएंडडी के आगे का नवाचार, केरल के विकास संबंधी अनुभव की सीख, सामाजिक क्षेत्र (स्वास्थ्य/शिक्षा) के नवाचार, वंचित और सतत विकास, जमीनी स्तर का नवाचार, और समावेशी एवं सतत विकास के लिए नवाचारः प्लांटेशन कृषि। सम्मेलन में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों, अकादमिक क्षेत्र और उद्योग जगत के लोगों व राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भागीदारी की।

सतत विकास के दौर में कृषि और खाद्य व्यवस्था पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परामर्श

आरआईएस ने ग्लोबल पैनल ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर न्यूट्रीशन और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के साथ मिल कर नई दिल्ली में 11–12 फरवरी, 2016 को सतत विकास के दौर में कृषि और खाद्य व्यवस्था पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किया।

यह सम्मेलन आरआईएस के सतत विकास लक्ष्य पर चल रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में ही था। इसका उद्देश्य एसडीजी में, खास तौर से कृषि और पोषण, पर विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिल कर काम करने के मौकों की पहचान करना था।

आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई) के प्रेसिडेंट प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी और ग्लोबल पैनल ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर न्यूट्रीशन के सदस्य ने भाषण दिए। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस परामर्श के उद्देश्य प्रस्तुत किए। ग्लोबल पैनल ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर न्यूट्रीशन के निदेशक प्रो. सैंडी थॉमस ने खाद्य और कृषि व्यवस्थाओं के संदर्भ में बेहतर पोषण नतीजों में सहयोग के लिए पैनल के कार्यक्रमों के बारे में बताया। नीति आयोग, भारत सरकार के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. पी. के. आनंद ने विशेष टिप्पणी की। घाना के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम जॉन कुफोर ने भी विशेष संदेश दिया।

तकनीकी सत्र के दौरान दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि, दक्षिण एशिया में बेहतर पोषण, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पोषण सुरक्षा और खान–पान विविधता को सुनिश्चत करना, फसल की गुणवत्ता और स्वास्थ्य, कीटनाशक के अवशेष, जल संक्रमण, जल संकट, एसडीजी हासिल करने की राह और कृषि व खाद्य व्यवस्था के जरिए बेहतर पोषण, विविध क्षेत्रों की साझेदारी और

(बायें से दायें) प्रो. के श्रीनाथ रेड्डी, प्रो. सैंडी थॉमस, श्री श्याम सरन एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

वित्तीय सहायता, नीति निर्माण के लिए साक्ष्यों की उपलब्धता, नीति के स्तर पर कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता, दक्षिण एशिया के लिए कृषि संबंधी शोध व विकास और सहयोग पर चर्चा हुई।

भारत में मीडिया ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था, पोषण और कृषि जैसे विषयों को चर्चा में लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस नजरिए के साथ सम्मेलन के दौरान दूसरे दिन एक विशेष मीडिया के साथ विचार विनमय सत्र भी रखा गया जिसमें दक्षिण एशिया में उन्नत कृषि, खाद्य व्यवस्था, स्वास्थ्य और पोषण तथा विकास पर चर्चा की गई।

श्री श्याम सरन, डॉ. के श्रीनाथ रेड्डी, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. सैंडी थॉमस और ग्लोबल पैनल फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर न्यूट्रीशन के सदस्य प्रो. टॉम एर्नोल्ड वक्ता के तौर पर शामिल थे।

भाग लेने वालों में भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के वरिष्ठ नीति निर्माता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छा पोषण मानव विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला का काम करता है। कुपोषण की समस्या और कृषि, खाद्य और पोषण के गठजोड़ से जुड़ी अनेक चुनौतियों को हल करने को ले कर चले अभियान की वजह से दक्षिण एशिया में काफी कुछ किया जा चुका है इसका एक प्रमुख उदाहरण भारत में पांच साल से छोटे बच्चों में स्टंटिंग के मामलों को 2005–06 के 48 फीसदी से घटा कर 2014 में 39 फीसदी तक पहुंचाने का है।

इन बदलावों के बावजूद भारत वजन कम होने और मोटापे दोनों का बोझ एक साथ झेल रहा है। यह महसूस किया गया है कि उत्पादन, विरणन, प्रोसेसिंग और उपभोग से जुड़ी पूरी खाद्य और कृषि व्यवस्था में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बदलाव की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर सभी के लिए पोषण का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि दक्षिण एशिया के देश सूचनाओं के आधार पर और ज्यादा प्रभावशाली रणनीति अपनाएं।

स्वयंसेवी संस्थाए, व्यापार और नॉलेज सोसाइटी के साथ मिल कर काम करते हुए सरकारों को एकीकृत नजरिया विकसित करने की जरूरत है। साथ ही खाद्य व्यवस्था और कृषि का एक ऐसा सामरिक नजरिया भी विकसित करना होगा जिससे आज के निर्णयों और निवेश का भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने में पर्याप्त मदद मिल सके।

विज्ञान, तकनीक और नवाचार में भारत–अफ्रीका साझेदारी

आरआईएन ने 21 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसका विषय था 'विज्ञान, तकनीक और नवाचार में भारत–अफ्रीका साझेदारीः कृषि, खाद्य सुरक्षा और जैव सुरक्षा पर विशेष फोकस।'

आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि और सहयोग विभाग के संयुक्त सचिव (बीज और आईसी) श्री आर. के. सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। इथियोपियन इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल रिसर्च, इथियोपिया के उप महा निदेशक डॉ. अदुगना वाकजिरा जेमेलाल ने मुख्य भाषण दिया। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉ. कल्याण गोस्वामी ने विशेष टिप्पणी की।

सम्मेलन का पहला सत्र संसाधन जुटाने की व्यवस्था और क्षेत्रीय सहयोग के मुद्दे पर केंद्रित था। प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने इस सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र के मुख्य वक्ताओं में जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी, यूएसए के प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल इकॉनमिक पॉलिसी के प्रो. रामकिशन एस राजन, डीएफआईडी, इंडिया के फूड एंड रिसोर्स सेक्यूरिटी एडवाइजर डॉ. डैनिएल ब्रैडली, और आरआईएस के विजिटिंग प्रोफेसर प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती शामिल थे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के डीएआरई–आईसीएआर के ओएसडी डॉ. आर. के मित्तल ने दूसरे सत्र की अध्यक्षता की जो कृषि और खाद्य सुरक्षा पर था। तंजानिया के उप राष्ट्रपति कार्यालय में परमानेंट सेक्रेटरी श्री इब्राहिम अवधि मदीय जैन इरिगेशन के एडवाइजर श्री सुरेंद्र मखीजा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉ. जसकरन सिंह महल, सकता सीड्स के सीईओ डॉ. जय सिंह, और आरआईएस के विजिटिंग फेलो डॉ. टी. पी. राजेंद्रन मुख्य वक्ताओं में शामिल थे।

टेरी की सीनियर डायरेक्टर और डिस्टिंग्यूश्ड फेलो डॉ. विभा धवन ने तीसरे सत्र की अध्यक्षता की जो बायोसेफ्टी पर था। इस सत्र के दौरान मुख्य वक्ता थे टेरी के डिस्टिंग्यूश्ड फेलो और पूर्व सचिव, आईसीएआर, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार डॉ. अरविंद कौशल, डॉ. डीडीके शर्मा, एडिशनल प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर, डीपीपीक्यूएस, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. मूसा सवडोगो, सीनियर प्रोग्राम अफसर, एनवायर्नमेंटल बायोसेफ्टी, एनईपीएडी एबीएनई, बुर्किना फासो, श्रीमती ओबुवागबेमिनियी ओरियोमी ओलाजितन पपूला, हेड, लीगल यूनिट, महा निदेशक कार्यालय, राष्ट्रीय बायोतकनीक विकास एजेंसी, नाइजीरिया, और डॉ. सिलास ओबूकोसीओ ओबवोगो, ऑपरेशंस मैनेजर, एनईपीएडी एजेंसी एबीएनई, युगांडा।

डॉ. एस. आर राव, एडवाइजर, बायोतकनीक विभाग, भारत सरकार ने समापन भाषण दिया। प्रो. करीम मारेडिया, प्रोफेसर, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए ने अंतिम टिप्पणी की।

श्री आर.के. सिंह उद्घाटन भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, डा. अडुग्ना वाकजिरा गेमेलाल, डा. कल्याण गोस्वामी एवं प्रो. करीम मेरेडिया।

भारत–म्यांमार सीमा व्यापार पर परामर्श कार्यशालाः संभावनाएं, सीमाएं और नीतिगत सुझाव

आरआईएस ने भारत–म्यांमार सीमा व्यापार पर परामर्श कार्यशालाः संभावनाएं, सीमाएं और नीतिगत सुझाव पर इंफाल और मोरेह में 21–22 जनवरी, 2016 को आयोजित की। प्रो. राम उप्रेंद्र दास, आरआईएस ने स्वागत और परिचय भाषण दिया। एमयू के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. चौधरी प्रियोरंजन सिंह ने पहले व्यापार सत्र का संयोजन किया जो भारत–म्यांमार सीमा व्यापार और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के सामान्य संदर्भ पर था। इस सत्र के वक्ताओं में मणिपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. अमर यूमनामय राजनीति विज्ञान विभाग के प्रो. कोंसम ईबोय और राजनीतिक विज्ञान विभाग के ही डॉ. एल राजेन शामिल थे।

प्रो. अमर यूमनाम, अर्थशास्त्र विभाग, एमयू ने राज्य विशेष के अनुभव विषय पर दूसरे सत्र का संचालन किया। इस डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. डी. के. चक्रबर्ती, मिजोरम यूनिवर्सिटी के प्रबंधन विभाग के प्रो. ई निक्सन सिंह, पंचुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज, ऐजवाल के डॉ. आर के पी जी सिंघा, मणिपुर यूनिवर्सिटी के सीएसएसईआईपी में रीडर डॉ. थियाम भारत, और नगालैंड यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स विभाग के डॉ. टी रजेनतुंग इजुंग वक्ताओं के तौर पर शामिल थे।

तीसरे सत्र के दौरान व्यापार संगठनों, व्यापारियों और दूसरे दावेदारों के प्रतिनिधियों के विचार जानने का प्रयास किया गया। एमयू के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. चौ. प्रियरंजन सिंह ने इस सत्र का संचालन किया। इस दौरान मुख्य वक्ताओं में शामिल थे इंडो–म्यांमार बोर्डर ट्रेड यूनियन (आईएमबीटीयू) के अध्यक्ष श्री डब्लू. नाबाचंद्राय मणिपुर चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) के प्रेसिडेंट डॉ. धाबालीय मणिपुर टूरिज्म फोरम के वाइस प्रेसिडेंट श्री एन. इबोगोचोउबी, आईएमबीटीयू सदस्य श्री एन. रुद्रमणि, क्यूबटेन टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री होबम जोयरेंबा, आईएमबीटीयू के श्री टी. रशमणि, एमसीसीआई के श्री थोकचोम जोतिन, और एमसीसीआई के श्री खगेंबा सनाबम। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास ने समापन भाषण दिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास कार्यशाला को संबोधित करते हुए।

आईओआरए की बढ़ती शक्ति और अगले दशक की योजना

आरआईएस ने आईओआरए की बढ़ती शक्ति और अगले दशक की योजना पर नई दिल्ली में 6 जनवरी, 2016 को एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव (एसएम एंड आईओआर) सुश्री रेणू पाल ने अध्यक्षीय टिप्पणी की। इंडियन ओशन रिम स्टडीज (आईओआरएस) फॉर आईओआरए, मॉरिशस यूनिवर्सिटी के अध्यक्षीय प्रो. वी. एन. अत्री ने मुख्य भाषण दिया। महत्वपूर्ण वक्ताओं में आईसीडब्लूए के निदेशक (शोध) डॉ. पंकज कुमार झा, आईडीएसए की सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉ. रुचिता बेरी और आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती शामिल थे।

दिल्ली संवाद VIII – 'आसियान–भारत संबंधः एक नई मिसाल'

आसियान–भारत संबंधों के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर और आसियान के साथ भारत के रिश्तों के संदर्भ में एक नया नजरिया पैदा करने के लिए नई दिल्ली में 17–19 फरवरी, 2016 'आसियान–भारत संबंधः एक नई मिसाल' विषय पर तीन दिन के दिल्ली संवाद VIII का उद्घाटन श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार ने किया। यह संवाद विदेश मंत्रालय ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनायलसिस (आईडीएसए), आरआईएस स्थित आसियान–इंडिया केंद्र (एआईसी), फिक्की, सीआईआई, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री (एआईएआई), इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), आदि के साथ साझेदारी में मिल कर आयोजित किया था। इस तीन दिन के संवाद में भारत और आसियान क्षेत्र के विभिन्न राजनेता, नीति निर्माता, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक नेता और थिंक टैंक व अकादमिक जगत के

प्रो. वी.एन. अत्री पैनल चर्चा में प्रमुख भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. एस.के. मोहंती, सुश्री रेणु पॉल एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं।

विभिन्न लोगों ने भाग लिया। आसियान और भारत के संबंधों से जुड़े विभिन्न आयामों को शामिल करने के लिए यह संवाद मुख्य रूप से तीन वर्ग में बंटा थाः व्यापार सत्र, मंत्रियों का सत्र और अकादमिक सत्र। आरआईएस के एआईसी ने 'रीइनविगोरेटिंग सिविलाइजेशनल लिंक्स' पर सत्र आयोजित किया। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने इसकी अध्यक्षता की। प्रो. हिमांशु प्रभा राय, पूर्व अध्यक्ष, नेशनल मोन्यूमेंट ऑथरिटी, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, श्री एडिन खू, पुसाका फाउंडेशन, मलेशिया के फाउंडर डायरेक्टर, प्रो. बदलास घोशाल, महा सचिव और निदेशक (अकादमिक), सोसाइटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज (एसआईओएस), नई दिल्ली, श्री सच्चिदानंद सहा, सलाहकार, प्रिह विहियर नेशनल ऑथरिटी, रॉयल गवर्मेंट ऑफ कंबोडिया और आर्कियोलॉजिकल कांप्लेक्स ऑफ संबोर प्रि कूक कंबोडिया के यूनेस्को विशेषज्ञ, इस सत्र के प्रमुख वक्ता के तौर पर मौजूद थे।

भारतीय विकास सहायता मंच के जयपुर और चेन्नई में क्षेत्रीय परामर्श

भारतीय विकास सहायता मंच—आरआईएस ने जयपुर में 22—23 दिसंबर, 2015 को तीसरा क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र के दौरान आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री ए. के. साहू, संयुक्त सचिव (डीपीए— II), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. वी. एस. व्यास, मानद प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (आईडीएस), जयपुर ने मुख्य भाषण दिया। डॉ. कौस्तुभ बंदोपाध्याय, निदेशक, पीआरआईए ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

भारत सरकार की माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज दिल्ली डॉयलॉग— VIII के दौरान अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री साहू ने ध्यान दिलाया कि भारत ने आजादी के समय से ही विकासशील देशों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 1950 के दशक की शुरुआत में ही कई फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। 1964 में इन स्कॉलरशिप को औपचारिक तौर पर आईटेक का हिस्सा बना दिया गया। क्षमता विकास के अलावा भारत का विकास में सहयोग कई और रूप में भी दिखाई दिया, इनमें वित्त, आपदा राहत आदि शामिल हैं। इस दौरान भारत के अंदर और दूसरे देशों में भी विकास के क्षेत्र में स्वयं सेवा संस्थाओं की अहमियत पर भी चर्चा की गई।

प्रोफेसर व्यास ने अपने कीनोट भाषण में 'कृषि और दक्षिणीय सहयोग' पर ध्यान खींचा। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भारत की विकास दर को ले कर संतोष जताया और साथ ही इस बात पर भी कि कृषि और ग्रामीण विकास भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति को संभव बनाने के लिए गेहूं और चावल में जेनेटिक शोध के लिहाज से दक्षिणीय सहयोग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अभी भी पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक, ऑर्गेनिक खेती, कीट नाशक, ऊर्जा प्रबंधन, जल संचयन तकनीक, ऊतक संवर्धन जैसी अग्रणीय तकनीक, खेती में आईटी का उपयोग और कर्ज व विपणन में संस्थानिक इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत संभावना है। उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में महज तकनीक के बदलाव से बात नहीं बनेगी, बल्कि संस्थानिक सहयोग भी जरूरी होगा और इस दिशा में भारत बहुत गंभीर योगदान कर सकता है।

तकनीकी सत्र के दौरान इन– भारत के विकास सहयोगय नजरिए और व्यवहारय विकास सहयोग और स्वयं सेवी संगठन, विकास सहयोग और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सीएसओ इंटरवेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास, विकास सहयोग का मूल्यांकण, उभरती चुनौतियां पर विचार हुआ।

इस दौरान तीन समानांतर सत्र भी आयोजित किए गए जिनमें क्षेत्रवार मूल्यांकण किया गया। पहला सत्र 'प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन' पर था। दूसरा सत्र 'ग्रामीण विकास' पर और तीसरा समानांतर सत्र 'स्वास्थ्य व शिक्षा' पर था।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका और विकास परियोजनाओं में उनकी प्रमाणित क्षमता पर भी चर्चा की गई। इसका भी उल्लेख किया गया कि एकेडमिया और

प्रो वी.एस.व्यास कंसलटेशन के दौरान संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री ए. के. साहु एवं डा. कौस्तव बंद्योपाध्याय भी दिखाई द रहे हैं।

स्वयंसेवी संस्थाओं का आपसी संबंध के महत्व की पहचान आगे के रास्ते को ले कर स्पष्टता होनी चाहिए।

दो दिन के विमर्श के दौरान जो मुख्य बिंदू उभर कर सामने आए वे दक्षिणीय सहयोग में भारत के विचार के लिहाज से बेहद अहम हैं।

चौथा क्षेत्रीय परामर्श एफआईडीसी की ओर से 15 मार्च, 2016 को चेन्नई में आयोजित किया गया। इसमें देश के दक्षिणी क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठन, अकादमिक जगत के लोग और नीति नियंता एक साथ आए ताकि भारत के विकास सहयोग और दक्षिणीय सहयोग पर चर्चा कर सकें। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री ए. के. साहू, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उद्घाटन भाषण दिया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (एमआईडीएस) के प्रो. जनकराजन श्रीनिवास ने मुख्य भाषण दिया। प्रो. शशांक भिडे, निदेशक एमआईडीएस ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

प्रो. चतुर्वेदी ने अपने स्वागत भाषण में मदद के प्रभाव पर अब तक के चार उच्च स्तरीय फोरा के इतिहास के बारे में बताया जिनमें बुसान 2011, एक्रा 2008, पैरिस 2005 और रोम 2003 शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ओर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की डेवलपमेंट असिस्टेंस कमीटी (डीएसी) ने किस तरह रोम (2003) की चर्चा का नेतृत्व किया जिसमें बताया गया कि मदद उपलब्ध करवाने वाले अपने संबंधित कर दाताओं को क्या उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी तरह पैरिस में 2005 में कुछ खास तरह के उपायों का प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रगति की निगरानी व्यवस्था और मदद के नतीजे का आकलन शामिल है।

तीसरे कार्यक्रम में एक्रा में ओईसीड–डीएसी ने यह तथ्य स्वीकार किया कि दक्षिणीय सहयोग, उत्तर–दक्षिण सहयोग से अलग है और दक्षिणीय सहयोग के वादों की नीव के तौर पर काम करेगी। हालांकि एड इफेक्टिवनेस पर चौथे उच्च स्तरीय फोरम (बुसान 2011) में ओईसीडी–डीएसी ने दक्षिणीय सहयोग को उत्तर–दक्षिण सहयोग तार्किक बनाने की मंशा जताई और इसे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं

चेन्नई में एफआईडीसी क्षेत्रीय परामर्श के प्रतिभागी

वाले ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट कॉपरेशन (जीपीईडीसी) का हिस्सा बनाना होगा।

प्रो. चतुर्वेदी ने उत्तर–दक्षिण सहयोग और दक्षिणीय सहयोग के बीच सैद्धांतिक अंतर का भी उल्लेख किया और साथ ही उत्तर–दक्षिण सहयोग कैसे वित्तीय विचारधारा पर आधारित है जबकि उत्तर–दक्षिण सहयोग ढ़ाचागत विचारधारा पर। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तहत ही डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन (डीपीए) के गठन की अहमियत को भी रखांकित किया। उन्होंने कहा कि डीपीए का काम निरंतर जारी है ताकि यह दक्षिण के देशों में भारत की ओर से शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में मदद कर सके।

एमआईडीएस के प्रो. जनकराजन श्रीनिवासन ने अपने मुख्य संबोधन में विदेशी मदद और विकास सहयोग की शुरुआत पर प्रकाश डाला और इस दौरान दो ध्रुवीय दुनिया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग में उत्तर–दक्षिण सहयोग से दक्षिणीय सहयोग के रूप में आए भारी बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। पहले उत्तर–दक्षिण सहयोग असमानता के आधार पर खड़ा था, हालांकि मंदी जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने दक्षिणीय सहयोग को मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान किया है। दक्षिणीय सहयोग की मांग–संचालित प्रकृति और कोई शर्त लागू नहीं करने की वजह से इसका उत्तर–दक्षिण सहयोग का विकल्प बनना आसान हो जाता है।

उन्होंने दक्षिण के देशों की गरीबी, भूख, कुपोषण, शहरी स्लम, मानव विकास संकेतक में खराब स्थिति, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा संसाधनों की कमी, पारिस्थितिकि और प्राकृतिक संसाधनों में क्षरण, पर्यावरण को नुकसान, जलवायु परिवर्तन का खतरा और बढ़ता उपभोक्तावाद, कचरे के उत्पादन में तेज बढ़ोतरी और इसके वैज्ञानिक निस्तारन की कमी जैसी साझा समस्याओं पर चर्चा की और साथ ही उत्तर–दक्षिण सहयोग के लिए एक समान पृष्ठ भूमि को जरूरी बताया ताकि सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

श्री साहू ने अपने उद्घाटन भाषण में विकास के साधनों और इसे हासिल करने के तरीकों पर सवाल करते हुए विकास को सही संदर्भ देने की कोशिश की। उनके मुताबिक भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी 20 फीसदी आबादी को गरीबी से बाहर निकालना है। हालांकि, भारत को दूसरे विकासशील देशों की ओर से झेली जा रही विकास संबंधी चुनौतियों का भी आभास है और भारत अपने विकास सहयोग कार्यक्रमों के जरिए इन्हें दूर करने में बढ़–चढ़ कर मदद कर रहा है।

श्री साहू ने भारतीय विकास सहयोग मंच जैसे प्लेटफार्म के महत्व पर भी जोर दिया जिसे दक्षिणीय सहयोग और भारत के विकास सहयोग को ट्रैक 2 के जरिए पूरा करने के लिए खड़ा किया गया है।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने 'भारत का विकास सहयोगः परिदृष्य और वास्तविकता' पर पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की। सेंटर फॉर चाइना स्टडीज के निदेशक श्री आर. एस. वासन और आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती ने इसमें वक्ता के तौर पर भाग लिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने विकास सहयोग और स्वयंसेवी संगठनों पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. भवानी आर. वी., प्रोग्राम मैनेजर, एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशनय डॉ. कौस्तुभ बंदोपाध्याय, निदेशक, पीआरआईएय श्री संदीप मुखर्जी, वाइस प्रेसिडेंट, हैंड इन हैंड इंडिया ने इसमें वक्ताओं के तौर पर भाग लिया।

इस दौरान दो समानांतर सत्र भी हुए जो कृषि पर केंद्रित थे। इनका संचालन डॉ. पी. जी. चंगप्पा, आईसीएआर, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकनॉमिक चेंज के नेशनल प्रोफेसर ने किया। इसी तरह फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर सत्र का संचालन डॉ. वाई. एस. यादव, निदेशक, बीओबीपी ने किया।

आरआईएस की विश्व व्यापार एवं विकास रिपोर्ट का लोकार्पण

नैरोबी में दसवें डब्लूटीओ मंत्रीस्तर सम्मेलन के साथ ही व्यापार उदारीकरण और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को मजबूती देने की प्रक्रिया ने अपना चक्र पूरा कर लिया। जो 1995 में जीएटीटी और डब्लूटीओ के साथ शुरू हुआ था वह ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां बहुपक्षीयता को बहुत सी चुनौतियां दिखाई दे रही थीं।

टीपीपी पर हस्ताक्षर किया जाना दुनिया के आर्थिक इतिहास में एक अभूतपूर्व बदलाव है। टीपीपी के साथ ही तीन बड़े क्षेत्रीय समझौते– टीटीआईपी, आरसीईप और एफटीएएपी को ले कर काफी प्रगति हुई है और आने वाले वर्षों में इनके पूरा हो जाने की उम्मीद है। ये चार क्षेत्रीय संगठन पहले से मौजूद क्षेत्रीय संगठनों से अपने स्वरूप, उद्देश्य और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के लिहाज से अलग हैं। प्रतिस्पर्धा नीति, श्रम मानक, पर्यावरण संबंधी विषय और सरकारी खरीद जैसे मुद्दे (अक्सर जिन्हें नए मुद्दे भी कहा जाता है) को क्षेत्रीय संगठनों में वैधता प्रदान करने के बाद इनको मल्टीलेटरल फोरम में भी उठाए जाने की संभावना बन जाती है।

इन मुद्दों पर चर्चा के लिए आरआईएस ने 'ट्रेड डेवलपमेंट, डब्लूटीओ और मेगा एफटीए' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन नैरोबी में डब्लूटीओ मिनिस्टेरियल कांफ्रेंस के दौरान 17 दिसंबर, 2015 को किया। इसमें साउथ सेंटर, जेनेवा और केआईसीसी, नैरोबी स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय की भी साझेदारी थी। इस मौके पर आरआईएस के प्रमुख प्रकाशन, ''विश्व व्यापार एवं विकास रिपोर्ट (डब्लूटीडीआर) का लोकार्पण गया जो "क्षेत्रीय, विश्व व्यापार और नए मुद्दे हैं। इस पर चर्चा भी आयोजित की गई। श्रीमती सुचित्रा दुरई, भारत की रिपब्लिक ऑफ कीनिया में उच्चायुक्त ने इस चर्चा की अध्यक्षता की। मुख्य वक्ताओं में प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महा निदेशक, आरआईएस,

कीनिया में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती सुचित्रा दुरई 'आरआईएस वर्ल्ड व्यापार एवं विकास रिपोर्ट : का लोकार्पण करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के प्रो. एस.के. मोहंती, आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, एवं जेनेवा, साउथ सेंटर के विशेष सलाहकार डा. कार्लोस कोर्रिया।

प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, डॉ. कार्लोस कोरिया, स्पेशल एडवाइजर, साउथ सेंटर, जेनेवा, डॉ. मोहम्मद रज्जाक, निदेशक, ट्रेड डिवीजन, कॉमनवेल्थ सचिवालय, लंदन, सुश्री सैन्या रीड स्मिथ, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, जेनेवा और अन्य शामिल थे।

भारत में क्लीनिकल ट्रायल नियमन पर कार्यशाला

आरआईएस ने भारत में क्लीनिकल ट्रायल नियमन पर नई दिल्ली में 2 दिसंबर, 2015 को कार्यशाला आयोजित की जिसमें इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही स्वास्थ्य अभियान मंच बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद भारत में क्लीनिकल ट्रायल को ले कर लाए गए हाल के बदलावों पर शोध दल की ओर से किए गए अध्ययन के तात्कालिक नतीजे भी साझा किए जाने थे। इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. एस. के. ब्रह्मचारी, पूर्व सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और महा निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने किया। इसमें भाग लेने वालों में डॉ. नंदिनी के. कुमार, पूर्व डीडीजी (एसजी), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), डॉ. के. सत्यनारायण, पूर्व डीडीजी, आईसीएमआर, डॉ. मनीशा श्रीधर, रिजनल एडवाइजर, दक्षिण–पूर्व एशियाक्षेत्रीय कार्यालय, डब्लूएचओ, डॉ. सुनीला गर्ग, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्यूनिटी मेडिसीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉ. सरला बालाचंद्रण, चीफ साइंटिस्ट, सीएसआईआर और परियोजना निदेशक, ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी (ओएसडीडी), डॉ. अनंत भान, रिसर्चर, ग्लोबल एक्शन फॉर हेल्थय डॉ. स्वाती सुबोध, सदस्य, एथिक्स कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूब्रोकोलोसिस एंड रेस्पिरेट्री डिजीजेज (एनआईटीआरडी), डॉ. मीरा शिवा, पूर्व चेयरपर्सन, हेल्थ एक्शन इंटरनेशल एशिया पैसिफिक (एचएआई–एपी), डॉ. संजीव शर्मा, हेड, क्लीनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट, अपोलो हॉस्पिटल, डॉ. एस विसालाक्ष्मी, सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट, कंसोर्टियम फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट (सीईएनटीएडी), सुश्री लीना मेघाने, रिजनल हेड, साउथ एशिया, एमएसएफ–एक्सेस कैंपेन, डॉ. वाई माधवी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसे, टेक्नालॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज (एनआईएसटीएडीएस), डॉ. रोली माथुर, आईसीएमआर शामिल थे। इनके अलावा आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी, और ओएसडीडी के पूर्व परियोजना निदेशक श्री जाकिर थॉमस ने भी इसमें हिस्सेदारी की। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में रेगुलेटरी मंजूरी प्रक्रिया, एथिक्स समितियों के काम–काज, पूर्व इंफोर्म्ड कंसेंट और मुआवजे के दिशा–निर्देश पर चर्चा हुई।

प्रो. एस. के. ब्रहमचारी कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) डा. नंदिनी के कुमार, डा. मनीषा श्रीधर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी एवं प्रो. टी.सी. जेम्स भी दिखाई दे रहे हैं।

डब्लूटीओ और एसडीजी पर सम्मेलनः नैरोबी मंत्रीमंडलीय सम्मेलन के समक्ष मुद्दे

नैरोबी, केन्या में दिसंबर, 2015 में आयोजित दसवें मंत्री स्तरीय सम्मेलन (एमसी 10) का दुनिया के अकेले बहुपक्षीय व्यापार संस्थान डब्लूटीओ के काम–काज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना था। दोहा डेवलपमेंट राउंड को जल्द से जल्द पूरा किया जाना है ताकि नियम– आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था कायम हो सके। इस व्यवस्था को टीपीपी जैसी वृहद स्वतंत्र समझौते के जरिए चुनौती तेजी से बढ़ रही है।

इसे ध्यान में रखते हुए, आरआईएस ने सेंटर फॉर डब्लूटीओ स्टडीज (आईआईएफटी), जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ मिल कर नैरोबी मिनिस्टीरियल बैठक से पहले दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में 23–24 नवंबर, 2015 को आयोजित किया गया। श्री सुधांशु पांडे, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महा निदेशक, आरआईएस, और प्रो. अभिजीत दास, हेड सेंटर फॉर डब्लूटीओ स्टडीज, नई दिल्ली ने स्वागत भाषण दिया। श्री मानब मजूमदार, असिस्टेंट सेक्रेटरी जेनरल (डब्लूटीओ), फिक्की, श्री प्रणव कुमार, हेड, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी डिवीजन, सीआईआई ने अपने वक्तव्य दिए। प्रो. थॉमस फ्यूस, हेड, ट्रेनिंग, द जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, बॉन ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

अपने संबोधन में श्री सुधांशु पांडे ने कहा यह चुनौती भरा दौर है। एमसी 10 को कोई खास इलाज बताए बिना ही उन्होंने कहा कि यह मोटे तौर पर एक बातचीत के लिए बैठक होगी। श्री पांडे ने दो दिन के सम्मेलन को दोहा विकास चक्र के नतीजों पर चर्चा करने की सलाह दी क्योंकि इसके मुख्य बिंदू, सिद्धांत और उद्देश्य में कोई व्यापक बदलाव नहीं आया है। उन्होंने सामूहिक, परिपक्व और उत्तरदायी रूप से एक–दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयासों की वकालत की। साथ ही कहा कि दुनिया लगातार वैश्वीकरण हो रहा है और तकनीकी की वजह से उत्पादन व उपभोग के केंद्र लगातार बदल रहे हैं। अगर असमानता बढ़ती रही तो यह हमारे लिए बेहतर कल का संकेत नहीं हो सकता। यह साझा जवाबदेही है और इसमें विकसित, विकासशील और न्यूनतम विकसित देशों को एक साथ मिल कर एमसी 10 में न्यूनतम समझौते को हासिल करने की कोशिश करनी

श्री सुधांशु पांडेय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) श्री मानब मजुमदार, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, प्रो. अभिजीत दास, श्री प्रणव कुमार एवं जर्मन डेवेलपमेंट इंस्टीच्युट के रिसर्चर श्री जोहान्स ब्लैंकेनबाच।

होगी ताकि सभी के लिए जीत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि दोहा विकास चक्र में कृषि मुख्य बिंदू था, क्योंकि विकासशील देशों की 65 फीसदी आबादी इसी पर आधारित है। इसके साथ ही विकासशील के साथ ही विकसित देशों के लिए भी लोक स्वास्थ्य सुविधाओं व सस्ती जेनरिक दवाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने अपने शुरूआती टिप्पणी में कहा कि एमसी 10 से पहले दो तरह के परस्पर विरोधी विचार पैदा हुए हैं। इसमें एक है विकासशील देशों की ओर से जिसमें कहा जा रहा है कि दोहा विकास चक्र को जारी रखा जाए। जबकि दूसरा विचार कुछ विकसित देशों की ओर से बढ़ाया जा रहा है, जिसके मुताबिक अब इसे समाप्त कर कोई नई पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के भारत–अफ्रीका फोरम सम्मेलन में दिए भाषण की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि विकसित देशों को दोहा चक्र के वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने नैरोबी मंत्रीस्तरीय सम्मेलन की सफलता को ले कर जी–20 की प्रतिबद्धता और पोस्ट नैरोबी व्यापार मुद्दों पर चल रही बातचीत पर हैरानी जताई। प्रो. अभिजीत दास और श्री मानब मुखर्जी, फिक्की तथा श्री प्रणव कुमार, सीआईआई ने भी अपने विचार साझा किए।

सम्मेलन में जो प्रमुख मुद्दे उठाए गए, वे हैं कृषि और मत्स्यपालन सब्सिडी, ट्रिप्स, ट्रेड एंड एक्सेस टू टेक्नालॉजी, डब्लूटीओ और संभावित नए मुद्दे, वृहद क्षेत्रीय समझौते और दोहा चक्र का भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और एसडीजी 12, ऐच्छिक मानक 2030 के एजेंडा को पूरा करने में कैसे मददगार हो सकते हैं, सस्टेनेबल विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, निगम स्वैच्छिक मानकों का अपनी वैश्विक मूल्य चेन को नए सिरे से डिजाइन करने में कैसे उपयोग करे, नैरोबी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए मानकों की प्रासंगिकताः डब्लूटीओ सतत उपभोग और उत्पादन को कैसे बढ़ावा दे सकता है। प्रख्यात वक्ताओं के साथ ही उद्योग जगत, अकादमिक जगत और मीडिया के विभिन्न लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर ईएएस सम्मेलन

विदेश मंत्रालय ने आरआईएस के एआईसी और नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) के साथ मिल कर समुद्री सुरक्षा और सहयोग पर पूर्व एशिया सम्मेलन (ईएएस) के सदस्य देशों के लिए नई दिल्ली में 9–10 नवंबर, 2015 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सभी ईएएस देशों ने अपने अधिकारियो को सम्मेलन के लिए नामित किया और कुल मिला कर वरिष्ठ अधिकारियों सहित सौ लोगों ने दो दिन के कार्यक्रम में भाग लिया। एंबेस्डर अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने कीनोट संबोधन किया। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन

श्री अनिल वाधवा सम्मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. प्रबीर डे, डा. विजय सखुजा, राजदूत वी.एस.शेषाद्रि, श्री दीपक शेट्टी एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं।

चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। एंबेस्डर वी. एस शेषाद्री, वाइस अध्यक्ष, आरआईएस ने शुरुआती संबोधन किया। डॉ. विजय सखूजा, निदेशक, नेशनल मेरिटाइम फाउंडेशन ने विशेष संबोधन किया। श्री दीपक शेट्टी, शिपिंग महा निदेशक, ने विशेष भाषण दिए। प्रो. प्रबीर डे, संयोजक, एआईसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

समुद्री सुरक्षा और सहयोग तथा समुद्री संपर्क से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहराई से विमर्श करने के लिए सम्मेलन को छह अलग–अलग सत्रों में बांटा गया था। ये सत्र इस तरह थेः समुद्री मामलों पर ईएएस का परिप्रेक्ष्य, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उभरता सुरक्षा ढांचा, समुद्री संपर्कः व्यापार के लिए आधार, ब्लू अर्थव्यवस्था और समुद्री संरक्षण, कॉमन पब्लिक गुड्स की कॉपरेटिव डिलीवरी और भविष्य की राह। समुद्री मामलों में ईएएस सदस्य देशों के लिए मददगार साबित होने वाले विभिन्न मामलों पर सम्मेलन में चर्चा कर इनकी व्याख्या की गई और इन्हें व्यस्थित रूप से पेश किया गया। प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने अंतिम दिन सम्मेलन का सार प्रस्तुत किया और धन्यवाद प्रस्ताव भी पेश किया।

नवीन प्रवर्तन वित्त नीति के जरिए स्वच्छ ऊर्जा प्लेटफार्म के निर्माण पर चर्चा बैठक

आरआईएस ने इनोवेटिव वित्त नीति के जरिए स्वच्छ ऊर्जा प्लेटफार्म निर्माण पर नई दिल्ली में 18 दिसंबर, 2015 को चर्चा बैठक का आयोजन किया। प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने आरंभिक टिप्पणी की। कोएलीशन फॉर ग्रीन कैपिटल के कार्यकारी निदेशक श्री जेफ्रे स्कूब इसमें मुख्य वक्ता थे। द इनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) के फेलो डॉ. नित्या नंद, और आरआईएस से डॉ. सब्यसाची साहा ने चर्चा में भाग लिया।

वक्ताओं ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में सरकारों की ओर से अपनाए जा रहे नवीन प्रवर्तन वित्तीय तरीकों की चर्चा की गई। उन्होंने जोर दे कर कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए पर्याप्त और पहुंच योग्य पूंजी बेहद आवश्यक है। ऊर्जा कुशलता और वितरित उत्पादन को हासिल करने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा इस तकनीक की शुरुआती लागत ही है। यह बाधा तीसरे पक्ष की ओर से निवेश के जरिए दूर हो सकती है। निजी क्षेत्र जो इस समय स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने में हिचकिचा रहा है, उसे साथ लेने के लिए दुनिया भर में सरकारें सरकारी–निजी साझेदारी के नए ढांचे तैयार कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने वाले ये सार्वजनिक प्राधिकरण या ग्रीन बैंक दुनिया के सभी हिस्सों में लांच किए गए हैं और प्रत्येक एक अमेरिकी डॉलर

श्री जेफ्री सक्ब बैठक को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) डा. नित्या नंदा, प्रो. राम उपेंद्र दास एवं डा. सव्यसाची साहा।

के सरकारी निवेश के मुकाबले दस अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश आकर्षित कर पा रहे हैं। ये वित्तीय ढांचे स्वच्छ ऊर्जा के बाजार को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जिसकी मदद से बाजार की ताकतें मूल्य प्रभावी स्वच्छ ऊर्जा को विस्तार देने में कामयाब हो सकती है।

आसियना–भारतः एकीकरण और विकास पर गोलमेज सम्मेलन

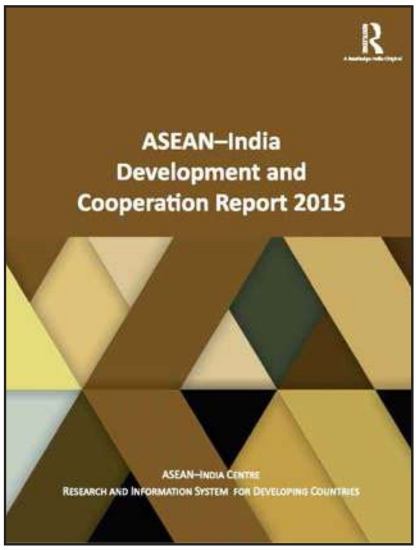

आरआईएस के एआईसी ने 'आसियान–भारतः एकीकरण और विकास' पर 27 अक्तूबर, 2015 को नई दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस मौके पर एआईसी के अध्ययन 'आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015' को भी जारी किया गया। यह सम्मेलन नवंबर, 2015 में क्वालालंपुर में होने वाले 13वें आसियान–भारत सम्मेलन और 10वें पूर्वी एशिया सम्मेलन का कर्टेन रेजर कार्यक्रम भी था। आरआईएस के महा निदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने कीनोट भाषण दिया। श्री श्याम सरन, अध्यक्ष आरआईएस ने विशेष भाषण दिया। श्री श्रीकांत सोमनी, अध्यक्ष, सीआईआई (एनआर) और सोमनी सेरामिक्स लि. के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने भी विशेष संबोधन किया। प्रो. प्रबीर डे, संयोजक एआईसी ने 'आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015' पर प्रस्तुती दी। आसियान–भारत रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक और क्षेत्रीय एकीकरण के नए ढांचों के सामने मौजूद विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए दो तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। राउंडटेबल के अंतिम सत्र में प्रो. प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

ट्रांस पैसिफिक साझेदारी (टीपीपी) पर परिचर्चा

ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके गैर–सदस्यों और खास कर भारत के लिए इसके नतीजों को ले कर बहुत से नजरिए हैं। टीपीपी के व्यापक असर पर चर्चा के लिए आरआईएस ने नई दिल्ली में 16 अक्टूबर, 2015 को परिचर्चा आयोजित की। श्री राजीव खेर, पूर्व वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने इसकी

श्री अनिल वाधवा 'आसियान–इंडिया डेवेलपमेंट एवं कोपरेशन रिपोर्ट 2015' नामक एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट का अनावरण करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) प्रो. प्रबीर डे, श्री श्याम सरन, श्री श्रीकांत सोमानी, सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (आसियान–एमएल), विदेश मंत्रालय; एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी

शुरुआत की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महा निदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। प्रमुख वक्ताओं में शामिल थेः प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस, श्री बिपुल चटर्जी, डिप्टी एक्जेक्यूटिव डायरेक्टर, सीयूटीएस इंटरनेशनल, और प्रो. टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस।

श्रे खेर का कहना था कि चुनौती यह नहीं है कि टीपीपी में शामिल हुआ जाए या नहीं, बल्कि असली चुनौती अपने अंदर झांकने की चुनौती है। टीपीपी कोई अकेली इकाई नहीं है, बल्कि व्यापक वैश्विक–ढांचे से संबंधित है। जब तक उत्पादन और सेवा के घरेलू मुद्दों को संभाल नहीं लिया तब तक हम टीपीपी की चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने जोर दिया कि ताजा मामलों को देखते हुए यह भारत के व्यापक आर्थिक और वाणिज्यिक हित में होगा कि वह आरसीईपी को रफ्तार देने में मदद कर। टीपीपी को ले कर डरे रहने की बजाय भारत को घरेलू आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए।

प्रो. एस. के. मोहंती के मुताबिक भारत को टीपीपी में शामिल होना चाहिए या नहीं, यह बहुत गंभीर सवाल है। टीपीपी में श्रम, पर्यावरण, सरकारी खरीद, आईपीआर आदि को ले कर जो प्रस्तावित मानक हैं, वे भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत को आरसीईपी और दूसरे उदार व्यापारिक समझौतों को ले कर ज्यादा जोर देना चाहिए। भारत को बहुत बारीकी से बहुपक्षीय, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौतों के फर्क को समझना होगा।

प्रो. टी. सी जेम्स कहते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में सस्ती दवा की उपलब्धता को बाधित करने वाले कई प्रावधान हैं। 'ज्ञात उत्पाद के नए उपयोग'को भी पेटेंट प्रदान करने के प्रावधान को ले कर सघर्ष जारी है, क्योंकि इसका असर बहुत व्यापक होगा और यह एवर ग्रीनिंग की ओर ले जा सकता है। इसी तरह फार्मा पेटेंट को विशेष स्थान देते हुए उन्हें दूसरी तकनीक के मुकाबले वरीयता वाली श्रेणी में रखने और पेटेंट अवधि को नियमन संबंधी देरी से समायोजित करने से भी इनके पेटेंट की अवधि बढ़ जाएगी। यह समझौता भारतीय औषधि उद्योग के लिए विपणन मंजूरी पाने के लिहाज से नई बाधा खड़ी कर देगा जो ज्यादातर जेनरिक दवाओं पर आधारित है।

सीयूटीएस इंटरनेशनल के श्री बिपुल चटर्जी ने कहा कि, टीपीपी का अपने आप में हमारे देश पर ज्यादा असर नहीं होगा। टैरिफ संबंधी असर भी सामान्य ही है।

आरआईएस के प्रो. टी.सी. जेम्स संगोष्ठी को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) श्री बिपुल चटर्जी, प्रो. एस.के.सोमानी, श्री राजीव खेर एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

लेकिन घरेलू मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसमें ई–कॉमर्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। कृषि के संबंध में आ रहे गतिरोध को दूर करने की जरूरत है तथा जमीन, श्रम, और विपणन क्षेत्रों आदि में सुधार की जरूरत है। टीपीपी को इसके मौजूदा स्वरूप में बहुत नरम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी, इसलिए भारत में टीपीपी को ले कर चिंता करने की जरूरत नहीं है।

रिजाल–नेहरू व्याख्यान

महामहिम श्री एल्बर्ट एफ. डेल रोशेरिओ, (मंत्री) विदेश मंत्रालय, द फिलिपाइंस द्वितीय राइजल–नेहरू भाषण देते हुए

एआईएस ने नई दिल्ली में दूसरे रिजाल–नेहरू व्याख्यान का आयोजन 14 अक्टूबर 2015 को किया. प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत वक्तव्य दिया. श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने आरंभिक वक्तव्य दिया. सुश्री मोनिका मोहता, अतिरिक्त सचिव (साउथ), विदेश विभाग ने विशेष टिप्पणी की. महामहिम अलबर्ट एफ. डेल रोसारिओ, विदेश मामलों के मंत्री के सचिव, रिपब्लिक ऑफ फिलिपिंस ने "चुनौतियाँ और अवसरः फिलिपिंस और भारत के संबंधों में आगे का रास्ता' विषय पर अपना विशेष व्याख्यान दिया. प्रोफेसर प्रवीर डे, संयोजक, एआईसी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया. व्याख्यान के बाद आपसी बातचीत के सत्र में फिलिपिंस के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और अकादमिक जगत के लोगों भाग लिया.

कृषि में भारत–अफ्रीका सहयोग

आरआईएस ने 6 अक्टूबर 2015 को हैदराबाद में 'कृषि क्षेत्र में भारत–अफ्रीका सहयोग/अवसर और चुनौतियाँ' विषय पर एक वृहद अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेस का आयोजन किया। इस कांफ्रेंस का उद्देश्य भारत–अफ्रीका के बीज क्षेत्र में जो मुश्किलें और अवसर हैं, उस विषय पर शोध अध्ययन के निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार करना था। यह शोध आरआईएस ने आईडीएस (ससेक्स, यूके), इआईएआर (एडिस अबाबा, इथोपिया) और सीएबीइ (नैरोबी, केन्या) के साथ मिल कर किया था।

डॉक्टर आर आर हांचिनाल, अध्यक्ष, पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने शुरुआती सत्र का अध्यक्षता की। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदशक, आरआईएस ने स्वागत वक्तव्य दिया। मिस्टर एम प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नेशनल सीड एसोसिएशन (एनएसओआई) और सीएमडी, नूजिवेडु सीड्स ने मुख्य भाषण दिया।

डा. आर.आर. हांचिनल सम्मेलन को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) डा. पाकी रेड्डी, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री एम. प्रभाकर राव, डा. दिरान मकिंडे एवं डा. डोमिनिक ग्लोवर।

पहला सत्र 'इंडिया–अफ्रीका कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर' के ऊपर था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर डायरन माकिंडे, निदेशक, एबीएनइ, एनइपीएडी, बुरकिना फासो ने की। पैनल में डॉ पक्की रेडी, एग्री बायोटेक फांडेशन, हैदराबाद, मि. एस मखीजा, स्ट्रेजिक एडवाइजर, जैन इरीगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, नई दिल्ली, डॉ वी एन कुलकर्णी, उपाध्यक्ष (रिसर्च एंड डेवलपमेंट), जे के एग्री–जेनिटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, डॉ एलानगोवन एम, रिसर्च लीड, एडवांता और डॉ के रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस शामिल थे।

दूसरा सत्र, जो आरआईएस/सीएबीइ/इआईएआर/आईडीएस के भारत–अफ्रीका बीजक्षेत्र के ऊपर अध्ययन पर था उसकी अध्यक्षता प्रो. करीम मारेडिया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए ने की। श्री एम प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआई) और सीएमडी, नूजिवेडू सीड्स इस सत्र के उपाध्यक्ष थे। इस सत्र के वक्ताओं में प्रो सचिन चतुर्वेदी, डॉ हैनिनगटोन ओडामे, इडी, सीएबीइ, नौरेबी, केन्या और डॉ डॉमनिक ग्लोवर, रिसर्च फेलो, आईडीएस, ससेक्स, यूके शामिल थे। इस सत्र में चर्चा में भाग लेने वालों में डॉ सिमोन मैना, प्रमुख (सीड सर्टिफिकेशन), केइपीएचआईएस, नैरोबी, केन्या, डॉ डैनियल ब्राडले, डीएफआईडी, इंडिया, डॉ कल्याण गोस्वामी, इडी, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली, और डॉ यू एस बैग, निदेशक, नाथ सीड्स, औरंगाबाद शामिल थे।

तीसरा सत्र 'सीड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकाः ऑपुरच्यूनिटीज एंड चौलेंजेस' के ऊपर डॉ टी पी राजेंद्रन, विजिटिंग फेलो, आइआईएस के द्वारा था। इस सत्र में डॉ अरविंद कपूर, रासि सीडस, गुरगांव, श्री मनीष त्यागी, बिजनेस मैनेजस (सीडस), इएलगोन केन्या लिमिटेज, नैरोबी, श्री कौस्तुभ जोशी, मार्केटिंग मैनेजर (अफ्रीका), एडवांता सीडस, डॉ जय सिंग, एमडी और सीइओ, साकाता सीड इंडिया, और मि. सेंनथिल कुमारन, एरिया मैनेजर (अफ्रीका), असथोर एग्रीकोला, इथोपिया पैनलिस्ट के रूप में मौजूद थे।

चौथा सत्र 'डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेशन्स इन सीड सेक्टर कोलाबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका' के ऊपर था, जिसकी अध्यक्षता के डॉ. राजा रेड्डी, शोध निदेशक, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद ने की। डॉ सिमोन मैना, प्रमुख (सीड सर्टिफिकेशन), केइपीएचआईएस, नैरोबी, केन्या, डॉ पी ओर ओजो, डीडी, नाइजेरिया सीड कौंसिल, अबूजा, नाइजेरिया, डॉ केसावुलु, प्रोफेसर, आचार्य एन जी रंगा एग्री. यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, डॉ रूथ मबाबजि, निदेशक, नेशनल कौंसिल ऑफ एस एंड टी, कंपाला, उगांडा, प्रो करीम मारेडिया, प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए, और प्रो. टी सी जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस ने इस सत्र में भाग लिया।

अंतिम सत्र की अध्यक्षता डॉ टी पी राजेंद्रन ने की। डॉ हैनिनगटोन ओडामे, इडी, सीएबीइ, नैरोबी, केन्या, डॉ डेनियल ब्राडले, डीएफआईडी इंडिया, और डॉ कल्याण गोस्वामी, इडी, नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दिल्ली ने आगे के रास्ते पर विचार व्यक्त किए। डॉ रामा राव, निदेशक एनएएआरएम, हैदराबाद ने समापन वक्तव्य दिया। डॉ अमित कुमार, रिसर्च एसोशिएट, आर आईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव किया।

एशियान–इंडिया वायुक्षेत्र में संयोजकता के ऊपर गोलमेज

आईआरएस के तहत एशियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) ने 'एशियान–इंडिया एयर कनेक्टिविटी' विषय के ऊपर 28 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में एक गोलमेज का आयोजन किया. प्रो प्रबीर डे, संयोजक, एआईसी ने स्वागत वक्तव्य दिया। श्री अनिल

वाधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया. श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने आरंभिक भाषण दिया। श्री अनिल श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (एएस), नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया। गोलमेज का पहला सत्र 'एयर ट्रांसपोटेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथइस्ट एंड इस्ट एशिया' विषय के ऊपर था जिसकी अध्यक्षता डॉ सनत कौल, अध्यक्ष, इंटरनेशनल फांउडेशन फॉर एविएशन, एयरोस्पेस एंज डेवलपमेंट (आईएफएएडी), नयी दिल्ली ने की। सुश्री पूजा कपूर, संयुक्त सचिव (एएमएल), विदेश मंत्रालय ने विशेष भाषण दिया। प्रो प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने 'एशियान–इंडिया एयर कनेक्टिविटि' अध्ययन पर अपनी प्रस्तुति दी। डॉ शेफाली जुनेजा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विशेष टिप्पणी की। दूसरा सत्र जो 'एशियान–इंडिया ओपन स्काईः ऑपरच्यूनिटीज एंड चौलेंजेस' विषय पर था उसकी अध्यक्षता श्री सतेंद्र सिंह, पूर्व महानिदेशक, डायरेक्टोरेट जेनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए), नई दिल्ली ने की। एआईसी के डॉ दुराईराज कुमारास्वामी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मलेन की समाप्ति हुई।

आरआईएस एवं एआईसी के अध्यक्ष श्री श्याम सरन गोलमेज के दौरान उद्घाटन भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) के समन्वयक प्रो. प्रबीर डे; नागरिक उड़डयन मंत्रालय (एमओसीए) में संयुक्त सचिव (एएस) श्री अनिल श्रीवास्तव; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा; एवं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (एएमएल) सुश्री पूजा कपूर।

सतत विकास के लक्ष्यों पर परामर्श

भारत सरकार के नीति आयोग, भारत में यूनाइटेड नेशन, भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआइडीसी) और ऑब्जरवर रिसर्च फाउंडेशन (ओराएफ) के सहयोग से आरआईएस ने नयी दिल्ली में 9 सितंबर 2015 को 'सतत विकास के लक्ष्यों पर परामर्श' का आयोजन किया। इसका आयोजन न्यूयार्क में 22–27 सितंबर 2015 के बीच हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्पेशल सेशन से पहले किया गया।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र के आवासीय संयोजक और यूएनडीपी के भारत में आवासीय प्रतिनिधि मि. यूरी एफानासिव ने मेहमानों का स्वागत किया। मिस सिंधुश्री खुल्लर, चीफ एक्सक्यूटिव आफिसर, नीति आयोग ने उद्घाटन भाषण दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने अध्यक्षीय टिप्पणी की। श्री पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव (यूएनइएस), विदेश मंत्रालय ने विशेष टिप्पणी की। उद्घाटन सेशन में समापन टिप्पणी एफआईडीसी के अध्यक्ष और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू की डीन प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय ने

भारत सरकार के नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सिंधुश्री खुल्लर परामर्श में स्वागत भाषण देती हुई। चित्र में (दायें से बायें) एफआईडीसी की चेयरमैन एवं जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की डीन प्रो. अनुराधा शिनॉय; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (यूएनईएस) श्री पुनीत अग्रवाल; आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; यूएन रेजीडेंट कॉर्डिनेटर एवं भारत में यूएनडीपी रेजीडेंट रिप्रजेंटेटिव, श्री युरी अफानासिएव; एवं आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

दिया। चर्चा में शामिल वक्ताओं ने नोट किया कि सतत विकास लक्ष्य बहुत ही जटिल है। साथ ही इन उद्देश्यों के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर भी चर्चा की। चर्चा में शामिल वक्ताओं ने इस पर भी रोशनी डाली कि किस तरह एमडीजीज और एसडीजीज भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में चिह्नित वैकासिक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। इस बात पर जोर दिया गया कि विकास और दक्षिणीय सहयोग मुद्दा में सबसे ऊपर है और यह पारंपरिक दानदाताओं और नए साझेदारों के साथ काम करने के नवीन तरीकों को भी समाहित किए हुए है। एसडीजीज को पूरा करने के राह में जो चुनौतियाँ हैं उस पर भी चर्चा की गई। इस बात की बातचीत की गई कि 12वें पंच वर्षीय योजना में मात्र 25 सूचक थे। आंकड़ों के अभाव में इनमें से कई सूचकों की पड़ताल नहीं हो पाई। एसडीजीज अपने 169 लक्ष्यों के साथ और भी महत्वाकांक्षी है।

इस मशविरे के दौरान आरआईएस ने अपने जर्नल एशियन बयोटेक्नालाजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू (एबीडीआर) पर एसडीजीज के विशेष अंक का भी विमोचन किया। संस्था ने एसडीजीज को समर्पित एक नए वेब पेज का भी अनावरण किया

मशिवरे के तकनीक सत्रों में इन विषयों पर विचार–विमर्श हुआ, स्वास्थ, कृषि और पोषण के संबंधित सुरक्षा और मानवीय विकासके ऊपर एसडीजीज, विज्ञान, नवाचार और तकनीक तक पहुँच, एसडीजीजः समेकित वृद्धि, लिंग और संवहनीयता, एसडीजीजः ऊर्जा और पर्यावरण, एसडीजीजः उद्योग की भूमिका, स्वयं सेवी संस्थाए और मीडिया और एसडीजीजः लागू करने से जुड़े मुद्दों, निगरानी, राज्यों की भूमिका और वैश्विक वचनबद्धता उनमें शामिल हैं।

दक्षिण एशिया विकास एवं सहयोग पर रिपोर्ट 2015 का लोकार्पण

नयी दिल्ली में 25 जून 2015 को आरआईएस के प्रमुख प्रकाशन साउथ एशिया डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन रिपोर्ट 2015(एसएडीसीआर) का लोकार्पण किया। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, माननीय रेलमंत्री, भारत सरकार ने किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी,

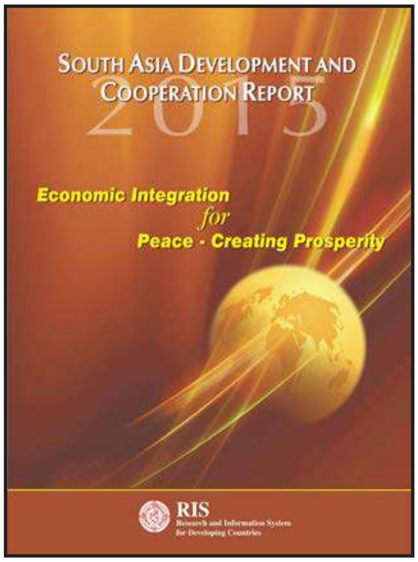

महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की।

प्रो दीपक नैय्यर, मानद प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में और साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज (एसएसीइपीएस) के को–चेयर, श्री ए. एम गोंडाने, संयुक्त सचिव (सार्क), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और महामहिम मि. शैयदा मोहम्मद अब्दाली, इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान के भारत में राजदूत ने भी उद्घाटन सत्र में विशेष टिप्पणी की प्रो. राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। कार्यक्रम में 'इकॉनामिक कोऑपरेशन फार इकानॉमिक डेवलपमेंट इन साउथ एशिया' और 'न्यू चौलेंजेस विफोर सार्क' विषय पर भी सत्र आयोजित किए गए थे।

महामहिम श्री लयोनपो डागो तेसरिंग, भारत में भूटान के पूर्व राजदूत ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। डॉ. कविता ए. शर्मा, अध्यक्ष, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नयी दिल्ली और श्री जयंत प्रसाद इस सत्र में शामिल थे। श्री अरविंद मेहता, संयुक्त सचिव (सार्क), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने समापन वक्तव्य दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजदूतों, सरकारी अधिकारीओं, नीतिनिर्माता, अकादमिक जगत से जुड़े लोग, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और मीडिया के लोगों ने भाग लिया।

यह रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों, मसलन वस्तु और सेवा क्षेत्र में कारोबार, निवेश, कारोबार में सहूलियत, जुड़ाव, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और तकनीक, विकास में सहयोग और सामाजिक आधारभूत ढाँचा के लिए ठोस नीतिगत सुझाव देता है।

दक्षिण एशिया के बारे में प्रभावी आख्यान यह है कि यह दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काम–धाम ठीक से नहीं होता है और जहाँ कारोबार के लिए आपसी जुड़ाव बेहद कम और धीमा है। एसएडीसीआर 2015 का कहना है कि यह सांख्यिकीय दृष्टि

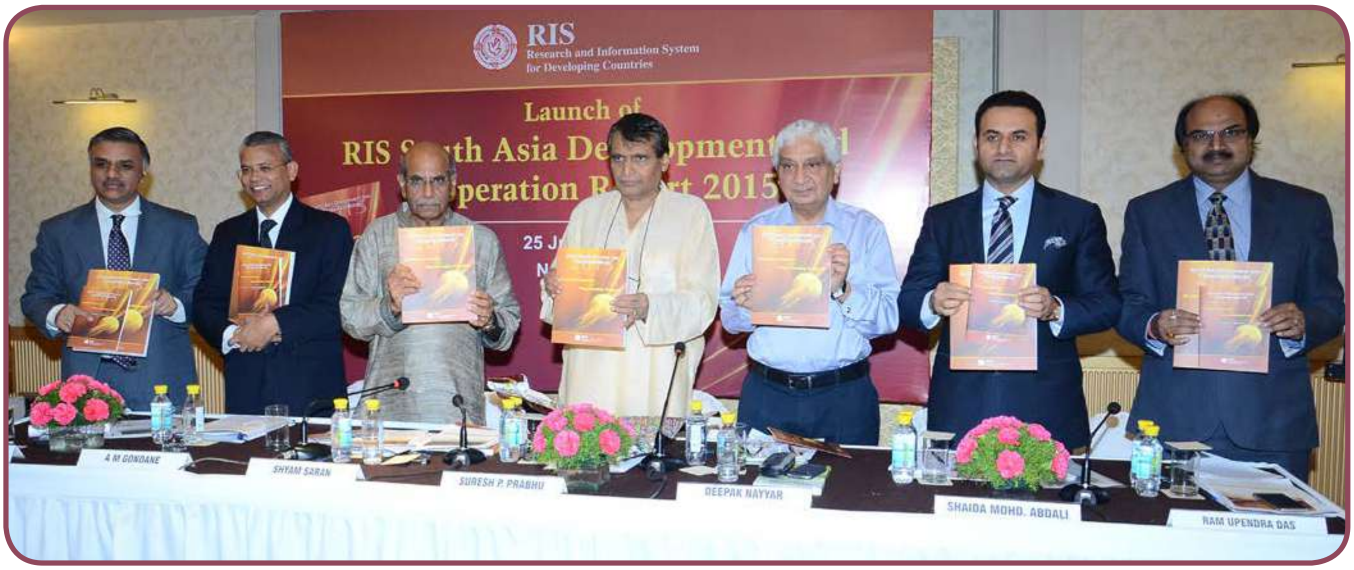

भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ''दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015' नामक एआईसी–आरआईएस रिपोर्ट का लोकार्पण करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सार्क) श्री ए. एम. गोंडाने ;आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; नई दिल्ली स्थित जेएनयू के इमिरेटस ऑफ इकोनोमिक्स, एवं साउथ एशिया सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज (एसएसीईपीएस) के को–चेयर प्रो. दीपक नायर; भारत में इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के राजदूत महामहिम शैदा मोहम्मद अब्दाली तथा आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास।

से गलत है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देता है कि भारत के नेतृत्व में वर्तमान में यह दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तरह ही 2008–09 में आए वैश्विक आर्थिक मंदी से यह क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बात करें तो सार्क आकार में अन्य क्षेत्रीय गठजोड़े जैसे, एएसइएएन, एमइआरसीओएसयूआर, एसएसीयू, एसएडीसी, सीओएमइएसए, जीसीसी और सीएआआईसोओएम से बड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वृद्धि की जो गति है उसे लंबे समय तक जारी रखा जाना चाहिए। इसे पाने का एक जरिया यह है कि क्षेत्रिय कारोबार को बढ़ावा दिया जाए।

यह रिपोर्ट इस गलहफहमी को भी दूर करता है कि दक्षिण एशिया में कारोबार के लिए आपसी मेल–जोल कम और धीमा है। सार्क के तत्वावधान में दक्षिण एशियाई क्षेत्र इस मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। दुनिया के अन्य देशों से होने वाले कारोबार के अनुपात का 5–6 प्रतिशत इस क्षेत्र में आपसी कारोबार से होता है। तथ्य यह है कि दोनों क्षेत्रों के साथ कारोबार एक ही गति से आगे बढ़ रहा है जिससे दोनों का अनुपात 5–6 प्रतिशत के इर्द–गिर्द ही स्थिर रहता है। असल में, साफ्टा (एसएएफटीए) की सफलता इस तथ्य में निहित है कि सार्क के देशों में आपसी कारोबार साफ्टा संधि के लागू होने के बाद दुगुना हो गया। अंतक्षेत्रीय निर्यात 2006 में जहाँ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं 2013 में बढ़ कर यह 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

हाल के अनुमान से ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया में विधिवत कारोबार 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच 2018 तक हो सकता है यदि सदस्य देशों के बीच पूरी तरह से सीमा शुल्क (टैरिफ) में उदारीकरण, कारोबार में सरलीकरण और उत्पादकता में सुधार की नीति अपनाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार के लिए एक विशाल संभावना है जिसे पूरी तरह से पकड़ा नहीं जा सका है। यह कारोबार 2018 तक 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकता है, बशर्ते कि संवेदनशील सूचियों, उपयुक्त एनटीबी और सेवा क्षेत्र में कारोबार की पूर्णता के लिए आपसी समझौते के लिए पर्याप्त कदम सुनिश्चित किए जाए।

दक्षिए एशिया भले ही बाहरी सहायता पर बड़ी मात्रा में निर्भर हो सकता है लेकिन यह आख्यान बदल रहा है। भारत के इतर, साउथ–साउथ सहयोग के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच वैकासिक साझेदारी की शुरुआत हुई है। रिपोर्ट इस बात पर बल देता है सार्क डेवलपमेंट फोरम की जल्दी से जल्दी शुरूआत हो ताकि क्षेत्र में वैकासिक मुद्दों पर बात–चीत हो सके। साथ ही रिपोर्ट यह रेखांकित करता है कि किस तरह एस एंड टी सहयोग का इस्तेमाल ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ, जो हमारे सामने आईं हैं, उसका सामना किया जाए और कम से कम कार्बन वृद्धि की तरफ बढ़ा जाए। साथ ही सार्क उपग्रह के विकास भी जरूरत है, जिसकी बात भारत के प्रधानमंत्री ने की। इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से वास्तविक समय में वैज्ञानिक आंकड़ों के मार्फत निपटा जा सके।

'इकॉनामिक इंटिग्रेशन फॉर पीस–क्रिएटिंग प्रास्पेरटी' के मुद्दे पर इस रिपोर्ट का केंद्र बिंदु है जो काठमांडू (2014) 18वें सार्क सम्मेलन की थीम से मेल खाता है। रिपोर्ट इस बात पर बल देता है कि किस तरह आर्थिक सहयोग से क्षेत्र में समृद्धि पाई जा सकती है, जो आगे 'शांति निर्माण'का पथ प्रशस्त करेगी। रिपोर्ट आपसी सहयोग के प्रयासों में के स्वरूप परिवर्तन (पैराडाइम शिफ्ट) पर बल देता है।

भारत–कोरिया सीइपीएः प्रगति का एक मूल्यांकन

श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व), भारत सरकार ने नयी दिल्ली में 8 सितंबर 2015 को एआईसी–आरआईएस के रिपोर्ट 'इंडिया–कोरियाः एन अप्रैजल ऑफ प्रोग्रेस' जारी किया। श्री वाधवा ने अपने विशिष्ट भाषण में एआईसी और आरआईएस का इस उपयोगी रिपोर्ट लाने के लिए तारीफ की। इंडिया–साउथ कोरिया कंप्रिहेनसिव इकॉनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीइपीए) के लागू होने के पाँच साल बाद दोनों देश सहमित को आगे बढ़ाने और उत्पादन के ज्यादा क्षेत्रों को शामिल किए जाने को लेकर बातचीत शुरू कर चुके है। सरकार कोरिया के साथ सभी तरह के अवसरों को खोजने और उससे लाभ उठाने की दिशा में काम करने को तत्पर है।

प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस और एआईसी ने आरंभिक वक्तव्य दिए। श्री अमिताभ कांत, सचिव, डिपार्टमेंट आफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपनी विशेष टिप्पणी में रेखांकित किया कि यह रिपोर्ट सरकार को सहायता पहुँचाएगी जब दोनों देश समझौते को और आगे ले जाने, अपग्रड करने के लिए मशवरा प्रदान। श्री वी एस शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस और एआईएस, जो इस अध्ययन के मुख्य शोधकर्ता हैं, ने इस अध्ययन के ऊपर एक प्रस्तुति दी। श्री एस.आर. तयल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारत के पूर्व राजदूत ने भी भारत–कोरिया के सीइपीए को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचारों, अनुभवों को प्रस्तुत किया।

यह रिपोर्ट इस मायने में अलहदा है कि यह पहली बार इस बात की आलोचनात्मक समीक्षा करता है कि एफटीएएस जो लागू है और भारत की जिसमें सहभागिता है उन्हें से अमल में लाया गया है और क्या और भी रास्ते हैं जिस पर चल कर हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह इस बात की भी समीक्षा है कि क्या इसे जिस तरह से लागू किया गया है उसमें सुधार की गुजांइश है और इस बारे में ठोस सलाह भी देता है। यह इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि क्या इस स्तर पर सीइपीए को और परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा रिपोर्ट का लोकार्पण करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस एवं एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी; आरआईएस एवं एआईसी के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्रि; भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री संजय चढ्ढा।

'सीएलएमवी के साथ भारत की आर्थिक एकीकरण की रणनीति' रिपोर्ट का विमोचन

सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार, ने इंडियाज स्ट्रेटेजी फॉर इकॉनामिक इंटिग्रेशन विद सीएलएमवी रिपोर्ट का दिल्ली में 14 अगस्त 2015 को विमोचन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार इस रिपोर्ट को सामने लेकर आई है। कार्यक्रम के आरंभ में श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस, नयी दिल्ली ने अपने विचार रखे। श्री रवि कपूर, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने रिपोर्ट की तैयारी के पीछे क्या वजह रही और इसे कैसे तैयार किया गया उस पर अपनी प्रस्तुति दी। महामहिम मि. तोन सिंह नाह, भारत में वियतनाम के राजदूत ने विशेष वक्तव्य दिया। प्रो राम उपेंद्र दास, आरआईएस, जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है, इसके मूल बिंदुओं को सबके सामने रखा। प्रो राम उपेंद्र दास के धन्यवाद ज्ञापन के साथ विमोचन समारोह का समापन हुआ।

भारत सरकार की वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया रिपोर्ट का लोकार्पण करती हुई। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास; आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रवि कपूर एवं भारत में वियतनाम के राजदूत महामहिम श्री टोन सिन्ह थान्ह।

एशियान–भारत के बीच सांस्कृतिक कड़ियाँ के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिल कर नयी दिल्ली में 23–24 जुलाई 2015 को 'एएसइएएन–इंडिया कल्चरल लिंक्सः हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परारी डाइमेंशंस' विषय के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य वक्तव्य दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और एआईसी ने स्वागत वक्तव्य दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस और एआईएस ने आरंभिक वक्तव्य दिया। प्रो लोकेश चंद्रा, अध्यक्ष, आईसीसीआर, ने उद्घाटन भाषण दिया। कांफ्रेंस के दौरान भारत और एशियान के बीच प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों और

वर्तमान समय में उसकी महत्ता के कई महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा हुई। भारत और एशियान के बीच की सांस्कृतिक कड़ियाँ कारोबार की कड़ियों को मजबूत करने में किस तरह से सहायता पहुँचा सकती है उस पर विचार किया गया।

कांफ्रेंस के दौरान विभिन्न सत्रों में इन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गयाः दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के बीच कारोबार और समुद्री कड़ियाँ, निरंतरता और बदलाव, धर्म और रीति–रिवाजों कानिरुपण, शाब्दिक परंपराएँ और उनका प्रसार, पवित्र भू

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा सम्मेलन में प्रमुख भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) एआईसी के समन्वयक प्रो. प्रबीर डे; आरआईएस एवं एआईसी के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्ष प्रो. लोकेश चंद्रा; एवं आरआईएस एवं एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं।

भाग और विश्वासों का स्थानीकरण, कलात्मक अभिव्यक्तियों का विकासः परंपरा से आधुनिकता तक, अपने इतिहास को खुद लिखनाः प्रविधियों में बदलाव। विश्व के विभिन्न भागों से नामी विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रो प्रबीर डे, संयोजक, एआईसी ने धन्यवाद प्रस्ताव किया।

एक बेल्ट, एक रोड पर सम्मेलन

25–26 अगस्त 2015 को द इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकॉनामिक्स एंड पालिटिक्स (आईडब्लूइपी), चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस (सीएएसएस) ने 'एक बेल्ट, एक रोड' सम्मेलन और बीसीआईएमएस रिजनल इंटरकनेक्शन सम्मेलन का बीजिंग, चीन में आयोजन किया। आरआईएस इस सम्मेलन का सह–संयोजक था। डॉ. जांग यूयान, निदेशक, आईडब्लूइपी, सीएएसएस के आरंभिक और स्वागत वक्तव्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

एक बेल्ट, एक रोड के लक्ष्य को पाने में बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार इकानॉमिक कॉरिडोर (बीसीआईएस–इसी) पूरक का काम करता है। बीसीआईएम के देश प्राचीन दक्षिण–पश्चिम सिल्क रोड की परिधि में आते हैं जो चीन के दक्षिणी इलाके को म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के साथ, जिसमें उत्तर–पूर्वी राज्य भी शामिल हैं, जोड़ता है। ट्रैक दो के स्तर पर दशकों तक बातचीत, सलाह–मशविरे के बाद बीसीआईएम ने अंततः ट्रैक एक अंतर–राज्यीय उपक्रम के रूप में वर्ष 2013 में अधिकारिक स्वीकृति अर्जित की। सहयोग के लिए असीम संभावाओँ और अवसर को देखते हुए, इस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया ताकि इसके माध्यम से अवसरों की चर्चा की जाए, मुख्य चुनौतियों को रेखांकित किया जाए और बीसीआईएम के

वन बेल्ट, वन रोड एवं बीसीआईएमएस क्षेत्रीय अंतःसंपर्क सम्मेलन के प्रतिभागी।

सहयोग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के सुझावों पर सामूहिक रूप से सहमति बनाई जा सके। इंस्टीयूट ऑफ वर्ल्ड इकानॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स (आईडब्लूइपी), चीनय द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी, एंड गर्वनेंस (आईपीएजी), बांग्लादेश, ऑबजरवर रिसर्च फांउंडेशन (ओआरएफ), मुंबई, और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज (आईपीएस), श्रीलंका जैसी संस्थाओं/थिंक टैंक ने 'ओबीओआर' और 'बीसीआईएम' के सहयोग से जुड़े, बीसीआईएम के फायदे और साथ ही क्षेत्रीय स्तर अंतरजुड़ावों को बढ़ावा देने जैसे वृहद आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा मसलों पर विचार–विमर्श किया। आइआईएस के प्रो एस.के. मोहंती ने इस कांफ्रेंस में भाग लिया और 'इमरजेंस ऑफ ए रिजनल ग्रोथ इपीसेंटर इन एशियाः पोटेंशियल आफ बीसीआईएम विद द पॉलिसी आप वन बेल्ट वन रोड' विषय पर अपनी प्रस्तुति दी।

भारत–आसियान विशिष्ट व्याख्यानमाला

भारत–आसियान विशिष्ट व्याख्यानमाला के तहत एशियान–इंडिया सेंटर, आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और एशियान सेक्रिटैरिएट के साथ संयुक्त रूप से

आरआईएस एवं एआईसी के अध्यक्ष श्री श्याम सरन उद्घाटन भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) में समन्वयक प्रो. प्रबीर डे; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) श्री अनिल वाधवा; फिलीपींस के विदेश मामलों के अवर संचिव महामहिम श्री इवान गार्सिया एवं आरआईएस एवं एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

मिल कर महामहिम श्री एवान ग्रासिया, फिलिपिंस के फारेन अफेयर्स अंडर सेक्रेटरी का 17 जुलाई 2015 को नयी दिल्ली में एक व्याख्यान का आयोजन किया। श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस, ने आरंभिक भाषण दिया।

श्री ग्रासिया का व्याख्यान वर्तमान दौर में भारत और फिलिपिंस के बीच आपसी सहयोग औरपरस्पर संबंधों की पड़ताल को लेकर था। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले वर्षों में संबंधों को मजबूत और विस्तृत बनाने रखने के लिए ठोस कदमों के बारे में बताया। श्री श्याम शरण के समापन वक्तव्य के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। प्रो प्रबीर डे, संयोजक, एशियान–भारत सेंटर (एआईसी) ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

दूसरे एशियान–इंडिया एमनन्ट पर्सनलेक्चर के तहत 'एशियान–इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस एंड प्रासपरेटी'विषय पर महामहिम मि. लि ल्योंग मिन्ह, महासचिव, एशियान ने नयी दिल्ली में 10 दिसंबर 2015 को व्याख्यान दिया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत वक्तव्य दिया। श्री वी. एस. शेषाद्री, उप–अध्यक्ष, आरआईएस ने आरंभिक वक्तव्य दिया। श्री अनिल वधवा, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष भाषण दिया। प्रो प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी ने सत्र का समाप्त किया और धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

ऐपेक और भारत पर रिपोर्ट का विमोचन

एशियान– इंडिया सेंटर, आरआईएस ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चौंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फीआईसीसीआई), के साथ संयुक्त रूप से 'एपीइसी एंड इंडियाः एन अप्राइजल' रिपोर्ट के विमोचन समारोह का आयोजन दिल्ली में 21 मई 2015 को किया। इसे डॉ. वी. एस. शेषाद्री, उपाध्यक्ष, आरआईएस ने लिखा है। श्री अनिल वधवा,

इंडिया एंड एपीईसी रिपोर्ट का लोकार्पण।

सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का विमोचन किया और बीज वक्तव्य दिए। रिपोर्ट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'एक ऐसे समय में जब भारतीय सिंह, जो मेक इन इंडिया का ब्रांड इमेज है और आर्थिक कूटनीति के तौर पर पूरी दुनिया के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है, यह रिपोर्ट प्रासंगिक बन जाती है।'

मि. सिद्धार्थ बिरला, पूर्व अध्यक्ष, फिक्की और अध्यक्ष एक्सपीआरओ इंडिया लिमिटेड ने स्वागत वक्तव्य दिया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने विशेष वक्तव्य दिए। डॉ. वी. एस. शेषाद्री ने रिपोर्ट के बारे एक प्रस्तुति दी जिसके बाद खुली बहस हुई। डॉ प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, एशियान–इंडिया सेंटर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

रिपोर्ट भारत के एपीइसी मे शामिल होने की संभावनाओं की पड़ताल करता है। इस बात को रेखांकित करता है कि एपीइसी मे शामिल होना भारत के लिए वांछनीय है। इससे घरेलू कारोबार और निवेश में सहयोग के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसे बल मिलेगा, नई मुद्दों से परिचय और अन्य क्षेत्रों में जो बेहतरीन व्यवहार चलन में आ रहे हैं उसमें सहयोग मिलेगा, अधिकारिक, विशेषज्ञ, बिजनेस और थिंक टैंक स्तर पर नेटवर्किंग के लिए अवसर मुहैया कराएगा, और वैश्विक स्तर पर कारोबार के क्षेत्र में सुशासन के वृहद अवसर के लिए भारत को सामरिक रूप से तैयार करेगा।

भारत–मध्य एशिया आर्थिक सहयोग के पर संगोष्ठी

आरआईएस ने इंस्टीटूयट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से मिल कर नयी दिल्ली में 11–12 जून 2015 को 'टूआर्डस इंडिया–सेंट्रल एशिया इकॉनामिक कोऑपरेशन' के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत वक्तव्य दिया।

आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी स्वागत भाषण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ईआरएस) श्री शंभू एस. कुमारन ;भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) श्री नवतेज सिंह सरना; आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ; एवं नई दिल्ली स्थित इंस्टीच्युट ऑफ सोशल साईसेज के निदेशक डा. ऐश नारायण रॉय।

डॉ. ऐश नारायण राय, निदेशक, इंस्टीटूयट ऑफ सोशल सांइसेज ने विशेष वक्तव्य दिया। श्री नवतेज सिंह सरना, सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने बीज वक्तव्य दिया। महामहिम श्री मिरजोशरीफ असोमुद्दीनविच जालोलोव, भारत में तजाकिस्तान के राजदूत, मि. इवगेने काबलुकोव, मिनिस्टर कौंसिलर, किरगिज रिपब्लिक, श्री सदर शिहियेव, फर्स्ट सेकरेट्री, कौंसिलर, तुर्कमेनिस्तान और श्री तैरोव, ट्रेड और इकॉनामिक कौंसिलर, उजबेकिस्तान ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

श्री अशोक सज्जनहार, सचिव, नेशनल फांउंडेशन फॉर कम्यूनल हारमनी (एनएफसीएच) और कजाकिस्तानमें भारत के पूर्व राजदूत ने 'ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लिंकेजेज' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता की। प्रो एस.के. मोहंती, आरआईएस, सुश्री माया ए सोरोनबेइवा, सलाहकार, पब्लिक एसोसिएशन इंरनेशनल आईसीक्कुल फोरम अंडर द नेम ऑफ चिंगिजएतमातोव, बिश्केक, किर्गिजस्तान और मि. आईक्रोमो जोविदजाफरोविच, स्ट्रेटेजिक रिसर्च सेंटर अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान के वरिष्ठ विशेषज्ञ इस सत्र के पैनल में वक्ता के रूप में शामिल थे।

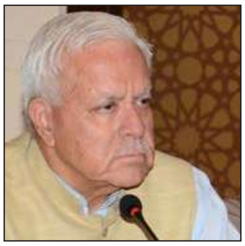

श्री अशोक सजानहार
सचिव, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी (एनएफसीएच)

श्री शंभु एस. कुमारन, संयुक्त सचिव (इआरएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने 'रोल ऑफ रिजनल एंड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स' विषय पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र की वक्ताओं में प्रो ऐश नारायण राय, निदेशक, इंस्टीटूयट ऑफ सोशल सांइसेज, नयी दिल्ली, डॉ बेनु सनाइडर, सीनियर इकानामिक अफेयर्स आफिसर, फाइनेंनसिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफिस (एफएफडी),न्यूयार्क, डॉ अनुराधा चेनाय, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नयी दिल्ली, प्रो राम उपेंद्र दास, आआईएस, डॉ लाउरा येरेकेशेवा, उपनिदेशक, रा डी सुलेमोनोल इंस्टीटूयट ऑफ ओरियंटल स्टडीज, अलमी, कजाकस्तान और प्रो अरुण मोहंती, प्रोफेसर, सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, नयी दिल्ली शामिल थे।

तीसरे सत्र में 'इनोवेशन एंड टेक्नालाजी ट्रांसफर कोलाबोरेशन आपरच्यूनिटीज' विषय पर विचार–विमर्श किया गया। डॉ लाउरा येरेकेशेवा, और डॉ ऐश नारायण राव, निदेशक ने इस सत्र की अध्यक्षता की। श्री इसेनकुल मोमुनकुलोव, सलाहकार, सेरेप रिसर्च इंस्टीट्यूट किरगिजस्तान, प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस और श्री अभिषेक सहाय, सीनियर एसिस्टेंट डायरेक्टर, फिक्की, नयी दिल्ली इस सत्र के वक्ताओं में शामिल थे।

डा. अनुराधा चिनॉय
सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू

इस सत्र में वक्ताओं में डॉ. सपराबायेव बाटेयर, हेड स्पेशलिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड फारेन रिलेसंस, तुर्कमेनिस्तान ने 'डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्यूरल पार्टनरशिप एंड एजेंडा फॉर इकॉनामिक डेवलपमेंट' विषय पर चौथे सत्र की अध्यक्षता की। प्रो संजय पाल, इंटरप्रेन्यूरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, डॉ सुचंदना चौटर्जी, फानलो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज (एमएकेएआईएएस), कोलकाता, डॉ मनजीत कौर, एडिशनल डारेक्टर, एसौचैम, नयी दिल्ली, सुश्री बोबोजोनोवा फारानगिंस सोबिरोवना, अकेडमी ऑफ साइंस, तजाकिस्तान के विशेषज्ञ और डॉ बोरजाकोव मकसत, हेड स्पेशलिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च कमोडिटी सर्कुलेशन ऑफ तुर्कमेनिस्तान्स नेशनल गुड्स, तुर्कमेनिस्तान शामिल थे।

भारत और मध्य एशिया साझेदारी का लंबा इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से भारत और मध्य एशिया के बीच कारोबार और सांस्कृतिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। भारत का पूर्व के सोवियत संघ के साथ नजदीकी और मैत्रीपूर्ण

संबंधों के कारण मध्य एशिया के देशों के साथ राजनयिक संबंध में निरंतरता बनी रही। जैसा कि सर्वविदित है, मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाएँ प्राकृतिक, खनिज और मानव संसाधन से भरी–पूरी है लेकिन विकास के स्तरों में काफी विविधता है। जब हम जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं तब यह काफी स्पष्ट हो जाता है। जहाँ कजाकिस्तान का जीडीपी 231.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वहीं करगिजिस्तान का जीडीपी 7.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तजाकिस्तान का जीडीपी भी बेहद कम है जबकि अन्य दो देशों, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जीडीपी मध्यवर्ती कहा जा सकता है। विकास के विभिन्न स्तरों से मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। जीडीपी के विकास दरों के मामले में किरगिजस्तान को छोड़ कर अन्य मध्य एशिया के देशों ने हाल के वर्षों में काफी ऊंचे और प्रभावशाली वृद्धि दरों को दर्ज किया है।

भारत की विदेश नीति में पिछले दशकों में दक्षिण एशिया का सामरिक दृष्टि से महत्व काफी बढ़ गया है। इसकी वजह भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों, दक्षिण एशिया का अफगानिस्तान से नजदीकी और इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी है। अफगानिस्तान में जारी अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के अफगानिस्तान से वापसी से इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर लोगों की निगाह एशिया की तरफ तेजी से मुड़ रही है, भारत को मध्य एशिया के देशों के भू भाग और सामरिक दृष्टि से महत्व के कारण इन पर बारीक नजर रखनी होगी। इसलिए यह भारत के हित में होगा कि वह तेल और खनिज संसाधनों से भरपूर इस भूभाग के देशों के साथ कारोबार और आर्थिक संपर्क को मजबूत करे। इसलिए, इस क्षेत्र के साथ कारोबार और निवेश को बढ़ाने के लिए कोशिशों को समानुपातिक ढंग से तुरंत तेज करने की जरूरत है।

कारोबार और निवेश के अवसरों और उत्पादन संबंधी मूल्यों में वृद्धि की संभावनाओं की पड़ताल की भारतीय कोशिशों को इन दो रास्तों से बेहतर पाया जा सकता है। पहला, क्षेत्र में द्वपक्षीय और क्षेत्रीय कारोबार को बढ़ावा देकर और दूसरा, भारत की क्षेत्रीय/बहुपक्षीय कारोबारी नियामन ढॉचे में भूमिका और महत्ता को बढ़ा कर। इनमें

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव, श्री राजीव सिकरी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास एवं नई दिल्ली स्थित इंस्टीच्युट ऑफ सोशल साईसेज के निदेशक डा. ऐश नारायण रॉय।

संघाई इकॉनामिक कोऑपरेशन, यूरेशियन इकॉनामिक यूनियन और अन्य शामिल हैं जो मध्य एशिया के साथ भारत के कारोबार के लिए साझा मंच मुहैया कराते हैं।

इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ के जमाने की कमांड इकॉनामी (निर्देशित अर्थव्यवस्था) से छुटकारा पाकर तेजी से प्राइवेट अर्थव्यवस्था के विकास की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र की नींव रखने के लिए प्राइवेट इंटरप्राइजेज के उत्साह को बढ़ावा देनेकी इच्छा के क्रम में इस क्षेत्र के देश भारत की तरफ असीम आशा और विश्वास से देखते हैं। चूंकि इन देशों का भारत के साथ नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा कर इस क्षेत्र में अपनी पहुँच को और गहरा कर सकता है। वह इन देशों के साथ लघु और मध्य उद्योगों के विकास के लिए जरूरी तकनीक साझा कर सकता है।

औद्योगिक उत्पादन आधार के विकास के साथ तकनीकी की उपलब्धता और तकनीक के मूल्य वृद्धि की देशज क्षमता गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। उत्पादन के स्तर पर अपर्याप्त क्षमता से यह क्षेत्र प्रभावित है, जो तकनीकी सहयोग और नई तकनीकी को अपनाने में बाधा बन कर उपस्थित है। इस मायने में भारत का तकनीकी के हस्तांतरण में सहयोग काफी उपयोगी है। भारत की भूमिका से राष्ट्रीय स्तर पर खोज की प्रणाली और उत्पादन की क्षमता को मजबूती मिलेगी।

मध्य एशिया के देशों में भारत के हित को पुनर्जीवित करने की दिशा में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कारोबार और आर्थिक सहयोग से एक–दूसरे को फायदा पहुँच सके, इस संगोष्ठी में उचित और सम्यक ढंग से उसका मूल्यांकन किया गया

इस संगोष्ठी में उन मुद्दों पर विशेष तरजीह दिया गया जो मध्य एशिया के साथ कारोबार में भारत के लिए अवसरों को अच्छी तरह से पहचान करते हैं। मोटे तौर पर संगोष्ठी के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय कारोबार को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय/बहुपक्षीय कारोबार हेतु नियामक ढांचे की भूमिका जिसमें, संघाई इकॉनामिक कारपोरेशन, यूरेशिएन इकॉनामिक यूनियन और अन्य भी शामिल हैं, आर्थिक विकास के लिएउद्यमियों के बीच साझेदारी और नवीन तकनीकी की खोज और तकनीकी हस्तांतरण के लिए सहयोग जैसे मुद्दे शामिल थे।

अन्य बातों के अलावा, संगोष्ठी के दौरान मध्य एशिया के देशों के बारे में सांख्यिकीय डेटा और अन्य सूचनाओं से लैस एक डिजिटल प्लेटफार्म के विकास की संभावनाओं की पड़ताल की गई। यह दूसरी बातों के साथ–साथ भारत के इन देशों के साथ कारोबार और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष क्षेत्रों और उनकी संभावनाओं को रेखांकित करेगा। इससे भारत के कारोबारियों और उद्योग जगत को इन देशों के साथ कारोबार करने में काफी सहायता मिलेगी। वे इस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि किन क्षेत्रों में कारोबार करना उनके लिए फायदेमंद हैं क्योंकि इन देशों के बारे में ठोस आंकड़ों का सख्त अभाव है। इस क्षेत्र के साथ गहरे स्तर पर मेलजोल के लिए सांख्यिकीय सूचनाओं का होना बेहद जरूरी है। यह बड़े स्तर पर भारत के स्टार्ट–अप्स को भी फायदा पहुँचाएगा, जो हाल के दिनों में उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं के विकास के लिए कम लागत वाली नवीन तकनीक लेकर आए हैं। ये स्टार्ट अप्स इन क्षेत्रों में इच्छुक सहयोगियों की तलाश में हैं।

संगोष्ठी के समापन सत्र को प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने संबोधित किया। श्री राजीव सिकरी, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने समापन भाषण दिया। मि. ऐश नारायण राय ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

शोधार्थियों, कारोबार और उद्योग जगत के अगुआ, अकादमिक जगत के लोग, राजनयिक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, जाने–माने विचारकों, जिनका इन क्षेत्रों के बारे में गहरी जानकारी है, ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और अपनी विद्वता और ज्ञान को लोगों के साथ बांटा।

बैंकाक में तीसरा एशिया–पैसेफिक एनआईएस मंच

यूनाइडेट नेशन्स इकॉनामिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसेफिक (इएससीएपी), नयी दिल्ली, भारत के एशियन एंड पैसेफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नालाजी (एपीसीटीटी) और नेशनल सांइस टेक्नालाजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफिस (एसटीआई), विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय, थाइलैंड के साथ मिलकर आरआईएस ने 'डायग्नोशिश ऑफ एनआईएस एंड डेवलपमेंट ऑफ एसटीआई स्ट्रेटेजिज इन द ओपन इनोवेशन फ्रेमवर्क' के ऊपर तीसरे एशिया–पैसेफिक एनआईएस फोरम का आयोजन 8–9 अप्रैल 2015 को बैंकाक, थाईलैंड में किया। आरंभिक सत्र में डॉ. सोमचाई चात्राताना, एसोशिएट प्रोफेसर, नेशनल साइंस टेक्नालॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ऑफिस (एसटीआई), मिनस्ट्री ऑफ सांइस एंड टेक्नालॉजी (एमओएसटी), रॉयल थाई सरकार ने स्वागत भाषण दिया। श्री माइकेल विलियमसन, हेड, एशियन एंड पैसेफिर सेंटर ऑफ द इकॉनामिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसेफिक (एपीसीआईटी–इएससीएपी) और प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने टिप्पणी की। डॉ. पिचेट डूरोनगकावेरोज, विज्ञान और तकनीक मंत्री, थाइलैंड सरकार ने बीज वक्तव्य दिया। श्री एन श्रीनिवासन, संयोजक, विज्ञान, तकनीक और अविष्कार, एपीसीआईटी–इएससीएपी ने फोरम के बारे में जानकारी दी और धन्यवाद ज्ञापन किया। आरआईएस की तरफ से डॉ. रवि श्रीनिवास, सलाहकार ने भी फोरम में भाग लिया और 'ओपन इनोवेशन फ्रेमवर्क एज एन एसटीआई स्ट्रेटेजी' पर एक प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में विषयों पर पैनल डिसक्शन और देश आधारित प्रस्तुति दी गई उनमें शामिल हैंः एसटीआई की अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियाँ, ओपन टेक्नालाजी इनोवेशन के बिजनेस मॉडल और आने वाली संकल्पनाएं, एशिया पैसेफिक में एनआईएस की जाँच–पड़ताल और एसटीआई की रणनीतियों का विकास, जाँच–पड़ताल और रणनीतियाँ के विकास की चुनौतियाँ और अवसर, और एनआईसी जाँच–पड़ताल और एसआईटी रणनीति के समर्थन में विकास का सहयोग।

तीसरे एशिया–प्रशांत फोरम के प्रतिभागी।

बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिंस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और विएतनाम में एसटीआई की नीतियाँ और इनोवेशनल प्रणाली की जाँच–पड़ताल करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं के विशेषज्ञों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिसोर्स पर्सन (विषय विशेषज्ञ) ने इनमें भाग लिया और चुने गए विषयों पर अपने अनुभवों और बेहतरीन अभ्यासों को प्रस्तुत किया। इसका आयोजन नेशनल इनोवेशन प्रणालियों के अध्ययन और विश्लेषण में लगे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के लिए किया गया। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एसटीआई की नीतियों के अध्ययन में लगे राष्ट्रीय संस्थानों के बीच बहस–मुबाहिसा करवाना और अनुभवों को बांटना है। साथ ही नवाचार प्रणाली (राष्ट्रीय, उप क्षेत्रीय, विभागीय) की जाँच–पड़ताल और एसटीआई पर सलाह देना, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में रणनीतियाँ और इस प्रकार नीतिनिर्माताओं का सहयोग करना, ताकि साक्ष्य आधारित नीतियों के बारे में निर्णय ले सकें, फोरम का उद्देश्य है।

एसटीआई की रणनीति के रूप में एक महत्वपूर्ण इकाई, और दक्षिणीय और क्षेत्रीय सहयोग के लिए नवाचार में आने वाली संकल्पनाओं पर विचार–विमर्श के लिए विशेषज्ञों को एक मंच मुहैया कराता है। इसमें भाग लेने वाले देशों में एनआईएस की जाँच–पड़ताल की प्रविधियों और बेहतरीन तौर–तरीके की पहचान करना इन विमर्शों का उद्देश्य है। एक राष्ट्रीय एसटीआई रणनीति के रूप में खुली नवाचार दृष्टिकोण एप्रोच एनआईएस को मजबूत करेगा और इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में हो सकेगा, ताकि एक–दूसरे के फायदे के लिए तकनीकियों का सह–विकास हो।

भारत 2050ः सतत संवृद्धि के लिए खाके पर चर्चा

आरआईएस ने नयी दिल्ली में 29 मई 2015 को 'इंडिया 2050ः ए रोडमैप टू सस्टेनेबल प्रास्पेरिटी' विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने स्वागत टिप्पणी की। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस

पहले इंडिया फाउंडेशन के डा. रामगोपाल अग्रवाल पुस्तक के बारे में प्रस्तुतिकरण देते हुए। चित्र में (बायें से दायें) जेएनयू के पूर्व उपकुलपति प्रो. बी.बी. भट्टाचार्य; आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम सरन; सीएसडी के प्रेसीडेंट प्रो. मुचकुंद दूबे; एवं एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी।

ने आरंभिक टिप्पणी की। डॉ. रामगोपाल अग्रवाल, अध्यक्ष, पहले इंडिया फांउंडेशन, नयी दिल्ली ने अपनी किताब 'इंडा 2050: ए रोडमैप टू सस्टेनेबल प्रास्पेरेटी' पर एक प्रस्तुति दी जिसके बाद वक्ताओं ने अपनी बात रखी। परिचर्चा में प्रो मुचकुंद दुबे, अध्यक्ष, कौंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट (सीएसडी), प्रो बी बी भट्टाचार्या, जेएनयू के पूर्व कुलपति, श्री मनीष सिंघल, उप महासचिव, फिक्की और डॉ. सैकत सिन्हा राय, एसोशिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जाधवापुर विश्वविद्यालय, कोलकाता शामिल थे।

यूएनडीपी के दक्षिणीय सहयोग की रणनीति पर एक परिचर्चा

आरआईएस ने नयी दिल्ली में 14 अप्रैल 2015 को 'साउथ–साउथ कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ यूएनडीपी' विषय पर परिचर्चा का आयोजन सुश्री शियोजुन वाग,साउथ–साउथ और ट्राएनग्यूलर कोऑपरेशन, ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट (बीपीपीएस), यूनाइटेड नेशन डेवलपमेट प्रोग्राम (यूएनडीपी), न्यूयार्क के साथ किया। मिस नान कौलिंस, एसएसस स्पेशलिस्ट, यूएनडीपी रिजनल हब, बैंकाक और सुश्री मोमिनजान, प्रोग्राम ऑफिसर, यूएनडीपी इंडिया कंट्री ऑफिस ने भी परिचर्चा में भाग लिया।

ऑस्ट्रेलिया और भारत: एशिया में शांतिपूर्ण और संवृद्ध आर्थिक व्यवस्था की ओर

26 मई 2015 को 'ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया: टूआर्डस ए पीसफुल एंड प्रोसपेरस एशियन इकॉनामिक ऑडर' विषय पर गोलमेंज चर्चा का आयोजन किया गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया पब्लिक पॉलिसी के दो जाने माने व्याख्याता, मि. रोवन कैलिक, ऑस्ट्रेलियन न्यूजपेपेर के एशिया–पैसेफिक संपादक और श्री टॉम स्विटजर, लेक्चरर, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रिसर्च एसोशिएट, यूनाइटेड स्टेटस स्टडीज सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने भाग लिया। आरआईएस की तरफ से प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक ने शुरुआती टिप्पणी की और प्रो राम उपेंद्र दास, आरआईएस ने ऑस्ट्रेला–भारत के आर्थिक संबंधों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी

भारत–अफ्रीका आर्थिक व्यवस्थाएँ पर परिचर्चा बैठक

आरआईएस ने इंडिया–अफ्रीका इकॉनामिक अरैंजमेंट (आईएइए) ने नयी दिल्ली में 12 जून 2015 को एक परिचर्चा का आयोजन किया। श्री श्याम शरण, अध्यक्ष, आरआईएस ने इस परिचर्चा की अध्यक्षता की। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने आरंभिक वक्तव्य दिया। मुख्य वक्ताओं में शामिल थे: मि सैयद अकबरूद्दीन, संयुक्त सचिव और मुख्य संयोजक (आईएएफएस), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अमित शुक्ला, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रोहित मिश्रा, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, और प्रो. एस. के. मोहंती, आरआईएस।

मेडिकल उपकरण नीति पर गोलमेज

आरआईएस ने 10 अगस्त 2015 को ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, 2015 के ऊपर टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने कि लिए एक गोलमेज का आयोजन किया। इस गोलमेज का उद्देश्य ड्राफ्ट पॉलिसी के ऊपर एक संयोजित प्रतिक्रिया को पाना था। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक ने आरंभिक टिप्पणी की। श्री टी. सी. जेम्स, विजिटिंग फैलो, आरआईएस ने ड्राफ्ट पॉलिसी को प्रस्तुत किया। श्री के एम. गोपा कुमार, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, डॉ. रेजि के. जोसेफ, आईएसआईडी, डॉ. अमित सेनगुप्ता, इंटरनेशनल पीपुल्स हेल्थ यूनिवर्सिटी, डॉ. जितेंद्र कुमार शर्मा, नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मि. जाकिर थॉमस, पूर्व निदेशक, ओएसडीडी, डॉ. सरोजिनी एन बी, डॉ. देवप्रिया दत्ता, निदेशक, इंडो–फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांसड रिसर्च और डॉ. सव्यसांची साहा, सहायक प्रोफेसर ने इस गोलमेज में भाग लिया।

नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द सोशिलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल आरआईएस में

सहायक प्रोफेसर, डॉ. त्रिन्ह डूक थाओ, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट एंड लॉ, हो चि मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स (एचएनएपी) के नेतृत्व में एक सात सदस्यी प्रतिनिधि मंडल 15 सितंबर 2015 को आरआईएस में एक परिचर्चा के लिए पहुँचा। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थेः डॉ. नदूयेन थि थूएट माई, सीनियर लेक्चरर, इंस्टीट्यॉ ऑफ लीडरशिप एंड पब्लिक पॉलिसी, एचएनएपी, डॉ. नगूयेन थि फोंग लान, व्याख्याता, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनामी, एचएनएपी, श्री नगूयेन वान डोंग, एमए, एचएनएपी उपाध्यक्ष के सचिव, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के इनचार्ज हैं, श्री डो खुओंग मान्ह, लिन्ह, एमए, सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के विशेषज्ञ, एचएनएपी, और श्री वू वान अन्ह, अंतर राष्ट्रीय सहयोग के विशेषज्ञ, एचएनएपी।

एआईसी के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी एवं प्रो. एस.के. मोहंती वियतनाम के शिष्टमंडल के साथ।

दक्षिणीय सहयोग पर संगोष्ठी

आरआईएस ने 'द आईबीएसए ट्रस्ट फंड एज ए टूल ऑफ साउथ–साउथ कोऑपरेशनः पर्सपेक्टिव ऑफ इमरजिंग कंट्रीज' विषय पर नयी दिल्ली में 21 दिसबंर 2015 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें मि. लौरा करिना गुटिररेज मातामोरोज, रिसर्च स्कॉलर, इंटरनेशनल डेवलेपमेंट कोऑपरेशन, डॉ. जोसे मारिया लुइस मोरा, रिसर्च इंटस्टीयूट, मेक्सिको (और इंटर्नशिप स्कॉलर, आरआईएस) ने भाग लिया। प्रो. सचिन चतुर्वेदी महानिदेशक, आरआईएस ने आरंभिक वक्तव्य दिया। श्री राजीव कुमार भाटिया, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के पूर्व महानिदेशक, ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की।

सुश्री लौरा करीना गुटिएरेज माटामोरोस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए। चित्र में (बायें से दायें) श्री राजीव कुमार भाटिया; एवं प्रो. सचिन चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं।

आरआईएस शोध के नए सीमांत

आरआईएस ने वरिष्ठ शोधार्थियों के लिए एक नई संगोष्ठी श्रृंखला की शुरूआत की गई जिसे संगोष्ठी श्रृंखला कहा गया है। इसके तहत संस्थान में जो शोध की परियोजनाएं विकसनशील हैं, उस पर चर्चा की जाएगी।

इस सीरिज के तहत 28 अगस्त 2015 को प्रो. राम उपेंद्र दास द्वारा 'यूरेशियन एफटीए और भारत' विषय पर पहली संगोष्ठी का आयोजन हुआ।

दूसरे संगोष्ठी में प्रो. एस. के. मोहंती ने 28 सितंबर 2015 को आने वाले आरआईएस विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्लूटीडीआर) की एक रूप–रेखा को प्रस्तुत किया।

आरआईएस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला

आरआईएस ब्रेकफास्ट संगोष्ठी श्रृंखला एक प्रक्रिया है जहाँ निकाय के युवा सदस्यों और अपने कैरियर के शुरुआती दौर में जो शोधार्थी हैं उन्हें अपने काम के नतीजों को अन्य लोगों के साथ सांझा करने का एक मंच मिलेगा। साथ ही उन्हें अपने जारी शोध पर विशषज्ञों और सहकर्मियों से आलोचनात्मक टीका–टिप्पणी भी मिलेगी। नामी गिरामी शोधार्थियों को भी इस सीरिज के तहत अकादमिक और नीतिगत मौजू विषयों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। निम्नलिखित संगोष्ठी इस सीरिज के तहत आयोजित किए गए:

आरआईएस की ब्रेकफ़ास्ट सेमिनार श्रृंखला

तिथि	वक्ता	विषय	अध्यक्ष
7 अप्रैल 2015	प्रो राम उपेंद्र दास, आरआईएस	ट्रेड सिद्धांत और कार्यप्रणाली में विकास	प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस
5 मई 2015	श्री सुशील कुमार, सलाहकार, आरआईएस	चीनी उत्पादन में इथोपिया के साथ भारत का वैकासिक सहयोग/एक मूल्यांकन	प्रो. एस. के. मोहंती आरआईएस
2 जून 2015	श्री सुनंदो बासु, रिसर्च एसोशिएट, आरआईएस	सीजीइ माडलिंग और उसके उपयोग की एक भूमिका	प्रों. एस. के मोहंती, आरआईएस
11 अगस्त 2015	सुश्री रश्मि सिंह, सलाहकार, आरआईएस	वियतनाम–चीन ग्रेटर मेकांग सब–रिजनल फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन (जीएमएस)	श्री जयंत प्रसाद, विजिटिंग फेलो, आईआरएस
11 सिंतबर 2015	सुश्री आस्था गुप्ता, रिसर्च असिस्टेंट	ट्रेड नीति का उदारीकरण और भारत में ट्रेड के साथ उसके संबंधों की कड़ियाँ	डा. शाहिद अहमद, अर्थव्यवस्था विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया
3 नवंबर 2015	सुश्री पायल चटर्जी, रिसर्च असिस्टेंट, आरआईएस	भारत के फरमास्यूटिकल इंडस्ट्री का विकासरू ट्रीप्स (टीआरआईपीएस) व्यवस्था के पहले और बाद मे	
2 दिसंबर 2015	सुश्री प्रत्युष, रिसर्च असिस्टेंट, आरआईएस	वर्ल्ड सिस्टम थियरी के नजरिए से वैश्विक विकास पर बहस	प्रो. ऐश नारायण राय, निदेशक, इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली
7 जनवरी 2016	सुश्री प्रतिभा शाव, रिसर्च असिस्टेंट, आरआईएस	औद्योगिक शोध और विकास (आर एंड डी) के बढ़ावे केलिए राजकोषीय प्रोत्साहन	प्रो. प्रणव एन. देसाई, सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- भारत में 'बायोटेक्नालॉजी से जुड़ी परियाजनाओं में सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ'विषय पर 'सोशियो–इकॉनामिक मेथोडॉलाजी' कार्यशाला के दौरान एक प्रस्तुति दी। इस कार्यशाला 20–21 अप्रैल 2015 को इंडो–स्विस कोलाबोरेशन इन बायटेक्नालाजी (आईएससीबी), स्विटरलैंड आयोजित किया था। कार्यशाला के उद्देश्य, आईएससीबी की अपेक्षाओं पर एक विशेष टिप्पणी भी पेश की किया और डाटा पब्लिशिंग को लेकर मंचीय बहस में भाग लिया।
- 'मानवीय और वित्तीय संसाधनों को भारत के थिंक टैंक के लिए जुटाना' विषय पर थिंक टैंक, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंसरू आइडियाज, एनालिसिस, इनोवेशन एंड इमपैक्ट यूएस–इंडिया थिंक टैंक सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी। इस सम्मेलन को नयी दिल्ली में 27–29 अप्रैल 2015 को टीटीसीएसपी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया, ऑबजरवर्स रिसर्च फांउंडेशन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन भारत में अमेरिकी दूतावास ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- 'भारत में स्वास्थ्य के लिए सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने की व्यवस्था' विषय पर जिनेवा में 4–7 मई 2015 को एक प्रस्तुति दी। 'रिस्पांसिबल इनक्लूसिव इनोवेश इन हेल्थ' संगोष्ठी में दिया जिसे विश्व स्वास्थ्य संस्था (डब्लू एच ओ) ने आयोजित किया था।
- 'अफ्रीकी बाजारों में भारतीय बीजः कारोबार और तकनीकी में दक्षिणीय सहयोग' विषय पर राइजिंग पावर्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक प्रस्तुति दी। जिसे 8 मई 2015 को यूके में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (आईडीएस) ने आयोजित किया था।
- 'कार्यान्वयन के माध्यमः वित्त और तकनीक की भूमिका' विषय पर 'पर्सपेक्टिव फ्राम इंडिया ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोस्ट–2015 डेवलपमेंट एजेंडा' संगोष्ठी में एक प्रस्तुति दी। इस संगोष्ठी को न्यूयार्क में 15 मई 2015 को ऑबजरवर्स रिसर्च फांउंडेशन (ओआएफ) और सेफ गार्ड एंड सेंटर ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन (सीआईसी) ने आयोजित किया था।
- 'ब्रिक्स (बीआरआईसीएस) ट्रेड इन हाइ टेक्नॉलाजी प्रोडक्टस (एचटीपीस): ट्रेंडस एंड की पॉलिसी इंपरेटिव्स' विषय पर सातवें ब्रिक्स एकेडमिक फोरम में एक प्रस्तुति दी। 'बीआरआईसीएसः कोऑपरेशन फॉर ग्रोथ सिक्यूरिटी एंड प्रासपेरटी' मंच, मास्को में 22–23 मई 2015 को यह आयोजित किया।
- 'द रोल ऑफ एग्रिकल्चरल बायोटेक्नॉलाजी इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड न्यूट्रीशन' पर हुई संगोष्ठी में बाह्य सलाहाकार पैनल के एक मेंबर की हैसियत से एफएओ सिम्पोसियम के एडवाइजरी परिचर्चा बैठक में भाग लिया। जो रोम में 3–4 जून 2015 को हुई।
- 'वेस्टर्न एड आर्किटेक्चर एंड साउथ–साउथ पाराडाइमः वुड चाइना प्रोवाइड ए न्यू लीडरशिप ऑन ग्लोबल फ्रेमवर्कट' विषय पर एक प्रस्तुति बैंकाक में 9–10 जून 2015 को 'चाइनाज ओवससीस डेवलपमेंट पॉलिसी इन ए वर्ल्ड बियांड एड' पर एक गोलमेज सम्मलेन में दी।

- नाबाने नेशनल नेचर रिजर्व (एनएनएनआर) के लिए फील्ड ट्रीप में भाग लिया। 28 जून–2 जुलाई 2015 को शीशुआंगबन्ना क्षेत्र में द चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क (सीआईडीआरएन) ने आयोजित किया था।
- बीजिंग में 2 जुलाई को हुए 'थर्ड एनुअल कांफ्रेंस ऑफ चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क (सीआईडीआरएन)' में भाग लिया
- नयी दिल्ली में 23 जुलाई 2015 को संसद भवन में स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव (एसआरआई) में '2015 के बाद विकास के एजेंडा' पर एक प्रस्तुति दी।
- इकॉनामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशियान और इस्ट एशिया (एआरआईए) के फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नेटवर्क मीटिंग (आरआईएनएम) में भाग लिया। जिसे बैंकाक रिसर्च सेंटर और जेइटीआरओ ने 25 जुलाई 2015 को बैंकाक में आयोजित किया था।
- 'लिंकिंग ट्रेड, इनेवस्टमेंट एंड एसटीआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' विषय पर बैंकाक में 6 अगस्त 2015 को एक प्रस्तुति रिजनल वर्कशाप ऑन हारनैसिंग साइंस, टेक्नालाजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमॉ में दी जिसे यूएन–अएससीएपी ने आयोजित किया था।
- 'ढॉचागत सुधार और लागू करने की चुनौतियाँ' विषय पर चाइना–ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल इश्यू डॉयलाग में संघाई में 14 अगस्त 2015 को एक प्रस्तुति दी। जिसे संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईआईएस) और इस्ट एशिया ब्यूरो ऑफ इकॉनामिक रिसर्च (इएबीइआर), एएनयू ने आयोजित किया था।
- 'एशियन पैनल राउंडटेबल' सत्र में सिम्पोजियम ऑन सस्टेनेलब डेवलपमेंट गोल्स और एशियन पर्सपेक्टिव के दौरान 20 अगस्त 2015 को सियोल में एक प्रस्तुति दी। जिसे कोरिया एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन (केएआईडीइसी) और कोरिया फांउंडेशन (केएफ) ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- 'बिल्डिंग साउथ–साउथ सपोर्ट स्ट्रक्चर' सत्र में हाई–लेवल मल्टी–स्टेकहोल्डर्स स्ट्रेटेजी फोरम ऑन स्केलिंग–अप ग्लोबल सपोर्ट फॉर साउथ–साउथ एंड ट्राएंग्यूलर कोऑपरेशन इन द कॉनटेक्स्ट ऑफ द पोस्ट–2015 डेवलपमेंट एजेंडा के दौरान मुख्य वक्ता थे। जिसे 25 अगस्त 2015 को मकाओ में कमिटी ऑन साउथ–साउथ कोऑपरेशन एंड दी यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस फॉर साउथ–साउथ कोऑपरेशन (यूएनओदक्षिणीय सहयोग) एंड इटस ग्लोबल साउथ–साउथ डेवलपमेंट एक्पो सेक्रेटेरियट (जीएसएसडी एक्सपो) ने आयोजित किया था।
- 'एफआईडीसी के काम के दौरान अनुभव की साझेदारी' विषय पर नयी दिल्ली में 2 सितंबर 2015 को एक प्रस्तुति को संगोष्ठी ऑन इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद अफ्रीकाः व्हाट रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर के दौरान प्रस्तुत किया गया जिसे सीआईआई ने आयोजित किया था।
- कंसलटेशन टू प्रपोज इंडिकेटर्स फॉर क्लाइमेट चेंज–रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड यूएनएफसीसीसी बॉन डिब्रीफ के दौरान नयी दिल्ली में 10 सितंबर 2015 को उद्घाटन भाषण दिया और उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। जिसे अल्टरनेटिव फ्यूचर्स और सीएएनएसए ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- 'माइक्रो पर्सपेक्टिवः सेटिंग द टोन विद इंडियाज एसपिरेशन्स ऑन पोस्ट–2015 डेवलपमेंट एजेंडा विद ए स्पेसिफिक फोकस टू गोल 16' विषय पर 14 सितंबर

2015 को एक प्रस्तुति सतत विकास के लक्ष्य विषय पर गोलमेज के दौरान प्रस्तुत की। जिसे वाटर एड और वादा ना तोड़ों ने संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया था।

- 'फेयर एंड इक्यूटेबिल सोर्सिंग इन रेपुटेशन इकॉनामी' के सत्र में 10 वें सस्टेनेबल शिखर सम्मेलन के दौरान परिचर्चा में भाग लिया जिसे 15 सितंबर 2015 को सीआईआई, नयी दिल्ली में आयोजित किया।
- 'अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ रिजनल इकॉनामिक इंटिग्रेशन इन साउथ एशियाः प्रॉयरिटीज फॉर द इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन ऑफ सार्क' विषय पर हुए क्षेत्रीय परिचर्चा में भाग लिया जिसे नयी दिल्ली में 16 सितंबर 2015 को हुए यूएनइएससीएपी, फिक्की और सार्क चौंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने आयोजित किया।
- 'प्राकृतिक संसाधन का कोरोबारः दक्षिण से एक परिप्रेक्ष्य' विषय पर कांफ्रेंस ऑन एकसेसिंग रिसोर्सेज फ्राम ग्लोबल मार्केटः जियो–पॉलिटिकल चौलेंजेज एंड स्ट्रेटेजिज के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे नयी दिल्ली में 17 सिंतबर 2015 को टेरी और कोनार्ड एडेनाउर सटिफुंग ने आयोजित किया था।
- 'फाइनेंसिंग स्मार्ट सिटी फॉर इंडिया एट दि नेशनल कांफ्रेंस ऑन स्मार्ट सिटीज एंड इंडियाज न्यू अरबन इंपरेटिव्स' विषय पर एक सत्र की अध्यक्षता की। जिसे सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स, आईआईसी, नेशनल फांउंडेशन फॉर इंडिया और आईसीएसएसआर ने संयुक्त रूप से नयी दिल्ली में 29 सितंबर 2015 को आयोजित किया था।
- 'भारत–अफ्रीका के सामरिक संबंधों का एक मूल्यांकन' विषय पर नयी दिल्ली में 13 अक्टूबर 2015 को हुए गोलमेज के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। जिसे ब्रूकिंग्स इंडिया ने आयोजित किया।
- थर्ड नेशनल रिपोर्ट ऑन द इंपलिमेंटेशन ऑफ द कारटोजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी की उप–समिति के सम्मेलन में नयी दिल्ली में 14 अक्टूबर 2015 को भाग लिया। जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओइएफ) ने आयोजित किया था।
- 'बेल्ट रोड इनिशिएटव (बीआरआई) एंड डेवलपमेंट एप्रोचेज एंड ग्रोथ एसपिरेशंस' विषय पर डायलॉग विद चाइना फाइनेंस, 40 फोरम (सीएफ40) में 'चाइना एंड इंडियाः पाथवेज टू ए कॉमन एशियन फ्यूचर' के तहत प्रस्तित दी। जिसे 19 अक्टूबर 2015 को नयी दिल्ली में एनसीएइआर ने आयोजित किया।
- 'अफ्रीका के साथ भारत के वैकासिक सहयोगः अनुभव और अपेक्षाएँ' विषय पर प्री–इंडिया अफ्रीका फोरम सम्मिट III एकेडेमिक कांफ्रेंस ऑन 'इंडिया–अफ्रीका इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीः स्केल एंड स्कोप ऑफ कंप्रिहेनसिव पार्टनरशिप के दौरान प्रस्तुति दी जिसे नयी दिल्ली में16 अक्टूबर 2015 को इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्लूए) ने आयोजित किया।
- 'अफ्रीका के साथ वैकासिक साझेदारी–कारोबार, निवेश, आईटीइसी, कृषि आदि' सत्र में 'भारत–अफ्रीका संपादक' फोरम के दौरान मुख्य वक्ता थे। जिसे नयी दिल्ली में 25 अक्टूबर 2015 को विदेश मंत्रालय के एक्सपी विभाग ने आयोजित किया था।
- 'मेकिंग साउथ–साउथ पाराडाइम अकांउटेबल एंड ट्रांसपैरेंटरूरोडब्लॉक एंड रिकॉमेंडेशन्स' विषय पर एक प्रस्तुति 'अफ्रीकन वाइसेस–पीपुल्स पर्सपेक्टिव इन इंडियाज पिच फॉर स्ट्रांगर साउथ' के ऊपर हुए गोलमेज के दौरान दी जिसे नयी दिल्ली में 26 अक्टूबर 2015 को एसोचैम ने आयोजित किया था।

- 'चीन का एक बेल्ट रोड, भारत की पहलकदमियाँ और एशिया शताब्दी के विचारः संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की गुंजाइश' विषय पर सिल्क रोड फोरम 2015 में एक प्रस्तुति दी जिसे मैड्रीड, स्पेन में 29 अक्टूबर 2015 को जिसे डेवलपमेंट रिसर्च कौंसिल (डीआरसी) ऑफ द स्टेट कौंसिल ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेट (सीआईआरएसडी) ने आयोजित किया।
- 'ब्रिक्स–आईबीएसए जी 77' विषय पर' नेशनल कंसलटेशन ऑ एसडीजीज एंड इंटरनेशनल प्रोसेसेज' के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे नयी दिल्ली में 5 नवंबर 2015 को वादा ना तोड़ो अभियान ने आयोजित किया था।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में तबदीली–भारत और जर्मनी' विषय पर सीआईसीएमएएलइपी साइकिल 3, मॉड्यूल 1ः एक्सपर्ट रिसोर्स फॉर सेशन ऑन 'इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेन' के तहत हुए एक पैनल परिचर्चा का संचालन और जिसे नयी दिल्ली में 6 नवंबर 2015 को जीआईजेड इसे आयोजित किया।
- 'भारत की विकास सहयोगः एक अवलोकन' विषय पर 'भारत की वैकासिक सहयोग में भारत के नागरिक समाज के भाग लेने पर नीतिगत प्रभाव' कार्यशाला के दौरान एक प्रस्तुति दी। इसे नयी दिल्ली में 20 नवंबर 2015 को पीआरआईए (प्रिया) ने आयोजित किया था।
- ग्लोबल सम्मिटः हम कहाँ जा रहे हैं' विषय पर डब्लूटीओ की परिचर्चा में भाग लिया। जिसे नयी दिल्ली में 23 नवंबर 2015 को न्यू लाउंड्री ने आयोजित किया था।
- 'पूर्व एशिया सम्मेलन और आर्थिक क्षेत्रवाद के एक दशक' विषय पर एशिया पैसेफिक फोरम 2015, 'एशियान बिल्डिंग एंड रिजनल इकॉनामिक इंटीग्रेशन इन इस्ट एशियाः लुकिंग बियांड 2015' के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे 26 नवंबर 2015 को जकार्ता में जापान इकॉनामिक फांउंडेशन, इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशियान एंड इस्ट एशिया एंड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- 'पर्सपेक्टिव ऑफ आईपीआर पॉलिसीज इन लाइट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ आईपीआर' सत्र का दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो 'आईपी लाउस एंड इनफोरसमेंट ऑफ आईपीआर–प्रोटेक्ट एंड कामर्शियलाइज आपी इन इंडियाः मेक इन इंडिया' के ऊपर था, संचालन किया। इसे 1 दिसंबर 2015 को सीआईआई ने आयोजित किया था।
- 'इमरजिंग पार्टनरशिप इन बीबीआईएनः इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कोऑपरेशन' विषय पर एडवांसिंग द बीबीआईएनः एक्सपलोरिंग पॉसिबिलिटी इन ट्रेड, ट्रांसिट, इनर्जी एंड वाटर कोऑपरेशन' कांफ्रेंस के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे 3 दिसंबर 2015 को कोलकाता में एशिया फाउंडेशन और आब्जर्बर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- मिन्स ऑफ इंपलिमेंटेशनन (एमओआई)ः एन इंडियन पर्सपेक्टिव' विषय पर आठवें दक्षिण एशिया आर्थिक सम्मेलनरू दक्षिण एशिया में सतत विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे 8 दिसंबर 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसडीपीआई) ने इस्लामाबाद में आयोजित किया था।
- 'एसडीजीज एंड एसटीआई इमपरेटिव्स–टेक्नालॉजी फेसेलिटेशन मेकैनिज्म' विषय पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति के तीसरे सम्मेलन के दौरान एक

प्रस्तुति मे दी जिसे नसुक्कामें 14 दिसंबर 2015 को इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजेरिया ने आयोजित किया था।

- '2015 के बाद वैकासिक एजेंडा–एमडीजीज से लेकर एसजीजीज तक' विषय पर 98वें वार्षिक भारतीय आर्थिक संघ के सम्मेलन में एक पैनल डिसक्शन की अध्यक्षता की। यूएनडीपी प्रायोजित यह परिचर्चा में हैदराबाद में 28 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ।
- 'सतत विकास के एक औजार के रूप में बायोटेक्नालॉजी' पर हुए क्षेत्रीय संवाद जो 'विज्ञान एवं तकनीकी, बायोटेक्नालॉजी के परिप्रेक्ष्य में सतत विकास की ओर' विषय पर आयोजित था, के दौरान एक प्रस्तुति दी जिसे 30 दिसंबर 2015 को रिजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नालॉजी, आरसीबी एनसीआर बायोटेक साइंस कलस्टर कैंपस के द्वारा, फरीदाबाद में आयाजित किया गया।
- 'कॉमनवेल्थ सदस्यों के बीच कारोबार और निवेश' विषय पर 'कॉमनवेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप ऑन ट्रेड–रिवाटलाइजिंग ग्लोबल ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म' के सलाहकार सम्मेलन के दौरान एक प्रस्तुति दी। जिसे 31 मार्च 2016 को कानफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने नयी दिल्ली में आयोजित किया।
- 'एसडीजी प्रक्रिया, सूचक और राष्ट्रीय रणनीति' विषय पर 'सतत वैकासिक लक्ष्यों की प्राप्ति जिसे भारत के लिए अवसर और चुनौतियाँ' कार्यशाला में प्रस्तुति दी। इसे 10 जनवरी 2016 को अहमदाबाद में नीति आयोग और सेंटर फॉर इनवायरमेंट इजुकेशन ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।
- 'वाइसेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन ओपन इनोवेशन, ओपन साइंस, ओपन टू द वर्ल्ड' सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया। साथ ही आरआरआई–टेक होम मैसेज फ्रॉम प्लेनैरिज एंड पैरेल कार्यशालाएट द कांफ्रेंस ऑन रिस्पांसिबल रिसर्च एंड इनोवेशन इन यूरोप एंड एक्रास द वर्ल्ड गो–4 ज्वांइट फाइनल कांफ्रेंस में भाग लिया। जिन्हें ब्रुसेल्स में 15 जनवरी 2016 को इयू द्वारा पोषित चार परियोजनाओं ने यूरोपियन इकॉनामिक एंड सोशल कमिटी (इइएससी) के साथ मिल कर आयोजित किया गया।
- 'इमरजिंग एंड कंटम्परेरी आर एंड डी एंड इनोवेशन इंडिकेटर्स इन नेशनल एस एंड टी सिस्टम एंज पॉलिसी इंप्लीकेशन्स–ए कंप्रिहेनसिव स्टडी' विषय पर एलपीएसी की पहली बैठक में भाग लिया। जिसे नयी दिल्ली में 20 जनवरी 2016 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड (आईआईएफटी) ने आयोजित किया और डीएसटी ने प्रायोजित किया।
- ट्रेड इन नेचुरल रिसोर्सेजः इकॉनामिक इंप्लीकेशन्स ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिकशन' सत्र की अध्यक्षता पोटेंशियल इंपैक्टस ऑफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिकशननेचुरल रिसोर्सेज' कार्यशाला के दौरान की जिसे नयी दिल्ली में 20 जनवरी 2016 को टेरी ने आयोजित किया था।
- दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट नेटवर्क मीटिंग (आरआईएनएम) फॉर इकॉनामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एशियान एंड इस्ट एशिया (इआरआईए) में भाग लिया तथा टीपीपी और आरसीइपी के गोलमेज के दौरान 25 जनवरी 2016 को कुला लांपूर में भी मौजूद रहे।
- भविष्य में भारत के कारोबार नीति में प्राथमिकताएँ' विषय पर एक परिचर्चा सत्र में डब्लूटीओ नैरोबी मिनिस्टीरिल आउटकम्स एंड इंडियाज फ्यूचर ट्रेड प्लॉसी प्रायरेटीजके दौरान प्रस्तुति दी जिसे नयी दिल्ली में 27 जनवरी 2016 को

सीआईआई और सेंटर फॉर डब्लूटीओ स्टडीज ने संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया था।

- सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्सः द रोल ऑफ थिंक टैंक इन पॉलिसी मेंकिंग, के ऊपर एक पैनल डिसक्शन में पैनेलिस्ट रहे जिसे नयी दिल्ली में 28 जनवरी 2016 को ओआरएफ ने आयोजित किया था।
- एमइए–आईआईएएस संवाद के सातवें चरण में भाग लिया जिसे 9 फरवरी 2016 को नयी दिल्ली में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) ने संयुक्त रूप से आयोजित किया।
- 'सोशल एंड 'इकॉनामिक इंपैक्टस ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नॉलाजिज फॉर स्मालहोल्डर्सः टेकिंग स्टॉक ऑफ द इविडेंस एंड प्राइरॉटाइजिंग फ्यूचर एसेसमेंट्स' सत्र की अध्यक्षता की तथा 'साउथ–साउथ कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नालाजिज' के ऊपर एक प्रस्तुति इंटरनेशनल संगोष्ठी ऑन एग्रीकल्वर बायोटेक्नालाजिज के दौरान की जिसे रोम में 15–16 फरवरी 2016 को फूड एंड एग्रीकल्वर आर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया।
- 'अफ्रीका 2000 सेः संक्रमण और बदलाव' के ऊपर राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। नयी दिल्ली में 18 फरवरी 2006 को इसे अफ्रिकन स्टडीज विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था।
- सीआईआई अफ्रीका समिति के तीसरी बैठक में भाग लिया जिसे नयी दिल्ली में 23 फरवरी 2016 को श्री नोएल टाटा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
- एसडीजी इंडिकेटर फ्रेमवर्क पर सचिव, एमओएसपीआई के साथ एक परिचर्चा में भाग लिया जिसे नयी दिल्ली में 26 फरवरी 2016 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयोजित किया।
- 'इंटरनेशनल एड आर्किटेक्चर एंड थियरी ऑफ डेवलपमेंट कम्पैक्ट एंड मिशन एप्रोच' के ऊपर एक प्रस्तुति कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेसन्स (सीआईआर), शिकागो विश्वविद्यालय की तरफ से आए मेहमान छात्रों के समूह के बीच शिकागो विश्वविद्यालय के दिल्ली केंद्र पर 22 मार्च 2016 में प्रस्तुत की।
- 'भारत–नेपाल संबंधः बदलते संदर्भ, आने वाली परिस्थितियाँ' विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया। नयी दिल्ली में 26–27 मार्च 2016 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषट, भारत, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, नीति अनुसंधान परिषद नेपाल ने आयोजित किया।

प्रो. एस. के. मोहंती

- नई दिल्ली में 10 अप्रैल, 2015 को आयुर्वेदिक ड्रग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से एनबीए और एनटीसी के मुद्दों पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में 15 अप्रैल, 2015 को चीन और एशिया पैसिफिक क्षेत्र मुद्दे पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 'अफ्रीका के साथ भारत–चीन व्यापार संबंध' विषय पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अफ्रीका डिवीजन, नई दिल्ली में 9 मई, 2015 को प्रस्तुती की।
- अफ्रीका में भारत के लिए व्यापार संभावना विषय पर 11 मई, 2015 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित चर्चा में भाग लिया।

- भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की ओर से गोवा में 17 मई, 2015 को आयोजित सामान्य तौर पर व्यापार किए जाने वाली कमोडिटीज पर पुनर्गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक में 'भारत में जैविक संसाधनों का व्यापारिक वर्गीकरण' विषय पर प्रस्तुती की।
- खान मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 27 जुलाई, 2015 को आयोजित 'ब्लू इकॉनमी एंड रिव्यूइंग द माइनिंग सेक्टर इन इंडियन कॉंटेक्स्ट' पर बैठक में भाग लिया।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से 29 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में ब्लू इकॉनमी पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 2 अगस्त, 2015 को 'टुवार्ड्स ए कांप्रिहेंसिव फ्रेमवर्ग फॉर द ब्लू इकॉनमी इन आईओआरए' विषय पर प्रस्तुती की।
- राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड, नई दिल्ली में 4 अगस्त, 2015 को 'प्रोसपेक्ट्स ऑफ ब्लू इकॉनमी इन द इंडियन ओशन रीम' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 6 अगस्त, 2015 को 'टुवार्ड्स ए कांप्रिहेंसिव फ्रेमवर्ग फॉर द ब्लू इकॉनमी इन आईओआरए' विषय पर बैठक में हिस्सा लिया।
- आस्ट्रेलिया के पर्थ में 5–7 सितंबर, 2015 को डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन ट्रेड, आस्ट्रेलियाई सरकार, आईओआरए, ओआरएफ, और फ्यूचर डायरेक्शंस इंटरनेशनल, आस्ट्रेलिया की ओर से आयिजत इंडियन ओशन डायलॉग 2015 के दौरान 'ब्लू इकॉनमी एज ए ड्राइवर ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ' विषय पर प्रस्तुती की।
- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में 30 सितंबर, 2015 को आने वाली आईओआरए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग (सीओएमएम) को ले कर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (सीओएम) बैठक के तहत पडंग, इंडोनेशिया में 18–24 अक्तूबर, 2015 के दौरान आयोजित इंडियन ओशन रिम एकेडमिक ग्रुप मीटिंग (आईओआरएजी) में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया।
- पडंग, इंडोनेशिया में 20 अक्तबूर, 2015 को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (सीओएम) बैठक के तहत इंडियन ओशन रिम एकेडमिक ग्रुप मीटिंग (आईओआरएजी) में 'आरआईएस ब्लू इकॉनमी रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदू' और 'इकनॉमिक डायमेंशंस ऑफ फिशरीज इन आईओआरए' पर प्रस्तुती की।
- 'ट्रेड पॉलिसी इश्यूज' पर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से 7 जनवरी, 2016 को आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 'डब्लूटीओ नैरोबी मिनिस्टेरियल आउटकम्स एंड इंडियाज फ्यूजर ट्रेड पॉलिसी प्रायोरिटीज' पर कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और सेंटर फॉर डब्लूटीओ स्टडीज की ओर से नई दिल्ली में 27 जनवरी, 2016 को आयोजित इंटरेक्टिव सत्र में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 9 फरवरी, 2016 को 'तीसरे फिक्की/पीडब्लूसी स्ट्रेटजी एंड इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग बैरोमीटर' लोर्कापण कार्यक्रम में भाग लिया।
- यूजीसी सेंटर फॉर मैरिटाइम स्टडीज, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की ओर से पांडिचेरी

में 18–19 फरवरी को 'गुड आर्डर एट सीरू इंडियाज रोल' पर आयोजित संगोष्ठी में 'ब्लू इकॉनमी' पर प्रस्तुती की।

- इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी, एडवोकेसी एंड गवर्नेंस (आईपीएजी) की ओर से 29 फरवरी, 2016 को 'बांग्लादेश एंड नार्थ इस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया (बीएनईएसआइ)' पर आयोजित चर्चा में स्काइप के जरिए भाग लिया।
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से 18 मार्च, 2016 को सीओएमईएसए पर ज्वाइंट स्टडी ग्रुप (जेएसजी) की मसौदा रिपोर्ट पर आयोजित चर्चा बैठक में भाग लिया।
- सोसाइटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज (एसआईओएस) की ओर से नई दिल्ली में 19 मार्च, 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स इन द इंडियन ओशन' में "रिएस्योरिंग आईओआरए विद एक्सपेंडिंग कॉपरेशन इन ट्रेडः एड्रेसिंग रिजनल इंबैलेंस विद जीवीसी सेक्टर" पर प्रस्तुती की।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- न्यू डेलही इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एनडीआईएम) में 11 अप्रैल, 2015 को आयोजित इवैल्यूएशन ऑफ कारपोरेट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीएसडी) में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 6 मई, 2015 को आयोजित अंतर मंत्रालयी तैयारी बैठक में भाग लिया। जिसमें भारत और यूरोशियन इकनॉमिक कमीशन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तलाशने के लिए ज्वाइंट स्टडी ग्रुप को शुरू करने पर चर्चा हुई।
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) की ओर से नई दिल्ली में 13 मई 2015 को 'डब्लूटीओ की 20वीं वर्षगांठ' पर आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- एनसीएईआर, नई दिल्ली की ओर से 14 मई, 2015 को 'स्टेट ऑफ द इकॉनमी' पर आयोजित संगोष्ठी में 'न्यू फॉरन ट्रेड पॉलिसी' पर मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 4 जून, 2015 को आयोजित बीकेआरयू–कस्टम्स यूनियन पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) और इसके सदस्य देशों और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ज्वाइंट फिसीबलिटी स्टडी ग्रुप (जेएफएसजी) की पहली बैठक में भाग लिया जो मॉस्को में 31 जुलाई, 2015 को आयोजित हुई।
- सीआईआई की ओर से नई दिल्ली में 6 अगस्त 2015 को आयोजित 'इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट्स' पर समिति की पहली बैठक में भाग लिया।
- एसोचेम की ओर से नई दिल्ली में 20 अगस्त, 2015 को आयोजित 'मेक इन इंडियाः द नेक्स्ट लीप' पर सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास की ओर से नई दिल्ली में 21 अगस्त 2015 को आयोजित बैठक 'रिजनल इकनॉमिक कॉपरेशन' में भाग लिया।
- न्यूजीलैंड दूतावास की ओर से नई दिल्ली में 22 अगस्त, 2015 को आयोजित 'इकनॉमिक कॉपरेशन बिटविन इंडिया–न्यूजीलैंड' विषय पर गोलमेज में भाग लिया।
- नेशनल डिफेंस कॉलेज की ओर से नई दिल्ली में 9 सितंबर, 2015 को आयोजित संगोष्ठी 'रिवाइटलाइजिंग सार्क' में 'प्रमोटिंग सार्क इकनॉमिक इंटेगरेशन' सत्र की अध्यक्षता की।

- युनाइटेड नेशंस ईएससीएपी– एसएसडब्लूए की ओर से नई दिल्ली में 16 सितंबर, 2015 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला 'डब्लूटीओ एंड रिजनल ट्रेड एग्रीमेंट इन साउथ एशियारू नेगोशिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन चौलेंजेज' में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- ईएससीएपी–एसएसडब्लूए की ओर से नई दिल्ली में 17 सितंबर, 2015 को 'रिजनल कॉपरेशन फॉर इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटः साउथ एंड साउथ–वेस्ट एशिया डेवलपमेंट रिपोर्ट' पर आयोजित एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक में भाग लिया।
- नई दिल्ली में 22 सितंबर, 2015 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) और इसके सदस्य देशों और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की रिपोर्ट पर ज्वाइंट फिसीबलिटी स्टडी ग्रुप (जेएफएसजी) की बैठक में भाग लिया।
- चाइना–इंडिया एसोसिएशन फॉर प्रमोशन एंड ट्रेड (सीएपीईटी) की ओर से क्वालालंपुर में 22–25 सितंबर, 2015 को वन ब्लेड वन रोड पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।
- इंटरनेशनल अतातुर्क अलातू यूनिवर्सिटी, किरगिस्तान की ओर से 8–10 अक्तूबर, 2015 को 'द प्रोसपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन 21 सेंचरी' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 29 अक्तूबर, 2015 को इंडिया–यूरेशिया पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 'थिंक 20 समिट/ग्लोबल पॉलिसी डायलॉग प्लेटफार्म' सम्मेलन में भाग लिया जो 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट' पर इकनॉमिक पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन ऑफ टर्की (टीईपीएवी) की ओर से तुर्की में 12–16 नवंबर 2015 में आयोजित किया गया था।
- टेरी की ओर से नई दिल्ली में 19 नवंबर, 2015 को 'मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेजरू ए नार्थ–ईस्ट पर्सपेक्टिव' कार्यशाला में भाग लिया।
- यूरोपियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2015 को 'ईयू एफएलईजीटी एंड टिंबर ट्रेड इन साउथ एशिया' पर कार्यशाला में भाग लिया।
- 'टी20 किकऑफ मीटिंग' में भाग लिया जिसका चीन के तीन थिंक टैंक की ओर से चीन में 14–15 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई थी। ये थिंक टैंक हैं– इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एट चाइनिज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज (आईडब्लूईपी, सीएएसएस), शंघाईय इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशल स्टडीज (एसआईआईएस)य और चोंगयांग इंस्टीट्यूट फॉर फाइनांसियल स्टडीज, रेनमिन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना (आरडीसीवाई)।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से 7 दिसंबर, 2015 को यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) और इसके सदस्य देशों और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की रिपोर्ट पर 'ज्वाइंट फिसीबलिटी स्टडी ग्रुप' (जेएफएसजी) की बैठक में भाग लिया।
- इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (आईएलओ) और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नई दिल्ली की ओर से 17 दिसंबर, 2015 को 'ट्रेड एंड एंप्लायमेंट चौलेंजेज इन एशियाः इनसाइट्स फॉर साउथ एशिया' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से 18 दिसंबर, 2015 को 'इंडिया म्यांमार बोर्डर ट्रेड स्टडी' पर बैठक में भाग लिया।

- डेक्कन हेराल्ड की ओर से नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2015 को आयोजित चर्चा 'द एशिया पैसिफिक सेंचरी– इण्डिया एंड बिग पॉवर एंगेजमेंट' में वक्ता।
- अमेरिकन इकनॉमिक एसोसिएशन, एलाइड सोशल साइंस एसोसिएसन, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए की 3–5 जनवरी, 2016 को आयोजित वार्षिक बैठक में 'आसियान प्लस सिक्स एंड सक्सेसपुल एफटीएरू कैन इंडिया प्रोपेल इंट्रा–इंडस्ट्री ट्रेड फ्लॉज?' पर पेपर पेश किया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2016 को 'इंडिया–यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) एफटीए' पर बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से 15 फरवरी, 2016 को यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) और इसके सदस्य देशों और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की रिपोर्ट पर 'ज्वाइंट फिसीबलिटी स्टडी ग्रुप' (जेएफएसजी) की बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 16 फरवरी, 2016 को 'बोर्डर ट्रेड कमेटी एंड बोर्डर हाट कमेटी बिटविन इंडिया एंड म्यांमार' विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 26 फरवरी, 2016 को 'रिजनल कंप्रीहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी)' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 15 मार्च, 2016 को 'इंडिया–यूरोशियन इकनॉमिक यूनियन (ईएईयू) एफटीए' पर आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- टर्किक वर्ल्ड एजुकेसन एंड साइंटिफिक कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन (टीडब्लूईएससीओ) की ओर से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 28 मार्च, 2016 को 'सिनर्जीज एलांग द सिल्क रोड फॉर एजेंडा 2030' पर आयोजित संगोष्ठी में भाषण दिया।

प्रो. टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- सीएनसी न्यूज चौनल पर 5 अप्रैल, 2015 को 'ड्राफ्ट नेशनल आईपी पॉलिसी' में शामिल हुए।
- माननीय लोक सभा अध्यक्ष के साथ 6 अप्रैल, 2015 को एक बैठक में हिस्सा लिया और एक कोर ग्रुप गठित करने का प्रस्ताव किया जो माननीय सांसदों के लिए विभिन्न चुनिंदा विषयों पर अध्ययन और ब्रीफ तैयार करे ताकि वे लोकसभा की कार्यवाही में ज्यादा प्रभावी तरीके से भाग ले सकें। बाद में कोर ग्रुप गठित हुआ और आरआईएस को उसमें जगह मिली।
- माननीय लोक सभा अध्यक्ष की ओर से गठित कोर ग्रुप की पहली बैठक में भाग लिया और आरआईएस की विशेषज्ञता उपलब्ध करवाने की पेशकश की। डेवलपमेंट कॉपरेशन, सामयिक आर्थिक विषयों, इनोवेशन, आईपीआर और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों और क्षेत्रीय तथा दोक्षीय विषयों पर इंस्टीट्यूट की ओर से किए जा रहे अध्ययन का इसमें खास तौर पर उल्लेख किया गया।

- लोक सभा टीवी पर 28 मई, 2015 को होने वाले 'नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी पॉलिसी' चर्चा में भाग लिया।
- नेशनल मेडिसीनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली की ओर से 29 मई, 2015 को आयोजित नेशनल कार्यशालाऑफ स्टेकहोल्डर्स ऑफ मेडिसीनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स में भाग लिया और 'आईपीआर इश्यूज रिलेटेड टू मेडिसीनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स (हर्ब्स एंड देयर अलाइड प्रोडक्ट्स)' पर शोधपत्र उपलब्ध करवाया।
- ईयू बिजनेस काउंसिल और सीआईआई की ओर से नई दिल्ली में 5 जून, 2015 को आयोजित 'इंडो–यूरोपियन कांफ्रेंस ऑन फोस्टरिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट बायलेटरल कॉपरेशन इन रिसर्च, इनोवेशन एंड आईपीआर' के दौरान 'कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज इन दी एरिया ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड आईपीआरः ए हिस्टोरिकल अपोर्चुनिटी फॉर इंडियन एंड यूरोपियन इनोवेटर्स' पर एक प्रजेंटेशन दिया और 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन स्ट्रेंदनिंग आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेशन' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की।
- सीआईआई की ओर से कोच्ची में 19 जून, 2015 को एंटरप्रेनुअर्स के लिए आयोजित आईपीआर कार्यशाला के दौरान मुख्य भाषण दिया।
- संसद में डीएनए बिल पर येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस पोगे, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक कार्यालय के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों और विभिन्न अकादमिक विद्वानों के साथ 21 अगस्त, 2015 को आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान बिल के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई।
- हेल्थ इंपैक्ट फंड प्रपोजल पर 21 अगस्त, 2015 को आयोजित बैठक में हिस्सा लिया।
- सीआईआई अफ्रीका समिति (2015–16) की 17 अगस्त, 2015 को हुई पहली बैठक में भाग लिया।
- साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकनॉमिक्स एंड एनवॉयर्नमेंट (एसएडब्लूटीईई) की ओर से काठमांडू, नेपाल में 26–27 अगस्त, 2015 को आयोजित 'कंजर्वेशन, यूज एंड क्सचेंज ऑफ क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेजः प्रमोटिंग रिजनल कॉपरेशन फॉर फूड सेक्यूर, क्लाइमेट रिजेलिएंड साउथ एशिया' पर क्षेत्रीय बैठक के दौरान 'एक्सेस एंड बेनेपिट शेयरिंग अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन द नगोया प्रोटोकॉलः इंप्लीकेशंस एंड स्कोप फॉर रिजनल कॉपरेशन गिविंग द इंडियन पर्सपेक्टिव' पर प्रस्तुती दी।
- हेल्थ इकनॉमिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2–4 नवंबर, 2015 को आयोजित "इवोल्विंग रेजिम इन इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्शन" पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'आईपी एंड एक्सेस टू नॉलेज' और 'ट्रिप्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल' पर वार्ता पेश की।
- ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की ओर से जेनेवा में 12–13 नवंबर, 2015 को वैश्विक स्वास्थ्य नीति के थिंक टैंक्स और अकादमिक संस्थानों के लिए बैठक के दौरान 'हाउ टू स्ट्रेंदेन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी थिंक टैंक्स इन रिलेसन टू दी चैलेंज टू इंप्लीमेंट दी एसडीजी विद ए व्यू टू इंप्रूव हेल्थ' पर प्रजेंटेशन देने के अलावा सभी सत्रों में सक्रियता से भाग लिया।
- स्पीकर्स रिसर्च इनीशिएटिव की बैठक में भाग लिया।
- वीआईटी यूनिवर्सिटी, चेन्नई की ओर से 30–31 जनवरी 2016 को आयोजित ग्लोबल आईपी फिएस्टा में इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी लॉ और कॉपीराइट तथा पाइरेसी पर भारतीय नजरिया पेश किया।

- केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेलायानी, त्रिशूर में 4 फरवरी, 2016 को किसानों और कानून, अर्थशास्त्र तथा कृषि के छात्रों के लिए 'कॉमर्शियलिजेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स' पर वार्ता पेश की।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलूरू की ओर से 4 मार्च, 2016 को "कॉपीराइट लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शन ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स" पर आयोजित कार्यशाला में कीनोट भाषण दिया और "पैरलल इंपोर्ट्स" पर प्रजेंटेशन दिया।

डॉ. के. रवि श्रीनिवास

कंसल्टेंट

- इंधोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी, इंधोवन, नदीरलैंड्स की ओर से 13 अप्रैल, 2015 को 'बायोफ्यूल्स एंड (इ)रिस्पांसिबल इनोवेसनरू टेंशंस बिटविन पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट' पर आयोजित सम्मेलन में 'बायोफ्यूल्स, स्सटेनेबल डेवलपमेंट एंड रिस्पांसिबल इनोवेसनः द केस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी' पर प्रजेंटेशन दिया।
- नोर्विक, यूके में 14 अप्रैल, 2015 को 'हाऊ (एंड हाऊ नॉट) टू थिंक अबाउट इंटेल्कचुअल प्रोपर्टी इन एग्रीकल्चर एंड प्लांट साइंस' पर कल्टीवेटिंग इनोवेशन कांफ्रेंस में 'ओपन सोर्स, ओपन इनोवेसन एंड कॉमंसः टुवार्ड्स एन अल्टरनेटिव आईपी रेजिम इन एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग' पर प्रजेंटेशन दिया।
- स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट एंड फूड साइंस एचएएफएल, जोलिकोफेन, स्विट्जरलैंड में 20 अप्रैल, 2015 को आईएससीबी सोशियो–इकनॉमिक मैथडोलॉजी कार्यशालामें 'प्राइसिंग ऑफ टेक्नालॉजी इंटेंशिव प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी एंड सोशल इकनॉमी फ्रेमवर्क' पर प्रजेंटेशन दिया।
- इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो–इकनॉमिक चेंज की ओर से बेंगलूरू में 27 जून, 2015 को लीड ऑथर्स कार्यशालाऑन राइस स्ट्रेटजी में 'राइस जर्मप्लाज्म, सीड्स, इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन' पर प्रजेंटेशन दिया।
- कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में 28–30 जुलाई, 2015 को ओपन प्लांट सिनबायो मीटिंग एंड आईपी वर्किंग ग्रुप कार्यशालामें हिस्सा लिया।
- काउंसिल ऑन हेल्थ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट (सीओएचआरईडी) की ओर से फिलिपिंस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और फिलिपिंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी की साझेदारी में मनीला में 26 अगस्त, 2015 को आयोजित ग्लोबल फोरम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर हेल्थ 2015 में 'इनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर हेल्थ– टेक्नालॉजी हब्स, साइंस पार्क्स एंड मोर' सत्र में वक्ता के तौर पर भाग लिया।
- बीजिंग में 28–29 अगस्त, 2015 को 'गवर्नेंस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक इंफोर्मेशन एंड प्रेसीजन मेडिसीन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में प्रजेंटेशन दिया।
- 'बायोटेक्नालॉजी फॉर फूड सेक्यूरिटी एंड न्यूट्रीशन' पर एफएओ की ओर से रोम में 15–17 फरवरी, 2016 को आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- यूनिवर्सिटा का फोसकारी वेनेजिए, इटली के डिपार्टमेंट ऑफ एनवॉयर्नमेंटल साइंसेज में 18 फरवरी, 2016 को 'सोशियो–इकनॉमिक एसेसमेंट ऑफ नैनोटेक्नालॉजी एंड इमर्जिंग टेक्नालॉजीज' पर वार्ता पेश की।
- यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा में 18 फरवरी, 2016 को सेंटर फॉर एनवॉयरनमेंटल, एथिकल, लीगल एंड सोशल डिसीजंस के टीम के सदस्यों के साथ चर्चा बैठक में भाग लिया।

डॉ. सब्यसाची साहा

असिस्टेंट प्रोफेसर

- इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, चाइनिज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से बीजिंग में 18–19 जून, 2015 को 2015 ब्रिक्स थिंक टैंक राउंडटेबल में एक विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।
- नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (एनईएसटी), यूएनडीपी की न्यूयॉर्क में 22 सितंबर, 2015 को हुई बैठक में प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया।
- एसडीजी पर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की ओर से नई दिल्ली में 16 सितंबर, 2015 को सांसदों के लिए आयोजित बैठक में विशेषज्ञ के तौर पर हिस्सा लिया।
- पोस्ट 2015 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में चार जलवायु संबंधी बिंदुओं पर इंडिकेटर्स का प्रस्ताव करने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूचर्स एंड एक्शन 2015 की ओर से नई दिल्ली में 10 सितंबर, 2015 को आयोजित बैठक में विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।
- प्रस्तावित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 16वें लक्ष्य पर वादा ना तोड़ अभियान, नई दिल्ली की ओर से 30 जुलाई, 2015 को आयोजित कार्यशाला में एक विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।
- डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से 7 अक्तूबर, 2015 को ऑर्गनाइजेशनल प्रैक्टिसेज फॉर इनोवेशन इन इंडियन इंडस्ट्रीजः ए फर्म लेवल केस स्टडी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वर्क कल्चर प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।
- डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली में 8 अक्तूबर, 2015 को "पेटेंट्स ऑबटेंड बाय फॉरन एंटिटीज इन इंडियाः एन एनायलसिस" पर प्रस्तुती दी।
- व्हाइस ऑफ दी वोलंट्री सेक्टर (वाणी) और हेनरिच बॉल स्टिफटुंग–इंडिया की ओर से नई दिल्ली में 7–8 दिसंबर, 2015 को आयोजित 'सिविल सोसाइटी रिस्पांस टू इंडिया अफ्रीका समिट' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता के तौर पर भाग लिया।
- नई दिल्ली स्थित आस्ट्रेलियाई उच्चायोग की ओर से 17 दिसंबर, 2015 को श्री रिक वेल्स, डिप्टी सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरन अफेयर्स एंड ट्रेड, आस्ट्रेलिया सरकार के सम्मान में आयोजित डिनर बैठक में विशेषज्ञ के तौर पर भाग लिया।
- स्त्री आधार केंद्र, डेवलपमेंट सपोर्ट टीम, पुणे और बियांड कोपनहेगन की ओर से पुणे में 21 फरवरी, 2016 को आयोजित 'टेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एजेंडा पोस्ट 2015' संगोष्ठी में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और एसडीजी पर प्रस्तुती की।

डॉ. दुर्रईराज कुमारस्वामी

कंसल्टेंट, आरआईएस

- थाइलैंड के बैंकाक में 15–19 जून, 2015 के दौरान डब्लूटीओर्ध्इएससीएपी 10वें एआरटीएनईटी कैपिसिटी बिल्डिंग कार्यशालाफॉर ट्रेड रिसर्च की ओर से 'एंपेरिकल मैथड्स इन ट्रेडरू एनलाइजिंग ट्रेड कोस्ट्स एंड ट्रेड फेसिलिटेशन' पर आयोजित पांच दिन की कार्यशाला में भाग लिया।

- हेनन इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड वाच, हाइकू, चीन में 25–28 अगस्त, 2015 के दौरान इंडियाज कनेक्टिविटी विद नेबर्स एंड इट्स इंप्लीकेसंस फॉर साइनो–इंडिया रिलेशंस पर मासिक संगोष्ठी के दौरान 'ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट रिलेसंस बिटविन इंडिया एंड चाइनाः स्कोप एंड पोटेंशियल' पर प्रस्तुती की।

IV

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)/एससीएएपी कार्यक्रम के साथ संयोजन के रूप में 'अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास नीति (आईईआईडीपी)' पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम नई दिल्ली में 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2016 तक आयोजित किया। यह कार्यक्रम भूमंडलीकरण एवं विकास की प्रक्रियाओं से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर बेहतर

आरआईएस सकाय सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और विकास नीति (आईईडीपी) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी

समझ विकसित करने हेतु विकासशील देशों के प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम वैश्विक आर्थिक मुद्दों एवं वार्ताओं की बढ़ती हुई जटिलताओं से प्रतिभागियों को अच्छीक तरह अवगत कराने और इनसे निपटने के लिए उनके विश्लेषणात्मक कौशल का निर्माण करने के उद्देश्यी से तैयार किया गया है। यह आरआईएस की विभिन्नश गतिविधियों के तहत समग्र क्षमता निर्माण कवायद का एक हिस्सा है।

आईईआईडीपी कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास नीति के दायरे में रहते हुए विकासशील देशों में विश्लेषणात्मक क्षमता के निर्माण में योगदान देना है। वैश्विक व्यापार प्रणाली एवं डब्ल्यूटीओ, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणालियां, दक्षिणीय सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बहुराष्ट्रीय उद्यम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी और विकासात्मीक नीतिगत सुधार जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण भी इस कार्यक्रम में शामिल है।

इस कार्यक्रम से प्रतिभागियों के उन क्षमताओं से लैस होने की उम्मीद है जिससे उन्हें विभिन्न वैश्विक आर्थिक रुझानों का अपने गृह देशों पर पड़ने वाले असर को समझने एवं व्यवस्थित ढंग से उनका विश्लेषण करने और इसके साथ ही उपयुक्त नीतिगत विकल्पों एवं प्रतिक्रियाओं को तय करने में मदद मिलेगी।

प्रतिभागियों ने विशेष रूप से विकासशील देशों के नजरिए से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चाएं कीं। इसे आरआईएस के संकाय (फैकल्टी) द्वारा दिए गए व्याख्यानों की एक श्रृंखला के जरिए हासिल किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विद्वान, अन्य थिंक टैंक/विश्वविद्यालयों के जाने–माने विशेषज्ञ और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल हैं। दिल्लीक में एवं इससे बाहर विभिन्न क्षेत्र भ्रमणों के जरिए प्रतिभागियों को भारत की आर्थिक गतिशीलता से भी अवगत कराया गया। आरआईएस के प्रो. राम उपेंद्र दास कार्यक्रम निदेशक थे। 17 देशों के 27 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

दक्षिणीय सहयोग पर आईटीईसी/एससीएएपी क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी)/अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता कार्यक्रम (एससीएएपी) के तहत 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2015 तक नई दिल्ली में दक्षिणीय सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच सहयोग पर दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्यि दक्षिणीय सहयोग (एसएससी) की एक व्यापक अवधारण ाा, विशेषकर वैश्विक सहायता की संरचना में दिख रहे व्यापिक बदलाव के मद्देनजर दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे पुनरुत्थान के संदर्भ में विकास संबंधी सहयोग से प्रतिभागियों को अवगत कराना था। इस कार्यक्रम के तहत अन्य बातों के अलावा संबंधित देशों की अलग–अलग उपलब्धियों को आपस में जोड़ते हुए एसएससी के औचित्यं, अवधारणाओं एवं रूपरेखा पर ध्यापन केंद्रित किया गया और इस तरह उनकी सामूहिक सहभागिता से होने वाले फायदों एवं इसके मार्ग की बाधाओं के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में उन प्रमुख सिद्धांतों, नीतियों, तौर–तरीकों

आरआईएस सकाय सदस्यों के साथ दक्षिणीय सहयोग पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रतिभागी

(जिनमें राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वामित्व, स्वतंत्रता, समानता, गैर–शर्त, गैर–हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ शामिल हैं) एवं प्रथाओं को भी कवर किया गया, जो दक्षिणीय सहयोग में स्पष्ट नजर आते थे और इसके साथ ही इस बात पर गौर किया गया कि आखिरकार कैसे नीतिगत झुकाव या दक्षिणीय सहयोग की ताकत को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान इस पर भी चर्चा की गई कि दक्षिणीय सहयोग आखिरकार उत्तर–दक्षिण सहयोग (एनएससी) से एक अलग मिसाल कैसे है और दक्षिणीय सहयोग को किस तरह एक स्वैच्छिक भागीदारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो राजनीतिक एकजुटता की प्रारंभिक नींव को मजबूत करने के बाद अब एक कहीं अधिक परिपक्व मंच में विकसित हो चुका है। कार्यक्रम के दौरान इस पर भी विचार–विमर्श किया गया कि दक्षिणीय सहयोग को किसी भी महत्वपूर्ण दृष्टि से एनएससी के एक स्थानापन्न के रूप में क्योंग नहीं देखा जाना चाहिए।

इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों में विदेश/वित्त/वाणिज्य मंत्रालय अथवा दक्षिणीय सहयोग/एनएससी से वास्ता् रखने वाले अन्य मंत्रालयों के अधिकारीगण और संबंधित मुद्दों से जुड़े स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण शामिल थे। बौद्धिक सत्रों के अलावा एक अध्ययन दौरा भी आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों को समूह चर्चाओं और प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रवीणता से जुड़े परिणामों को साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

व्यापार नीति और विश्लेषण पर कार्यशालाएं

आरआईएस नियमित आधार पर कार्यशालाओं का आयोजन करके व्यापार नीति और विश्लेषण पर अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए क्षमता निर्माण में म्यांमार की सहायता करता है। इसके तहत आरआईएस ने म्यांमार के अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज संबंधी केंद्र (सीईएसएस) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आरआईएस में चौथी कार्यशाला 9 से लेकर 13 जून 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित किया। इस कार्यक्रम को आईपीई ग्लोबल, ब्रिटिश सहायता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए

विभाग (डीएफआईडी), ज्ञान भागीदारी कार्यक्रम और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय ने अपना समर्थन प्रदान किया।

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र के समन्वयक प्रो. प्रबीर डे ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। नई दिल्ली् स्थित केपीपी आईपीई ग्लोबल की डॉ. गीतांजलि नटराज ने विशेष टिप्पणियां कीं। आरआईएस के प्रो. एस. के. मोहंती ने उद्घाटन भाषण दिया। म्यांमार संघ गणराज्य के दूतावास में मंत्री परामर्शदाता (काउंसलर) श्री सैन ऊ माउंग ने भारत में म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री आंग खिन सोय की ओर से उद्घाटन भाषण दिया।

इस कार्यक्रम में जिन विभिन्न विषयों को शामिल किया गया वह थे व्यापार एवं विकासः सिद्धांत एवं नीति, व्यापार एवं निवेश संपर्कः अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय आयाम, व्यापार नीति, वरीयता संबंधी उपयोगिता एवं एलडीसी, गैर टैरिफ उपायों से निपटना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक : भारतीय अनुभव, भारतीय मानक ब्यूरो का अवलोकनः द्वि पक्षीय सहयोग पर परिप्रेक्ष्य, व्यापार वार्ताएंः बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, व्यापार सुविधाः सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, व्यापार सुविधा में वैश्विक एवं क्षेत्रीय पहल, भारतीय सीमा शुल्क, भारत–म्यांमार संबंध और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। प्रतिभागियों को व्यापार संबंधी डेटाबेस और विश्लेषणात्मक जानकारी भी दी गई।

इसके अलावा, आरआईएस के उपाध्यक्ष डॉ. वी.एस. शेषाद्री ने 'भारत एवं म्यांनमार के बीच के कनेक्टिविटी गलियारों (कॉरिडोर) को विकास गलियारों में तब्दील करना' विषय पर और डब्ल्यूटीओ में पूर्व भारतीय राजदूत श्री जयंत दासगुप्ता् ने 'ज्यादा मजबूत वैश्विक व्यामपार प्रणाली का निर्माण करना' विषय पर विशेष व्याख्यान दिए। आरआईएस के अध्यक्ष श्री श्याम शरन ने समापन भाषण दिया। प्रो. प्रबीर डे ने समापन टिप्पणियां कीं और इसके साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

इससे पहले, आरआईएस और म्यांमार के अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज संबंधी केंद्र (सीईएसएस) द्वारा संयुक्त रूप से यांगून स्थित यांगून आर्थिक विश्वविद्यालय में 11 से लेकर 15 मई 2015 तक ससेक्स विश्वविद्यालय, यूनेस्कैप, यांगून आर्थिक विश्वविद्यालय, ट्रेड सिफ्ट और एशिया–प्रशांत शोध एवं प्रशिक्षण नेटवर्क (आर्टनेट)

आरआईएस सकाय सदस्यों के साथ चौथी कार्यशाला व्यापार नीति और विश्लेषण के प्रतिभागी

के सहयोग से तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई। इस आयोजन को भी म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय, ब्रिटिश सहायता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए विभाग (डीएफआईडी) और आईपीई ग्लोबल ने अपनी ओर से भरपूर समर्थन प्रदान किया।

म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री महामहिम डॉ. पविंट सैन की ओर से वाणिज्य मंत्रालय में स्थायी सचिव एवं महानिदेशक श्री यू टो आंग मइंट ने उद्घाटन भाषण दिया। म्यांमार में भारत के राजदूत श्री गौतम मुखोपाध्योय ने मुख्य भाषण दिया। यांगून आर्थिक विश्वविद्यालय में प्रो–रेक्टार डॉ. तुन आंग ने विशेष भाषण दिया। इस परियोजना का प्रबंधन करने वाले प्रो. प्रबीर डे ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस परियोजना के तहत अंतराष्ट्रींय व्यापार से जुड़े विभिन्नम विषयों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को ट्रेडसिफ्ट के बारे में भी जानकारी दी गई, जो ससेक्सन के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विकसित की गई एक प्रणाली एवं सॉफ्टवेयर है और जिससे नीति निर्माताओं एवं सरकारों को काफी आसान एवं किफायती तरीके से व्यापार नीति का विश्लेषण करने के लिए इससे जुड़ी जटिल एवं महंगी गणितीय प्रतिरूपण के मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में म्यांमार के वरिष्ठ अधिकारियों और विद्वानों ने भाग लिया।

आरआईएस के संकाय (फैकल्टीं) के सदस्यों द्वारा बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिए गए व्याख्यान

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- 16 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) द्वारा आयोजित किए गए विदेशी राजनयिकों के लिए 59वें प्रोफेशनल पाठ्यक्रम (पीसीएफडी) में 'डब्ल्यूटीओः कृषि की गुत्थी', विषय पर एक प्रस्तुति दी।
- 20 मई, 2015 को नई दिल्लीः में अंतर्राष्ट्रीय जन संचार संस्थापन (आईआईएमसी) द्वारा आयोजित किए गए भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारतीय आर्थिक कूटनीतिः उत्पत्ति और विकास' पर एक प्रस्तुति दी।
- 21 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए रक्षा एवं सिविल सेवा के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 55वें पाठ्यक्रम में 'विकास सहयोग बनाम विदेशी सहायताः वैश्विक प्रभाव' पर एक प्रस्तुति दी।
- 3 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में आईआईएफटी द्वारा आयोजित किए गए भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षुअधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं बिजनेस प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'भारत के विकास सहयोग' पर एक प्रस्तुति दी।

प्रो. एस.के. मोहंती

- 16 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनेशनल समर स्कूल (आईएसएस) में 'विश्व अर्थव्यवस्था में भारत और चीन : व्यापार एवं निवेश में उभरते रुझान' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

प्रो. राम उपेंद्र दास

- 23 अप्रैल, 2014 को नई दिल्ली में स्थित आर्थिक विकास संस्थान में भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के प्रशिक्षुअधिकारियों, बैच 2014 के स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'भारत की व्यापार नीति' पर एक व्याख्यान दिया।
- 5 अगस्त 2015 को नई दिल्लील में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 'एफटीए पर नए दृष्टिकोण' पर एक विशेष व्याख्यान दिया।
- 10 नवंबर 2015 को हरियाणा में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा 'व्यापार एवं सतत विकास : 'दक्षिणीय और क्षेत्रीय सहयोग' पर आयोजित संगोष्ठी में एक व्याख्यान दिया।

प्रो. टी.सी. जेम्सि

विजिटिंग फेलो

- 25 मई 2015 को फरीदाबाद स्थित एनएसीईएन में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए 'बौद्धिक संपदा अधिकारों पर अमल' के विषय पर आधे दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- 26, 27 और 29 मई, 2015 को नई दिल्ली स्थित आईएसटीएम में नव नियुक्त सीएसएस अधिकारियों को 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' पर व्याख्यान दिए।
- 24 जून, 2015 को कोच्चि स्थित कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कानून के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 'पादप की किस्में और किसानों के अधिकार', 'वस्तुओं के भौगोलिक संकेतों के संरक्षण' और 'आनुवंशिक संसाधन एवं पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति' पर कक्षाएं आयोजित कीं।
- 4 और 5 दिसंबर 2015 को जेडीए में दिल्ली न्यायिक अकादमी (जेडीए) के न्यायिक अधिकारियों के लिए 'बौद्धिक संपदा अधिकार और अमल' पर आयोजित उन्मुाखीकरण कार्यक्रम के दौरान 'आईपीआर न्यायशास्त्र के बारे में कानूनी अवधारणाएं – दायरा और वर्तमान अधिनिर्णय में प्रासंगिकता, आईपीआर कानूनी व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, संवैधानिक अनिवार्यता और विधायी एवं न्यायिक प्रतिक्रियाओं' पर व्याख्यान दिए।
- 18 और 19 दिसंबर 2015 को डीजेए में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) के न्यायिक अधिकारियों के लिए 'सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आईपीआर व्यवस्था पर अमल के समय सोसायटी के अधिकारों और आईपीआर धारक के अधिकारों में संतुलन बैठाने में मजिस्ट्रेवट की भूमिका' पर आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम के सभी सत्रों में अनेक प्रस्तुतियां दीं।
- नई दिल्ली स्थित इंडियन एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में 'भारत के ट्रेड मार्क कानून' पर व्याख्यान दिए।

- 27 दिसंबर 2015 को गाजियाबाद स्थित सीएसआईआर के मानव संसाधन विकास केंद्र में इंजीनियरिंग के एकीकृत एम टेकः पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए आयोजित अनुसंधान उन्मुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'बौद्धिक संपदा अधिकारों' पर व्याख्यान दिए।
- 12 और 13 जनवरी 2016 को आईआईएफटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के विशेष संदर्भ में डब्यूटीओ पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'पेटेंट कानून, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं' और 'भारत में ट्रेड मार्क कानून' पर व्याख्यान दिए।
- 19 और 20 फरवरी 2016 को दिल्ली न्यायिक अकादमी द्वारा आयोजित जिला न्यायाधीशों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 'आईपी संरक्षण की जरूरत, पृष्ठभूमि एवं सामाजिक संदर्भ और इसके अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय आयाम' और 'सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आईपीआर व्यवस्था पर अमल के समय सोसायटी/उपभोक्ता के अधिकारों और आईपीआर धारक के अधिकारों में संतुलन बैठाने में जिला न्यायपालिका की भूमिका' पर अनेक प्रस्तुतियां दीं।

डॉ. सब्यसाची साहा

सहायक प्रोफेसर

- 11 मई, 2015 को नई दिल्ली में भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में 'डब्ल्यूटीओ और भारत' विषय पर दो व्याख्यान दिए।

V

प्रकाशन कार्यक्रम

रिपोर्ट/पुस्तकें

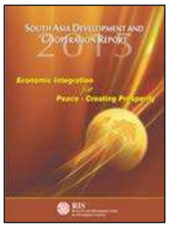

दक्षिण एशिया विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015
आरआईएस, 2015

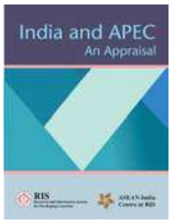

भारत और अपेकः एक मूल्यांकन
वी.एस. शेषाद्री

आरआईएस में एआईसी, 2015

भारत–कोरिया सीईपीएः प्रगति का मूल्यांकन
वी. एस. शेषाद्रि एआईसी–आरआईएस

नई दिल्ली, 2015

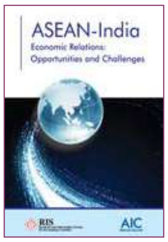

आसियान–भारत आर्थिक संबंध: अवसर और चुनौतियां

थिंक–टैंकों (विचारकों) के आसियान–भारत नेटवर्क (एआईएनटीटी) पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही

एआईसी–आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

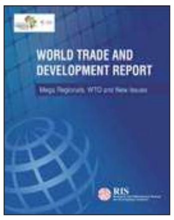

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट

आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

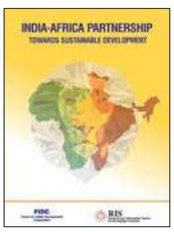

भारत–अफ्रीका की भागीदारी: सतत विकास की ओर

आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

आसियान–भारत विकास और सहयोग रिपोर्ट 2015

एआईसी–आरआईएस, 2015, रूटलेज इंडिया द्वारा प्रकाशित

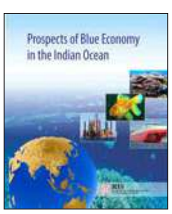

हिंद महासागर में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाएं

2015 एस. के. मोहंती, प्रियदर्शी दास, आस्था गुप्ता, पंखुड़ी गौर, आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

स्वास्थ्य सेवा में भारत–अफ्रीका की भागीदारी: उपलब्धियां और संभावनाएं

टी. सी. जेम्स, प्रतिवा शॉ, पायल चटर्जी, दीप्ति भाटिया, आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

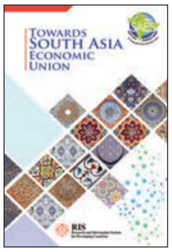

दक्षिण एशिया आर्थिक संघ की ओर

सातवें दक्षिण एशिया आर्थिक शिखर सम्मेलन (एसएईएस) की कार्यवाही

आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

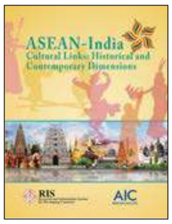

आसियान–भारत सांस्कृतिक संबंधः ऐतिहासिक और समकालीन आयाम

एआईसी–आरआईएस, नई दिल्ली, 2015

जर्नल

साउथ एशिया इकोनॉमिक जर्नल

खंड 16, नंबर 2

खंड 16, नंबर 2 (पूरक मुद्दा)

एशियाई जैव प्रौद्योगिकी और विकास समीक्षा

खंड 17, नंबर 2, जुलाई, 2015

खंड 17, नंबर 3, नवंबर 2015

खंड 18, नंबर 1, मार्च 2016

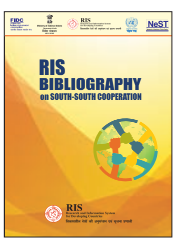

नीति सार

#68: नव विकास बैंकः विकास वित्त में योगदान, मई 2015

#69: पहुंच, प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय आईपीआर नीति, मई 2015

#70: पहुंच, निष्पक्षता और समावेशनः नैतिक मानदंड और एसएंडटी नीतिगत परिणाम, मई 2015

#71: देशों का वर्गीकरण और जी–20, मई 2015

#72: आकस्मिक रिजर्व व्यवस्थाः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली का एक नया स्वरूप, मई 2015

#73: मेक इन इंडियाः भारत में विनिर्माण की स्थिति, सितंबर 2015

#74: समुद्र के भीतर पाइप के सपने और भारत में ऊर्जा सुरक्षा, सितंबर 2015

परिचर्चा प्रपत्र

#196: *अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को नया स्वरूप प्रदान करना: ब्रिक्स पहल* – मनमोहन अग्रवाल

सारः इस प्रपत्र (पेपर) में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और ब्रिक्स देशों के लिए नव विकास बैंक (एनडीबी) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) की स्थापना के निहितार्थ को परखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की वर्तमान संरचना एवं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली (आईएमएस) के स्वरूप और विकासशील देशों के आर्थिक प्रदर्शन एवं जरूरतों को ध्याोन में रखते हुए ही इनकी स्थाणपना की गई है। विकासशील देश विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की गवर्नेंस प्रणाली एवं परिचालन के साथ–साथ इनमें सुधारों को लागू न किए जाने को लेकर असंतुष्ट रहे हैं। सुधारों को लागू करने में इन्हें मिली नाकामयाबी से अंसुष्ट होकर ही विकासशील देश ऐसे नए संस्थानों को तैयार करने के सकारात्मक चरण में प्रवेश कर गए हैं, जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। नई व्यवस्था कायम करने के लिहाज से एनडीबी के लिए काफी गुंजाइश है। न केवल अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, बल्कि परियोजना तैयार करने और कार्यान्वयन में भी एनडीबी ऐसा कमाल दिखा सकता है जो मौजूदा बहुपक्षीय विकास बैंकों को अपने तौर–तरीकों को बदलने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि, आईएमएफ का स्थाकन लेने में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं है। एक नया आईएमएस अस्तित्व में केवल तभी आ सकता है, जब इसका स्व रूप सार्वभौमिक होगा। विकासशील देश चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, उनका समूह किसी नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को विकसित नहीं कर सकता है। सीआरए केवल बीओपी संबंधी वित्त का एक अच्छास नया स्रोत सुलभ करा सकती है।

मुख्य शब्दः ब्रिक्सस, ब्रिक्स पहल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, नया स्वडरूप प्रदान करना

#197: *भारतीय विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देना: विश्वविद्यालय–उद्योग तारतम्यशता (इंटरफेस) का एक सैद्धांतिक मॉडल* – सब्यसाची साहा

सारः वैसे तो एक बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का अभ्यु दय तकनीकी प्रवीणता एवं कौशल पर आधारित गतिशील बढ़त को प्राप्तर करने से ही संभव हो पाया है, लेकिन नवाचार प्रेरित प्रतिस्पर्धा क्षमता हासिल करने को अपेक्षाकृत कम अहमियत मिलती रही है। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं जैसे कि विश्वविद्यालय और संस्थान ऐसे अभिनव अनुसंधानों एवं विचारों को सामने रखेंगे, जिनका वाणिज्यीकरण किया जा सकेगा। इस पेपर में हमने गुणवत्ता, उद्देश्यों और प्रोत्साहनों से जुड़े मुद्दों की तह में जाने के लिए एक रोचक सैद्धांतिक नजरिए से भारत में विश्वविद्यालयों एवं उद्योग जगत के पारस्परिक तालमेल को समझाने की कोशिश की है। वैस तो उद्योग जगत विभिन्न् समस्यायों को सुलझाने के लिए शिक्षाविदों की राय लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों में होने वाले आविष्कारों से लाभ उठाने में उद्योग जगत की बेहद कम दिलचस्पी पर बड़ी सावधानी से मंथन करने की जरूरत है। किसी विश्वविद्यालय में विकसित की गई प्रौद्योगिकी को बाजार में कामयाबी मिलने की संभावना प्रथम दृष्टया बेहद कम रहती है, क्योंयकि इन प्रौद्योगिकियों में कथित रूप से महत्वपूर्ण तकनीकी मूल्य वर्द्धन का अभाव रहता है। नवीनता में इस तरह के अभाव को अक्सर सर्वप्रथम भारतीय विश्वविद्यालयों में किए गए अनुसंधान की अपेक्षाकृत कम जटिलता से जोड़ दिया जाता है। हमारे मॉडल ने यह सूचित किया है कि प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आखिरकार किस तरह से विभिन्न मापदंडों जैसे कि रॉयल्टी शुल्क, रॉयल्टी में वैज्ञानिक की हिस्सेदारी और परामर्श संबंधी राजस्व का इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुख्य शब्दः विश्वविद्यालय–उद्योग इंटरफेस, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार, भारत

#198 *चीनी उत्पादन में इथियोपिया के साथ भारत का विकास सहयोग: एक आकलन* – सुशील कुमार

सारः इथियोपिया भी अफ्रीका के उन कुछ देशों में शामिल है जिनके साथ भारत विकास सहयोग में लंबे समय से भागीदारी करता आ रहा है। वर्ष 2006 में भारत ने इथियोपिया के चीनी उद्योग के विकास के लिए 640 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकतम ऋण सीमा उसे मुहैया कराई थी। इस परिचर्चा प्रपत्र में हमने इथियोपिया के चीनी उद्योग पर भारत की अधिकतम ऋण सीमा (2007–12) के असर का विश्लेषण किया है। हमने पाया है कि अभी जारी परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इथियोपिया प्रति वर्ष 1.6 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप इथियोपिया चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा और वर्ष 2015 के आखिर तक यह देश चीनी का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। हमने यह भी पाया है कि इथियोपिया में चीनी और एथनॉल के उत्पादन से होने वाले आर्थिक लाभ के प्रति वर्ष 961 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। विभिन्न क्षेत्रों के दौरे के आधार पर हमने भारत के प्रयासों के मार्ग में कई व्यावहारिक चुनौतियों का पता लगाया है जिनमें परियोजना की निगरानी और सत्यापन के लिए 'अपर्याप्त' समुचित व्यतवस्थाा भी शामिल है। इससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होती है, सूचनाओं का प्रेषण ठीक ढंग से नहीं होता है और समुचित तालमेल बैठाने में विफलता हाथ लगती है। इथियोपिया के चीनी क्षेत्र में भारत की भागीदारी यह दर्शाती है कि वह इथियोपिया में कृषि वैल्यूल चेन को काफी बढ़ावा दे रहा है और इसके साथ ही रेल पटरियों के निर्माण के लिए दी जा रही कलपुर्जा संबंधी सहायता पोर्ट कनेक्टिविटी और निर्यात को सुविधाजनक बनाने में संभवतरू महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

मुख्य शब्दः स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा, विकास सहयोग, चीनी उद्योग, भारत, इथियोपिया

#199: 'मेक इन साउथ एशिया' की ओर : उभरती क्षेत्रीय वैल्यू चेन
– राम उपेंद्र दास

सारः दक्षिण एशिया में कई आम विकासात्मक चुनौतियों से पार पाने में एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह भी हो सकता है कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चिरिंग) पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नए संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रीय वैल्यू चेन (आरवीसी) सृजित करने के लिहाज से काफी महत्वगपूर्ण बन गया है और इसके साथ ही इसमें विकास के इंजन के रूप में काम करने की असीम संभावनाएं भी हैं। इसे संभव कर दिखाने के उद्देश्य से इस पेपर में सैद्धांतिक परिदृश्य पेश किया गया है जिसमें एक क्षेत्रीय ढांचे के अंतर्गत वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यांपार और निवेश की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर विशेष बल दिया गया है। इस संदर्भ में वस्तु ओं के व्यापार के दायरे में शामिल मूल उत्पावदन स्थयल वाले नियम विनिर्माण के साथ–साथ स्थानीय मूल्य वर्द्धन को भी सुनिश्चित करने और उत्पादन के सभी कारकों में रोजगार सृजन जैसे विकासात्मरक परिणामों को हासिल करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति के साथ–साथ निर्मित उत्पादों के व्यापार के विश्लेषण से प्राप्तक जानकारियों का उपयोग आरवीसी सृजित करने के लिए अनुभवों के आधार पर उत्पाद व देशवार संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इन प्रक्रियाओं से जुड़ी कुछ बाधाओं को दूर करने के उद्देश्यत से इस पेपर में 'मेक इन साउथ एशिया' पहल पर कई नीतिगत सुझाव दिए गए हैं।

मुख शब्दः क्षेत्रीय वैल्यू चेन, दक्षिण एशिया, आर्थिक एकीकरण

#200: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और गरीबी में कमीः क्षेत्रीय संदर्भ में भारत
– मनमोहन अग्रवाल और प्रज्ञा अत्री

सारः इस बात को व्यापक रूप से कहा जाता है कि पूंजी खाते के उदारीकरण से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को काफी लाभ होगा, क्योंकि पूंजीगत नियंत्रण हटते ही पूंजी की बहुतायत वाले धनी देशों से पूंजी की कमी वाले विकासशील देशों की ओर पूंजी का तेज प्रवाह शुरू हो जाएगा। पूंजी के इस मुक्तअ प्रवाह से संभवतः विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी, जिससे करोड़ों लोग गरीबी की दुनिया से बाहर आ जाएंगे। भारत अस्सी के दशक से ही उदारीकरण को धीरे–धीरे अपनाता रहा है और अब तक की इस पूरी अवधि के दौरान यहां से पूंजी की कुल निकासी की तुलना में कहीं ज्यातदा पूंजी का आगमन देश में हुआ है। यही नहीं, अस्सीज के दशक से ही देश में पूंजी प्रवाह का स्व रूप भी बदलता जा रहा है। दरअसल, वर्ष 1991 के बाद देश में पोर्टफोलियो और डेट प्रवाह के मुकाबले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह कहीं ज्योदा तेजी से सतत रूप से बढ़ रहा है। हालांकि, वर्ष 2000 से ही भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी भी देखी जा रही है। इस परिचर्चा प्रपत्र में हमने अनुभवों के आधार पर इस तथ्यन को परखा कि वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2011 तक की अवधि के दौरान भारत में गरीबी पर एफडीआई प्रवाह का क्यो असर पड़ा है। भारत के प्रदर्शन पर एक दृष्टिकोण सुलभ कराने के लिए हमने सार्क देशों में एफडीआई के प्रवाह और गरीबी के बीच की कड़ी का विश्लेषण भी किया है। गरीबी पर एफडीआई प्रवाह से पड़ने वाले असर को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमने निकासी और देश में प्रवाह दोनों का अलग–अलग विश्लेषण किया है। हमने पाया है कि एफडीआई की आवक से भारत में गरीबी बढ़ रही है, जबकि अन्य सार्क देशों में गरीबी काफी कम हो रही है। भारत से एफडीआई की निकासी का असर भी अन्य सार्क देशों की तुलना में ठीक विपरीत रहा है। एफडीआई की निकासी से जहां एक ओर भारत में गरीबी काफी कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर अन्य क्षेत्रीय देशों में इसका अत्यंकत मामूली असर पड़ रहा है।

#201: इब्सा में सामाजिक क्षेत्रों के अनुभवों का साझा करनाः पहलों का आकलन और आगे की राह – *बीना पांडे*

सारः वर्ष 2003 के ब्रासीलिया घोषणा के मद्देनजर औपचारिक रूप से भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका त्रिपक्षीय सहयोग फोरम (इब्सा) की स्थापना इन देशों के बीच दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय विकास पहल है। इब्सा के गठन के बाद से ही इसके सदस्यण देशों में सामाजिक क्षेत्रों की समग्र स्थिति का आकलन करने के लिए समय–समय पर जारी की गई सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित चुनिंदा विज्ञप्तियों और घोषणाओं का विश्लेलषण इस परिचर्चा प्रपत्र में किया गया है। इसके मद्देनजर इस पेपर में इब्सा के प्रत्येक सदस्यो देश में सामाजिक विकास की स्थिति एवं उपलब्धि का आकलन किया गया है और एमडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में गरीबी में कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में हासिल प्रगति का विश्लेषण किया गया है। इस परिचर्चा प्रपत्र में समावेशी विकास के लिए उठाए गए नीतिगत कदमों पर एक अंतर्दृष्टि पेश करने के साथ–साथ त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उनकी गंभीर प्रतिबद्धताओं को ठोस कदमों का रूप प्रदान करने के बारे में विश्लेषण भी किया गया है और आखिर में आगे की राह के लिए सुझाव दिए गए हैं।

मुख्य शब्दः इब्सा, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, एमडीजी, डीबीटी, सीसीटी

#202: भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और पहुंच, समावेशन एवं निष्पीक्षता: परिचर्चाएं, माप और उभरती चुनौतियां

– सचिन चतुर्वेदी, कृष्णा रवि श्रीनिवास और रश्मि रस्तोगी

सार: आर्थिक विकास में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) की अहम भूमिका को सभी जानते हैं। वर्ष 1947 से पहले भारतीय समाज में विज्ञान की भूमिका पर जारी बहस को ध्यान में रखते हुए भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज पर हुई विभिन्न परिचर्चाओं एवं संबंधित वर्णन का खाका तैयार किया गया है और नीतियों पर उनके प्रभावों की चर्चा की गई है। हालांकि, बढ़ती विषमताओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच की पृष्ठभूमि में प्रौद्योगिकी एवं विकास पर जारी बहस ने अब और भी ज्यादा नीतिगत प्रासंगिकता का रूप धारण कर लिया है। इस परिचर्चा प्रपत्र में हमने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) नीति की गहरी समझ एवं इसके मूल्यांकन के मुद्दों पर चर्चा करने और संकेतकों के जरिए पहुंच, निष्पक्षता एवं समावेशन (एईआई) को मापने के लिए गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया है। वैसे तो सिद्धांतों के रूप में एईआई का उपयोग नीतिगत विश्लेषण और एसएंडटी नीतियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मजबूत संकेतकों की आवश्यकता निश्चित रूप से स्पष्ट है। हालांकि, एसएंडटी के प्रभावों के वर्तमान संकेतक या नवाचार संकेतक न तो एईआई को मापते हैं और न ही इन्हें मापने के लिहाज से महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। विकास अर्थशास्त्र में समावेशन एवं विभिन्न सेवाओं से वंचित रखने के तथ्य को मापने और लोगों को हाशिये पर रखे जाने के मामलों का अध्ययन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमने प्रमुख घटक विश्लेषण (पीसीए) का उपयोग करते हुए तीन सूचकांक तैयार किए हैं और हर सूचकांक में भारांक आनुक्रमिक प्रमुख घटकों में हुए फेरबदल को दर्शाते हैं। इस परिचर्चा प्रपत्र में यह सुझाव दिया गया है कि एईआई पर अनुसंधान को एसएंडटी नीति की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि प्रमुख प्रौद्योगिकी पहलों और नीतिगत प्रस्तावों में प्रस्तावित बजटों के 3 से लेकर 5 फीसदी तक के हिस्सेप को इस तरह के अनुसंधान के लिए आवंटित किया जा सकता है। एक अन्य सुझाव यह है कि उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में नए तरीके एवं मॉडल विकसित किए जाएं और एसएंडटी से संबंधित संकेतकों को सामाजिक–आर्थिक संकेतकों से जोड़ दिया जाना चाहिए।

मुख्य शब्द: पहुंच, निष्पक्षता, समावेशन, एसएंडटी संकेतक, एसएंडटी नीति, नवाचार नीति

एसएससी सम्मेलन के लिए विशेष प्रकाशन

शोध पर संक्षिप्त नोट

उभरता दक्षिण: कृत्रिम तथ्य

प्रो. एस. के. मोहंती, डॉ. प्रियदर्शी दास, डॉ. सब्यसाची साहा, डॉ. सुशील कुमार और सुश्री आस्था गुप्ता, आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

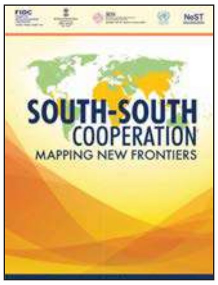

संदर्भ

दक्षिणीय सहयोग: नई सीमाओं का मानचित्रण

आरआईएस, नई दिल्ली, 2016

प्रदर्शकों की शख्सियत (प्रोफाइल)

भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) नीति पर संक्षिप्त नोट

#5 : दक्षिणीय सहयोग और भारतः एफआईडीसी बहु–हितधारक नीति से परखना
#6 : जयपुर में एफआईडीसी क्षेत्रीय परामर्श
#7 : भारतीय विकास सहयोगः एक सैद्धांतिक और संस्थागत रूपरेखा
#8 : विकास सघन – भारत के विकास सहयोग की आधारशिलाः एक 'बाह्य' परिप्रेक्ष्य

आरआईएस डायरी

- खंड 11 नंबर 2, अप्रैल 2015
- खंड 11 नंबर 3, जुलाई 2015
- खंड 11 नंबर 4, अक्टूबर 2015
- खंड 12 नंबर 1, जनवरी 2016

एआईसी न्यूज़लेटर

- खंड 1, नंबर 1, जुलाई 2015

आरआईएस की के सकाय द्वारा बाह्य प्रकाशनों में योगदान

पुस्तकें/रिपोर्ट

चतुर्वेदी, सचिन, और अन्य (कई संपादक). 2015. संस्थागत संरचना और विकासः उभरती शक्तियों की ओर से प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दक्षिण अफ्रीकी संस्थान (एसएआईआईए), दक्षिण अफ्रीका।

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. साझा करने का तर्कः दक्षिणीय सहयोग के प्रति भारतीय दृष्टिकोण । नई दिल्लीः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। आईएसबीएनः 978–1–107–12792–0

दास, राम उपेंद्र. 2015. सीएलएमवी के साथ आर्थिक एकीकरण के लिए भारत की रणनीति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त। आईएसबीएन : 81–7122–109–2

शोध पत्र

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. 'कृषि और स्वास्थ्य में भारतीय सहभागिता को तलाशनाः अंगोला और मोजाम्बिक का एक मामला।' ब्रिक्स नीति केंद्र का प्रपत्र, खंड 3. नं. 03, जनवरी–अप्रैल।

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. 'मजबूत पड़ोसी नीति का रास्ता एक्ट ईस्ट नीति।' एशिया कनेक्ट, अंक नं. 1, जनवरी–मार्च, मकाईअस न्यूजलेटर, कोलकाता।

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. 'परिचयः संस्थागत संरचना और विकासः उभरती शक्तियों की ओर से प्रतिक्रिया', 'भारत के विकास सहयोग की उभरती संस्थागत संरचना' और 'निष्कर्ष, दृष्टिकोण और नीतिगत सिफारिश' सचिन चतुर्वेदी, एलिजाबेथ सिदिरोपाउलस, जॉर्ज ए. पेरेज पिनेदा, और थॉमस फ्यूज (संपादक) : संस्थागत

संरचना और विकासरू उभरती शक्तियों की ओर से प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दक्षिण अफ्रीकी संस्थान (एसएआईआईए), दक्षिण अफ्रीका।

चतुर्वेदी, सचिन. 2015. 'भारत और अफ्रीका की ओर से समान प्रतिबद्धता ही आगे का एकमात्र रास्ता है।' इंडिया एंड अफ्रीका : फोर्जिंग ए स्ट्रे टेजिक पार्टनरशिप पुस्तक, ब्रूकिंग्स इंडिया, अक्टूबर।

चतुर्वेदी, सचिन, के. रवि श्रीनिवास और अमित कुमार. 2015. 'जैव सुरक्षा और जीएमओ का नियमन।' साइंस रिपोर्टर, खंड 52, एम नं. 11, नवंबर, पृ. 22–25.

चतुर्वेदी, सचिन. 2016. 'पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय विकास के मॉडलः दक्षिण एशिया के लिए सबक और आगे की राह।' ओआरएफ, ब्रीफ नं. 134. 8 मार्च। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली।

चतुर्वेदी, सचिन और अन्य. 2016. 'विकास साझेदारी परियोजनाओं में सरकार एवं समुदाय की भागीदारी में संतुलन बैठानाः नेपाल में भारतीय एसडीपी की ओर से उभरते साक्ष्यर।' दक्षिणीय सहयोग पर देश विशेष के मामले से जुड़े अध्ययनों में, विकास प्रभावशीलता के लिए सीएसओ भागीदारीः सहायता की हकीकतः फिलीपींस।

दास, राम उपेंद्र. 2015. 'भारत में व्यापार और निवेश उदारीकरणः उत्पादकता संबंधी लाभ के लिए निहितार्थ', खी जायप टैन और कांग यैम टैन (संपादक) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और लघु एवं मझोले उद्यम : उत्पादकता और वित्त तक पहुंच। सिंगापुरः वर्ल्ड साइंटिफिक। मई।

दास, राम उपेंद्र. 2015. 'दक्षिण एशिया–मध्य एशिया आर्थिक संपर्कों के लिए दलील एवं अवरोध।' यूरेशिया रिव्यू, अल्बानी, ओरेगन। आईएसएसएन 2330–717 एक्स।

दास, राम उपेंद्र और रीना मारवाह. 2015. 'एक वैश्विक संदर्भ में भारत–चीन आर्थिक सहभागिता', यूरेशिया रिव्यू, मई।

दास, राम उपेंद्र. 2015. 'आर्थिक विकास के लिए कूटनीति' योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, जून, आईएसएसएन–0971–8400।

दास, राम उपेंद्र. 2015. 'वैश्विक व्यापार व्यवस्था और उसका संचालनः जी–20 के नियम', एक अभिनव, सुदृढ़, परस्पसर संबद्ध और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था की ओर, टी20 चीन लोकार्पण बैठक, बीजिंग, आईडब्यू ईपी, सीएएसएस, एसआईआईएस, आरडीसीवाई, 14 दिसंबर।

दास, राम उपेंद्र. 2016. 'नैरोबी में डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक और इसका व्यापक दायरा,' द सारसिस्ट, आईएसएसएनः 2455–1775, नई दिल्ली, जनवरी।

डे, प्रबीर. 2015. 'एक्ट ईस्ट नीति और आसियान–भारत कनेक्टिविटी', रुमेल दहिया और उदय भानु सिंह (संपादक) आसियान–भारतः 2015 के बाद के एजेंडे को आकार देना, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), नई दिल्ली, अगस्त।

डे, प्रबीर. 2015. 'क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत बनानाः बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन करार', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 50, नं. 52.

डे, प्रबीर. 2015. 'भारतः एक्ट ईस्ट नीति के तहत कनेक्टिविटी का निर्माण करना', माइकल प्लशमर, पीटर मॉर्गन और गणेशन विग्नारराजा (संपादक) 'एशिया को जोड़ना : दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया को एकीकृत करने के लिए बुनियादी ढांचा। चेलटेनहैम और नॉर्थम्प्टनः एडवर्ड एल्गर।

डे, प्रबीर. 2016. 'भारत की लुक ईस्ट् से लेकर एक्ट ईस्ट् नीति तकः क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इसके क्या मायने हैं', मैगनस सी. एम. ब्रॉड, लियू

डोनक्वीए, नाडजा, एम्मानुएल, फिलिप ग्रिंस्टेड, फ्लोरियन मिब, टॉर्बेन नीमेइयर और एंके स्कॉल्ज (संपादक) में क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के लिए निवेश पहलः समान लाभ–नुकसान वाली स्थिति (जीरो–सम गेम) या सभी के फायदे के लिए गठबंधन?, जर्मन विकास निगम (जीआईजेड), बॉन।

कुमारसामी, दुरईराज एवं कल्लुमरू शिव रेड्डी. 2015. 'बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक आधारित भुगतान और महंगाई में क्या कोई संबंध है? भारत से साक्ष्य।' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्सठ एंड फाइनेंस, खंड 7, नं..9, सितंबर 2015।

VI

आंकडे एवं सूचना केन्द्र

आंकड़े और सूचना केन्द्र विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दुनिया की व्यापारिक प्रणालियों, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली, दक्षेश, आसियन, और आईओआर–एआरसी, जैसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सहित दक्षिण–दक्षिण सहयोग, पूंजी के प्रवाह, एफडीआई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वहनीय विकास जैसे मुद्दों पर पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनों, दूसरे शोध संस्थानों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों के प्रचुर संग्रह के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान के अग्रणी शोध संस्थान के रूप में काम करते हुए संस्था के काम–काज का अविभाज्य अंग रहा है। डेटा और सूचना केंद्र न केवल आरआईएस के शोधकर्ता संकाय को समर्थन प्रदान करता है बल्कि पूरे देश के नीति निर्मांताओं, प्रशासकों, सलाहकारों और छात्रों को भी समर्थन देता है। इस वर्ष से पुस्तकालय स्कूल छात्रों के लिए भी खुला है। अभिलेखन केंद्र की अभिलेख संग्रह नीति आरआईएस के शोध संकाय की आवश्यकताओं से निर्देशित होने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इत्यादि के क्षेत्र में इसे महत्त्वपूर्ण सूचना केंद्र बनाने की व्यापक नीति से संचालित होती है। विषेश संग्रह–सांख्यकीय प्रकाशनों में कृषि सांख्यकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यकी, बजट दस्तावेज़, श्रम सांख्यकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सांख्यकी, व्यापार और विकास सांख्यकी, आर्थिक दृष्टिकोण, एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक, डब्लूटीओ इत्यादि शामिल हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टें शामिल हैं। दस्तावेज़ों में कामकाजी पर्चे, चर्चा पर्चे, पुनर्मुद्रण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसांगिक संगठनों के मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त पर्चे या तो नियमित रूप से पारस्परिक आदान–प्रदान के अंतर्गत प्राप्त होते हैं या संस्थानिक वेबसाइटों से डाउनलोड किए जाते हैं। ग्रंथालय के संग्रह में पंद्रह हज़ार से अधिक पुस्तकें शामिल हैं जिनमें विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, जनसांख्यकी, सांख्यकी, और दूसरे संबंधित विषयों की पुस्तकें हैं। यह इस समय 600 पत्र–पत्रिकाओं की नियमित ग्राहक है। इसके अलावा, इसे 50 से अधिक पत्र–पत्रिकाएं उपहार के रूप में या पारस्परिक आदान–प्रदान के तहत मिलती हैं। यह ग्रंथालय कई राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रकाशनों के आदान–प्रदान करता है।

अभिलेखन केंद्र के ग्रंथालय का संग्रह

- पुस्तकें
- सांख्यकीय वार्षिक संदर्भ पुस्तिकें
- अभिलेख–डब्लूपी–ओपी–डीपी
- पत्र–पत्रिकाएं नियतकालिक (मुद्रित+ऑनलाइन+सीडी–रोम)
- अख़बार–भारतीय + अंतरराष्ट्रीय
- पिछले अंक
- सीडी रोम
- सीडी–रोम में डेटाबेस

आरआईएस का डेटाबेस

डेटा बैंक के पास अच्छी तरह से अनुरक्षित डेटाबेस हैं। हमारे पास घरेलू अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहित व्यापर, निवेश, रोज़गार, पर्यावरण और उद्योगों के डेटाबेस हैं। अपनी परियोजनाओं के लिए डेटाबेस की उपयोगिता के मद्देनज़र इसे नियमित रूप से नवीन बनाई रखा जाता है।

वैश्विक डेटाबेसः

- व्यापारिक डेटाबेस, टैरिफ़ और नॉन टैरिफ़ उपाय
- देय भुगतान
- वित्त सांख्यकी
- विकास सांख्यकी
- औद्योगिक सांख्यकी
- बौद्धिक संपदा सेवाएं, नीति, सूचना और वित्तीय निष्पादन

भारतीय डेटाबेसः

- 8 दृडिजिटल स्तरों पर व्यापार पर टाइम सिरीज़ के डेटाबेस
- भारतीय कंपनियों के डेटाबेस और उनके वित्तीय निष्पादन
- सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस
- सीमा शुल्क का डेटाबेस

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन अभिलेखन केंद्र

आरआईएस के प्रकाशनों और उसके आयोजनों के अलावा वेबसाइट को वास्तविक समय के आधार पर नवीनतम किया जाता है। शोध रिपोर्टों, नीति सारों, चर्चा पत्रों, सम्मेलन की रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना पत्रों और समाचार पत्रों में आरआईएस के संकाय सदस्यों के लेखों जैसे सारे विवरण मुक्त रूप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। शोध सामग्रियों को ट्विटर, फ़ेसबुक, और लिंक्डइन जैसी प्रमुख लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइटों के माध्यम से साझा की जा सकती हैं। हिट्स की संख्या में वृद्धि के

साथ आरआईएस की साइटों की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ रही है। आरआईएस की वेबसाइट हमेशा गूगल द्वारा समर्थित तलाश परिणामों में सबसे ऊपर दिखाई देती है, जिसका आशय यह है कि वेबसाइट की दृश्यता सबसे अच्छी होती है। इस वेबसाइट की समाग्री को दुनिया भर में ग्राहक के अनुकूल बनाने के लिए आरआईएस की वेब साइट के पास भाषा अनुवाद है।

आरआईएस यूट्यूब चैनल

आरआईएस पास यूट्यूब चैनल जिसमें टीवी पर आरआईएस का कवरेज और आरआईएस के प्रमुख हालिया आयोजन शामिल हैं।

आरआईएस फैसबुक और ट्विटर पर

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है। फेसबुक एकाउंट https://www.facebook.com/RISIndia और ट्विटर हैन्डल @RIS_NewDelhi है।

VII

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, पीएचडी
महानिदेशक
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ. एस के मोहंती
प्रोफेसर
विशेषज्ञताः वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ. राम उपेन्द्र दास
प्रोफेसर
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय एकीकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर/समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

डॉ. बीना पाण्डेय
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. साब्यासाची साहा
सहायक प्रोफेसर
विशेषज्ञता: प्रौद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ. प्रियदर्शी दास
अनुसंधान एसोसिएट
विशेषज्ञता: समष्टि अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ. अमित कुमार
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता–नवप्रवर्तन, दूरदर्षिता एवं नियंत्रण

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता: वैश्विक व्यापार

श्री इमदादुल इस्लाम हाल्दर
अनुसंधान सहायक
विशेषज्ञता–राजनीति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

श्री सुनंदो बासू, एम फिल
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता–व्यावहारिक अर्थमित्तीय, विधि एवं अर्थशास्त्र तथा विकास
(9 सितंबर 2015 तक)

सलाहकार/विजिटिंग फैलो

प्रो. टी सी जेम्स
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता: विकास अर्थव्यवस्था, परिवेक्षण एवम परिणाम निर्धारण

डॉ. टी.पी. राजेंद्रन
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर) कानून एवं संबद्ध नीति

डॉ. के रवि श्रीनिवास
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञता : बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

प्रो. संदीप सिंह परमार
(20 जुलाई 2016 तक)
सलाहकार

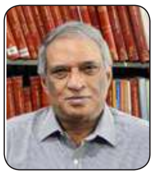

प्रो. चंद्रा मोहन
(17 दिसंबर 2015 तक)
विजिटिंग फैलो
विशेषज्ञताः अर्थशास्त्र एवं व्यवसाय टिप्पणीकार

डॉ. सुशील कुमार
सलाहकार
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. दूराईराज कुमारास्वामी
सलाहकार
विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार, एवं विदेश निवेश एवं व्यवहारिक अर्थमित्ति

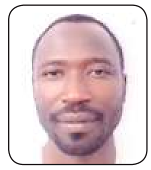

श्री सेडू एन. सुलईमन मनिम
सलाहकार
विशेषज्ञताः उद्यम एवं नवाचार

सुश्री अदिति गुप्ता
(31 मार्च 2016 तक)
सलाहकार
विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं माइक्रो–इकनॉमिक

श्री जय देव दूबे
(14 अप्रेल 2015 तक)
विशेषज्ञता : अर्थशास्त्र, माइक्रो–इकनॉमिक एवं एप्लाइड मैक्रो–इकनॉमिक्स

सुश्री रश्मि सिंह
(6 अक्टूबर 2015 तक)
सलाहकार

अनुसंधान सहायक

सुश्री आस्था गुप्ता

श्री प्रत्यूष

सुश्री दीप्ती भाटिया

सुश्री प्रतीवा सॉव

सुश्री ओपिंदर कोर

श्री दिव्य प्रकाश

सुश्री अंकिता गर्ग

अनुसंधान सहायक

सुश्री श्रेया मल्होत्रा
(14 जून 2016 तक)

सुश्री पंखुड़ी गौर
(14 जून 2016 तक)

सुश्री कशिका अरोड़ा
(15 जूलाई 2016 तक)

सुश्री नित्या बत्रा
(30 अप्रैल 2016 तक)

सुश्री हरप्रीत कोर
(30 अप्रैल 2016 तक)

सुश्री आकांक्षा बत्रा
(21 मार्च 2016 तक)

सुश्री भावना सेठ
(5 फरवरी 2016 तक)

श्री वैभव कौशिक
(30 जनवरी 2016 तक)

सुश्री पालय चटर्जी
(30 नवंबर 2015 तक)

सुश्री वेदांता धमिजा
(8 नवंबर 2015 तक)

सुश्री सुरभि अग्रवाल
(30 सितंबर 2015 तक)

सुश्री वृंदा सेकसरिया
(23 अगस्त 2015 तक)

श्री मनमीत सिंह अजमानी
(14 अगस्त 2015 तक)

सुश्री श्रुति शर्मा
(3 जुलाई 2015 तक)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

डॉ. मनमोहन अग्रवाल

डॉ. अमृता नरलिकर
अध्यक्ष, वैश्विक और क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जर्मन संस्थान (GIGA), हैम्बर्ग, जर्मनी हैम्बर्ग, हैम्बर्ग, जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्राध्यापकीय चेयर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पोलिस, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रीडर, डार्विन कॉलेज, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए वरिष्ठ रिसर्च एसोसिएट, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय

प्रो. मुकुल अशर
प्रोफेसर, ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगाफर

डॉ. बालाकृष्णा पिसुपति
पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, भारत सरकार

सहायक अध्येता

डॉ. केविन पी गालाघेर,
प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ. रामकिशन एस राजन
एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जार्ज मैसॉन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डी.सी.

डॉ. सूमा अथरयी
रीडर, ब्रूनल बिज़नेस स्कूल, ब्रूनल यूनिवर्सिटी, अक्सब्रिज

डॉ. श्रीविद्या रागवन
एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, कॉलेज ऑफ लॉ, नॉरमन, ओक्लाहोमा

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सीं अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

महानिदेशक कार्यालय

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव
श्रीमती रिंतु परनामी, निजी सहायक
श्री सचिन कुमार, सचिवीय सहायक

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक
(वेब और डिजाइन)
सुश्री रुचि वर्मा, प्रकाशन सहायक

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्री सुधीर राणा, पुस्तकालय सहायक

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, कम्प्यूटर सहायक
श्री सत्यपाल सिंह रावत, उवर डिवीजन कलर्क
श्रीमती गीतिका शर्मा, डाटा एट्री आपॅरेटर
श्री राहुल भारती, वेब डिजाइनर

वित्त एवं प्रशासन

श्री वी कृष्णामणि, उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा)
श्री डी पी काला, उपनिदेशक (प्रशासन एवं स्थापना
श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभागअधिकारी(लेखा)
श्री हरकेश, सहायक
श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार
श्री अनिल गुप्ता, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं
श्रीमती शालिनी शर्मा, अवर श्रेणी लिपिकं/स्वागती

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्री अलोक कुमार, सचिवीय सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान, दफ्तरी
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी

VIII

वित्तीय विवरण

सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटैंट्स

8, सेकेंड फ्लोर, कृष्णा मार्केट, कालका जी, नई दिल्ली–110019

टेलीफोन : 32500444, टेलीफैक्सः 40590344, ई–मेलः skacamail@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की आम सभा के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी रिसर्च एंड इंफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज (आरआईएस) के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2016 की तारीख तक की बैलेंसशीट, समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते तथा रसीद और भुगतान खाते एवं उल्लेखनीय लेखात्मक नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का एक सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरादायित्व

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जबावदेह है जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और सोसाइटी की रसीद और भुगतान का एक सच्चा और निष्पक्ष खाका प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण डिजायन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है जो एक सच्चा एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त है जो चाहे ध ोखाधड़ी से हो या गलती की वजह से हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की है। हमने अपने लेखा परीक्षण का संचालन भारतीय लेखापाल (चार्टर्ड अकाउंटैंट) संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं एवं योजना का अनुपालन करें और इस विवेकपूर्ण आश्वासन को प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है।

एक लेखा परीक्षण वित्तीय विवरणों में राशियों एवं खुलासों के बारे में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने से जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित है। चुनी गई प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या गलती की वजह से हो, के आकलन समेत लेखापाल के निर्णय पर निर्भर करती हैं। वैसे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षकों को सोसाइटी के वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पर विचार करना चाहिए जिससे कि ऐसी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों लेकिन सोसाइटी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर विचार व्यक्त करने के उद्वेश्य के लिए न हो।

एक लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारे लेखा परीक्षण विचार के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं विचार

हम घोषणा करते हैं कि :

i) हमने उन सभी सूचनाओं एवं व्याख्याओं की खोज की है एवं उन्हें प्राप्त किया है जोकि हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;

ii) हमारे विचार से सोसाइटी ने कानूनी रूप से आवश्यक उपयुक्त लेखा बही रखा है, जैसाकि बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

iii) इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और रसीद तथा भुगतान खाता से संबंधित जो कार्य किया गया है, वह बही खातों के अनुरूप है।

iv) हमारे विचार से इस रिपोर्ट द्वारा बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता और रसीद तथा भुगतान खाता से संबंधित जो कार्य किया गया है, वह भारतीय लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा परीक्षण मानकों के अनुरूप है;

v) हमारे विचार से और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और जो व्याख्याएं हमें दी गई हैं, उसके अनुसार उपरोक्त विवरण सामान्य रूप से भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धातों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करते हैंः

क) 31 मार्च, 2016 तक सोसाइटी की स्थिति से जुड़े बैलेंस शीट क्े मामलों में;

ख) उस तारीख को समाप्त वित वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय खाते के मामले में; और

ग) उस तारीख को समाप्त वित वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के मामले में।

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएटस्
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 008714C

ह.
(कृष्णा कुमार सिंह)
साझेदार, सदस्य सं. 077494

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी)

31 मार्च, 2016 तक तुलन पत्र

राशि रु. में

	अनुसूची	31–मार्च 2016 तक	31–मार्च 2015 तक
उत्तरादायित्व			
अनुसंधान एवं विकास फंड	1	92,418,034.41	92,643,533.70
स्थायी परिसंपत्ति फंड (गैर–एफसीआरए)	2	27,176,848.20	23,942,160.00
परिसंपत्ति फंड (एफसीआरए)		195,808.00	230,362.00
प्रायोजित परियोजनाओं का अव्ययित फंड (गैर–एफसीआरए)	3	4,510,582.97	9,447,691.00
प्रायोजित परियोजनाओं का अव्ययित फंड (एफसीआरए)		5,336,948.56	8,484,119.00
वर्तमान उत्तरादायित्व एवं व्यवस्थापन (प्रोविजन) (गैर–एफसीआरए)	4	40,875,987.38	35,395,171.00
वर्तमान उत्तरादायित्व एवं व्यवस्थापन (प्रोविजन) (एफसीआरए)		152,558,00	210,061.00
कुल		**170,666,767.52**	**170,353,097.70**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां (गैर–एफसीआरए)	5	27,176,848.20	23,942,160.00
स्थायी परिसंपत्तियां (एफसीआरए)		6,300,254.00	7,275,067.00
प्रायोजित परियोजनाओं से वसूल होने योग्य राशि (गैर–एफसीआरए)	3	27,680,987.92	13,097,790.00
प्रायोजित परियोजनाओं से वसूल होने योग्य राशि (एफसीआरए)		4,193,319.00	1ए122ए702ण00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि (गैर–एफसीआरए)	6	41,161,692.55	62,110,210.91
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि (एफसीआरए)		64,153,665.85	62,805,167.79
कुल		**170,666,767.52**	**170,353,097.70**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 15

अनुसूची 1 से 15 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714सी

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
एम सं. 077494
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29/09/2016

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

	अनुसूची	31–मार्च 2016 तक	31–मार्च 2015 तक
आय			
विदेश मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान राशि	4अ	52,715,708.00	48,432,521.00
प्रायोजित परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए अंतरित अनुदान की राशि (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	3	51,625,820.20	39,672,955.00
कार्यक्रम संबंधी व्यय के लिए प्रायोजित परियोजनाओं कि अंतरित अनुदान राशि (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	3	1,483,999.07	812,848.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय (गैर–एफसीआरए)		97,413.00	110,507.00
अर्जित आय			
आवधिक जमा पर (एफसीआरए)		5,386,779.37	5,214,042.46
आवधिक जमा पर (गैर–एफसीआरए)		2,355,234.60	3,533,963.17
बचत खातों/ऑटो स्वीप खाते पर (एफसीआरए)		122,938.00	198,415.16
बचत खातों/ऑटो स्वीप खाते पर (गैर–एफसीआरए)		722,938.00	312,073.27
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर (गैर–एफसीआरए)		19,943.00	13,043.00
अन्य विविध आय (गैर–एफसीआरए)		2,999.92	312,073.00
प्रायोजित परियोजनाओं से उपरिव्ययों की वसूली (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)		1,842,243.45	610,481.00
पूर्व अवधि आय		138,090.00	21,000.00
अचल आस्तियों की निधि सहस्तांतरित की गयी धनराशि – बची गयी/समाप्त की गई परिसंपत्तियां की डब्ल्यू.डी.वी. (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	2	59,805.00	431,208.00
अचल परिसंपत्तियों स हस्तांतरित धनराशि – भारत सरकार स सहायता अनुदान स हासिल की गयी अचल परिसंपत्तियां/प्रायोजित परियोजनाओं पर जमा (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	2	2,578,323.80	2,114,180.00
घाटा अनुसंधान और विकास निधि को हंस्तांतरित		225,499.29	–
कुल		**129,377,527.79**	**101,509,021.06**
व्यय			
कार्यक्रम संबंधी व्यय– प्रायोजित परियोजनाएँ (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	7	61,625,820.29	39,672,955.00
प्रतिष्ठान के व्यय (गैर–एफसीआरए)	8	42,537,858.00	41,580,210.00
प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य व्यय (गैर–एफसीआरए)	9	21,622,160.76	15,582,464.20
प्रशासनिक एवं कार्यक्रम के अन्य व्यय (एफसीआरए)	10	898.94	192,789.00
अचल संपत्ति का मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	5	3,518,582.80	3,205,145.00
घाटा राशि प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर स्थानातरित (गैर–एफसीआरए एवं एफसीआरए)	3	10,371.00	645,900.00
अवधि पूर्व व्यय		21,836.00	256,447.00
अधिशेष अनुसंधान और विकास निधि को हंस्तांतरित		–	373,110.86
कुल		**129,377,527.79**	**101,509,021.06**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 15
अनुसूची 1 से 15 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714सी
ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदार
एम सं. 077494
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29/09/2016

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान

(मूल्य रु. में)

	रशीदें	वर्ष समाप्त 31-मार्च-16		वर्ष समाप्त 31-मार्च-15	
क.	**बकाया शेष**				
i)	हाथ में रोकड़ (गैर–एफसीआरए)	30,987.00		16,296.00	
ii)	बैंक में बकाया रकम				
	बचत खातों में – आंध्रा बैंक	87,412.00		14,585.00	
	बचत खातों/ऑटो स्वीप-ऑफ इंडिया (गैर–एफसीआरए)	24,103,735.28		8,845,428.90	
	बचत खातों/ऑटो स्वीप-ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	2,829,948.96		4,273,434.40	
	सावधि जमाओं में बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	54,475,828.13		53,486,085.00	
	सावधि जमाओं में बैंक ऑफ इंडिया (गैर–एफसीआरए)	30,047,127.45		44,822,121.50	
iii)	डाक शुल्क के टिकट – फ्रैंकिंग मशीन में बकाया (गैर–एफसीआरए)	156,248.00		144,493.00	
	कुल क.		**111,731,286.82**		**111,602,443.80**
ख.	**प्राप्त अनुदान**				
i)	भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास से	58,500,000.00		52,800,000.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के पास से (गैर–एफसीआरए)	34,009,427.97		23,288,760.00	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के पास से (एफसीआरए)	3,926,539.00		9,882,929.00	
	कुल ख.		**96,435,966.97**		**85,971,689.00**
ग.	प्राप्त किया गया ब्याज				
i)	ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज (गैर–एफसीआरए)	19,943.00		13,428.00	
ii)	बचत बैंक खाते/ऑटो स्वीप पर ब्याज(एफसीआरए)	137,810.00		183,336.16	
iii)	सावधि जमा खाते पर ब्याज (गैर–एफसीआरए)	6,469,662.02		3,196,548.26	
iv)	सावधि जमा खाते पर ब्याज (एफसीआरए)	7,183,438.59		4,545,779.53	
v)	बचत बैंक खाते/ऑटो स्वीप पर ब्याज (गैर–एफसीआरए)	719,039.00		292,231.27	
vi)	बचत बैंक खाते पर ब्याज–आंध्रा बैंक (गैर–एफसीआरए)	3,899.00		3,080.00	
	कुल **ग.**		**14,533,791.61**		**8,234,403.22**
घ.	**अन्य आय**				

	भुगतान	वर्ष समाप्त 31-मार्च-16		वर्ष समाप्त 31-मार्च-15	
क.	**व्यय (गैर–एफसीआरए)**				
i)	स्थापना संबंधी व्यय (अनुसूची - 11)	41,225,641.00		36,564,081.00	-
ii)	प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी अन्य व्यय (अनुसूची - 12)	20,948,767.38		13,079,802.20	-
iii)	कार्यक्रम के खर्च – प्रायोजित परियोजना (अनुसूची - 14)	46,802,712.47		22,055,975.00	
iv)	पूर्व अवधि व्यय	21,836.00		256,447.00	
	कुल क.		**108,998,956.85**		**71,956,305.20**
ख.	**व्यय (एफसीआरए)**				
i)	प्रशासनिक एवं कार्यक्रम संबंधी व्यय (अनुसूची - 13)	898.94		555.00	
ii)	कार्यक्रम के खर्च – प्रायोजित परियोजना (अनुसूची - 14)	9,000,881.37		9,442,684.00	
	कुल ख.		**9,001,780.31**		**9,443,239.00**
ग.	**अचल संपतियों के लिए भुगतान**				
i)	अचल संपतियों के लिए भुगतान (गैर–एफसीआरए)	6,745,953.00		3,485,752.00	
ii)	अचल संपतियों के लिए भुगतान (एफसीआरए)	-		5,327,407.00	
	कुल ग.		**6,745,953.00**		**8,813,159.00**
घ.	**अग्रिम और जमा**				
i)	अग्रिम (गैर–एफसीआरए)	155,179.00		464,396.00	
ii)	अग्रिम (एफसीआरए)	2,157.00		719.00	
iii)	प्राप्त होने योग्य टीडीएस (गैर–एफसीआरए)	401,079.00		328,229.00	
iv)	प्रतिभुती जमा (गैर–एफसीआरए)			3,500.00	
	कुल घ.		**558,415.00**		**796,844.00**
ड.	**अन्य**				
i)	वापस लौटाया गया अनुदान (गैर–एफसीआरए)	520,641.00		2,845,627.00	
ii)	वापस लौटाया गया अनुदान (एफसीआरए)	-		560,740.00	
iii)	आयकर भुगतान	1,543,443.00		-	
	कुल ड.		**2,064,084.00**		**3,406,367.00**
च.	**जमा शेष**				
i)	हाथ में रोकड़ (गैर–एफसीआरए)	19,891.00		30,987.00	
ii)	बैक शेष :				
	बचत बैंक खाते पर ब्याज–आंध्रा बैंक (गैर–एफसीआरए)	101,741.00		87,412.00	
	बचत बैंक खाते/ऑटो स्वीप पर बैंक ऑफ इंडिया (गैर–एफसीआरए)	5,271,972.20	24,103,735.28		

(मूल्य रु. में)

	रशीदें	वर्ष समाप्त 31-मार्च-16		वर्ष समाप्त 31-मार्च-15			भुगतान	वर्ष समाप्त 31-मार्च-16		वर्ष समाप्त 31-मार्च-15	
i)	प्रकाशन बिक्री(गैर–एफसीआरए)	8,500.00		9,210.00			बचत बैंक खाते/ऑटो स्वीप पर	821,227.82		2,829,948.96	
ii)	रॉयल्टी(गैर–एफसीआरए)	108,395.00		93,372.00			बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)				
iii)	फुटकर आय (गैर–एफसीआरए)	2,999.92		31,787.00			बैंक ऑफ इंडिया मे सावधि जमा (एफसीआरए)	59,642,628.55		54,475,828.13	
	कुल घ.		**119,894.92**		**134,369.00**		बैंक ऑफ इंडिया मे सावधि जमा (गैर–एफसीआरए)	31,846,957.59		30,047,127.45	
ड़	**अग्रिम और जमा**										
i)	ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)	226,746.00		27,620.00		iii)	डाक शुल्क के टिकट – फ्रेंकिंग मशीन में बकाया (गैर–एफसीआरए)	99,432.00		156,248.00	
ii)	कर्मचारियों से वसूले गए अग्रिम (गैर–एफसीआरए)	282,715.00		47,390.00			**कुल च.**		**97,803,850.16**		**111,731,286.82**
iii)	ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए)	-		15,147.00							
iv)	पुराने चेक (गैर–एफसीआरए)	24,355.00		78,527.00							
v)	अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि (गैर–एफसीआरए)	273,240.00		1,799.00							
	कुल ड़.		807,056.00		170,483.00						
च.	**अन्य**										
i)	स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री	1,600.00		33,813.00							
ii)	प्राप्त किया गया सेवा कर	1,543,443.00		-							
	कुल च.		**1,545,043.00**		**33,813.00**						
	कुल		**225,173,039.32**		**206,147,201.02**		**Total**		**225,173,039.32**		**206,147,201.02**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 15
अनुसूची 1 से 15 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न
कृते सिंह कृष्णा एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटैंट्स
कंपनी की रजिस्ट्रेशन संख्या 008714सी

ह./–
(कृष्ण कुमार सिंह)
साझेदारनिदेशक (वित्त एवं प्रशासन)
एम सं. 077494
स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 29/09/2016

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

ह./–
महेश सी. अरोड़ा
महानिदेशक

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी

आरआईएस विकासशील देशों का शोध संस्थान

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इसकी वेबसाइट wwww.ris.org.in देखें।

अंतर्राष्टीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4-बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003, भारत
दूरभाष: 91-11-24682177-80 फैक्स: 91-11-24682173-74
ई-मेल: dgoffice@ris.orgin वेबसाइट: http://www.ris.org.in